सूर्योदय 6.20 सूर्यास्त 5:57

आज का तापमान

शिमला	14.0 न्यू	23.0 अधि
धर्मशाला	17.5 न्यू	25.0 अधि

बाजार

सेंसेक्स	71,593.24
निफ्टी	22,231.80

सोना 1,47,463 चांदी 2,18,045

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2026 | 23 अश्विन, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 165, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

2026 का साहित्य नोबेल कनाडाई लेखिका ऐन कार्सन को मिला

एजेंसी, स्टॉकहोम। कनाडा की लेखिका ऐन कार्सन को 2026 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल समिति ने उन्हें



यह सम्मान उनकी ऐसी रचनाओं के लिए दिया है, जिनमें उन्होंने पुराने ग्रीक-रोमन साहित्य और परंपराओं को नए तरीके से पेश किया है। उन्होंने साहित्य लिखने के नए तरीके भी विकसित किए हैं। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं को दिसंबर में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सम्मानित किया जाएगा। उन्हें मेडल, डिप्लोमा और पुरस्कार राशि दी जाएगी। पुरस्कार राशि 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। पिछले 10 साल में साहित्य का नोबेल 10 लेखकों को मिला, जिनमें 4 महिलाएं थीं। इनमें 6 ने अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषाओं में लिखा, जबकि 6 विजेता यूरोप से रहे।

इटली में चुनाव जीतने पर एक्स्ट्रा सीटों पर विवाद

एजेंसी, रोम। इटली में चुनाव जीतने वाली पार्टी या गठबंधन को संसद में एक्स्ट्रा सीटें देने के प्रस्ताव पर विवाद छिड़ गया है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार यह कानून लाना चाहती है। इसके तहत चुनाव में जीतने वाली पार्टी या गठबंधन को संसद में 105 अतिरिक्त सीटें मिल सकती हैं। हालांकि, इसके लिए उसे दोनों सदनों में कम से कम 42% वोट हासिल करने होंगे। सरकार का कहना है कि इससे देश में राजनीतिक स्थिरता आएगी और सरकारें बार-बार नहीं गिरेंगी। वहीं, विरोधियों का आरोप है कि इस कानून से चुनाव जीतने वाले गठबंधन को जरूरत से ज्यादा ताकत मिल जाएगी। इस कानून पर आज संसद में वोटिंग होनी है।

कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती, मरीजों पर कम होगा आर्थिक बोझ

एजेंसी, नई दिल्ली। सरकार ने कुछ कैंसर रोधी दवाओं पर दुकानदारों और वितरकों के मुनाफे की सीमा तय करने का फैसला किया है। अब इन दवाओं पर ट्रेड मार्जिन अधिकतम 30 प्रतिशत तक ही रखा जा सकेगा। यह नियम ब्रांडेड और जेनेरिक, देश में बनी और विदेश से आयातित दवाओं पर लागू होगा। सूत्रों के अनुसार इस फैसले से कुछ कैंसर की दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत यानी एमआरपी में 70 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से कैंसर मरीजों और उनके परिवारों को इलाज के खर्च में बड़ी राहत मिलेगी।

सऊदी एयरपोर्ट पर हूतियों का हमला, तीन की मौत

एजेंसी, रियाद। सऊदी अरब के दो एयरपोर्ट्स पर हूती विद्रोहियों ने ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही 36 लोग घायल हुए हैं। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने बुधवार को यह जानकारी दी। आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 6 और 7 अक्टूबर को निशाना बनाया गया। हूती विद्रोहियों ने दोनों हमलों की जिम्मेदारी ली है। वहीं, यमन में सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसने हूतियों के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की है।

नाना पाटेकर का कार्डियक अरेस्ट से 75 वर्ष की आयु में निधन

गोवा में ली अंतिम सांस, 4 दिन पहले कहा था- हम सभी को एक दिन जाना है, मुझे नहीं पता कि मैं कल रहूंगा या नहीं

एजेंसी, पणजी



भारतीय सिनेमा के वरिष्ठ और मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का वीरवार सुबह 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें गोवा स्थित घर में कार्डियक अरेस्ट हुआ था। उन्हें करीब 45 मिनट तक सीपीआर दी गई, लेकिन बचाया नहीं जा सका। अंतिम संस्कार पुणे के फॉर्महाउस में हुआ। मणिपाल हॉस्पिटल के डॉ. शेखर सालकर के मुताबिक नाना पाटेकर का सुबह 5:20 बजे निधन हुआ। घटना के वक्त नाना के साथ घर पर परिवार का कोई सदस्य नहीं था। उनके दोस्त और केयरटेकर मौजूद थे। नाना पाटेकर का 4 दिन पुराना आखिरी वीडियो सामने आया है। इसमें नाना पाटेकर ड्रम बजाते, डांस करते और मस्ती करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा था, 'हम सभी को एक दिन जाना है। पता नहीं मैं कल यहां रहूंगा या नहीं।' नाना पाटेकर की सामाजिक संस्था नाम फाउंडेशन के सीईओ गणेश थोरात ने बताया कि एक्टर का पार्थिव शरीर शाम 5 बजे तक फार्महाउस पहुंच सकता है। यहां अंतिम दर्शन की भी व्यवस्था की जाएगी।

नाना हिंदी और मराठी सिनेमा के चर्चित अभिनेता हैं। उनका जन्म एक जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड-जंजीरा में हुआ था। वह सिर्फ अभिनेता ही नहीं, बल्कि फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक भी रहे। नाना पाटेकर के अभिनय का आगाज 1978 की फिल्म गमन से हुआ। शुरुआती दौर में उन्होंने मराठी और हिंदी सिनेमा दोनों में अपना हुनर दिखाया।

संघर्षों से सफलता तक का सफर

1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुड-जंजीरा में जन्मे नाना पाटेकर ने अभिनय के क्षेत्र में अपनी अलग और बेहद प्रभावशाली पहचान बनाई। वे अभिनेता होने के साथ-साथ लेखक, निर्देशक और समाजसेवी के रूप में भी सक्रिय रहे। नाना पाटेकर का जन्म एक मराठी परिवार में हुआ। उनके पिता गजानन (दिनकर) पाटेकर टेक्सटाइल पेंटर और व्यवसायी थे, जबकि मां निर्मला पाटेकर गृहिणी थीं। नाना पाटेकर ने फिल्मों से पहले रंगमंच पर अपनी पहचान बनाई। थियेटर में लंबे समय तक काम करने के बाद उन्हें फिल्मों में आने का मौका मिला। वर्ष 1978 की फिल्म 'गमन' से उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। इस फिल्म में उनके साथ स्मिता पाटिल भी थीं। नाना के अनुसार, फिल्मों में आने के लिए स्मिता पाटिल ने भी उन्हें प्रोत्साहित किया था। इसके बाद उन्होंने 'सलाम बॉम्बे!' जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि उन्हें वास्तविक पहचान 1989 की फिल्म 'परिंदा' से मिली। फिल्म में उनके खतरनाक और प्रभावशाली अभिनय ने दर्शकों और समीक्षकों दोनों का ध्यान खींचा। इस भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

ये पुरस्कार जीते

नाना पाटेकर उन चुनिंदा अभिनेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने अभिनय के लिए तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। 1990 में 'परिंदा' के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इसके बाद 1995 में 'क्रांतिवीर' के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। 'क्रांतिवीर' में प्रताप नारायण तिलक का उनका किरदार आज भी हिंदी सिनेमा के यादगार पात्रों में गिना जाता है। 1997 में 'अग्निसाक्षी' के लिए नाना को एक बार फिर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इस तरह उन्होंने अभिनय की तीन अलग-अलग भूमिकाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित की।

बिजनेसमैन स्टारलिंक को रोक रहे, यह बात गलत : केंद्र सरकार



एजेंसी, नई दिल्ली। भारत सरकार ने एलन मस्क के उन आरोपों को खारिज कर दिया है, जिनमें उन्होंने दावा किया था कि कुछ भारतीय उद्योगपति एकाधिकार बनाए रखने के लिए स्टारलिंक को भारत नहीं आने दे रहे। सरकार ने 8 अक्तूबर को कहा कि देश में सैटेलाइट कम्यूनिकेशन सर्विसेज के लिए तय नियम सभी के लिए एक जैसे हैं। यह कहना बिलकुल गलत है कि नियमों को किसी के साथ भेदभाव करने के लिए लागू किया जा रहा है।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन

राहुल-प्रियंका ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी; खड़गे बोले- सरकार वोट देने का अधिकार छीन रही

एजेंसी, नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर के विरोध में विपक्ष ने वीरवार को देशभर में प्रदर्शन किया। पटना में प्रदर्शन के दौरान बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बैरिकेड पर चढ़ गए। वहीं, लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ता हाथ में हथकड़ी लगाकर पहुंचे। वहीं, एक प्रदर्शनकारी सर पर घड़ा लेकर पहुंचा जिस पर लिखा था 'ज्ञानेश कुमार के पाप का घड़ा'।

दिल्ली में भी वीरवार को लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन किया राहुल-प्रियंका गांधी और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने पहले कनॉट प्लेस में लंच किया, फिर बसों से



राजघाट पहुंचे। प्रदर्शन को देखते हुए भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। राजघाट पर करीब एक घंटे इंतजार के बाद उन्हें अंदर जाने दिया। यहां सांसदों ने बापू को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले खड़गे ने कहा था कि वे गांधीजी से प्रार्थना करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि दे। वह लोगों का वोट देने का अधिकार न छीने। दिल्ली में पिछले दो दिनों से धरने का एक ही पैटर्न दिखा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे विपक्षी सांसदों को लंच पर बुलाते हैं, सांसद खाना खाते हैं, फिर बसों में बैठकर निकल जाते हैं। फर्क इतना है कि बुधवार को मंजिल जंतर-मंतर थी और गुरुवार को राजघाट। इससे पहले विपक्ष ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला था। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए दिल्ली में शराब की दुकानें 9-10 अक्तूबर को बंद रहेंगी। कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, 'देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई जारी है। लोगों को उनके मतदान के अधिकार से अवैध रूप से वंचित किए जाने से बचाने की लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में सत्य की जीत होगी।' वहीं, खड़गे ने कहा कि वोट चोरी, बढ़ती महंगाई, युवाओं की समस्याएं और दूसरे संकट जनता के हित के खिलाफ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उन अधिकारों और स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश कर रही है, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे नेताओं ने देश के लिए हासिल किया था।

बापू जीवित होते तो राहुल को सलाह देते : भाजपा

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, 'इस समय आप राहुल गांधी और विपक्ष को राजघाट पर देख रहे हैं। अगर बापू जीवित होते तो कम से कम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को कुछ समझदारी भरी सलाह तो देते।'

जीएसटी अफसर से गिरफ्तारी का अधिकार छीना 5 करोड़ से कम की गड़बड़ी पर सिर्फ होगा जुर्माना

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीरवार को हुई 57वीं माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक में कारोबारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को राहत देने सहित कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि परिषद ने जीएसटी अधिकारियों के गिरफ्तारी के अधिकार को खत्म कर दिया है। साथ ही अभियोजन शुरू करने की सीमा को एक करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब पांच करोड़ रुपए करने को मंजूरी दी है। सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने रिफंड दावों को स्वीकार करने की समय सीमा 15 दिन से घटाकर अब 10 दिन कर दी है। परिषद ने ई-कॉमर्स मंचों पर छोटे विक्रेताओं के लिए नियम को आसान करने को अपनी मंजूरी दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि कर की दरों का ढांचा तय हो चुका है, इसलिए जीएसटी परिषद का ध्यान अब इस बात पर है कि कर व्यवस्था रोजमर्रा में कैसे काम करती है। उन्होंने बताया कि जीएसटी दरों में बदलाव अब साल में एक बार ही किया जाएगा। कर्मचारी 'बीमा कवर' पर चुकाए गए जीएसटी पर नियोक्ताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जीएसटी ढांचे में चेहरा-रहित कर प्रशासन शुरू करने की मंशा सरकार रखती है। वित्त मंत्री ने कहा कि जहां किसी विशेष उल्लंघन के लिए कोई विशिष्ट जुर्माना निर्धारित नहीं है, वहां लागू होने वाला सामान्य जुर्माना 25 हजार रुपए से घटाकर 10 हजार रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने अपनी 57वीं बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों के संबंध में अधिकारियों की एक समिति का गठन करने का फैसला लिया है। यह समिति इस बात की जांच करेगी कि उचित बिल रखने वाले, माल प्राप्त कर चुके और आपूर्तिकर्ता को पूरा भुगतान कर चुके वास्तविक खरीदार को किस तरह संरक्षण दिया जा सकता है।



◆ जीएसटी में सामान्य जुर्माना 25 हजार से घटकर 10 हजार हुआ

हरियाणा में बाजरे पर मिलेगा 2900 रुपए एमएसपी भावांतर भरपाई योजना से सरकार देगी पूरा लाभ

एजेंसी, पंचकूला। धान खरीद को लेकर किसानों की परेशानी को समझते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं। प्रदेश की मंडियों में शुरू हुई फसल खरीद प्रक्रिया को रिव्यू करते हुए सीएम ने अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।



नायब सैनी ने अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि सरकार धान और बाजरे की खरीद के साथ तत्काल उठान सुनिश्चित करेगी। फसल खरीद और भुगतान के किसी भी स्तर पर किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।

मंडी में खरीद व्यवस्था की निगरानी करेंगे एचसीएस

सीएम ने कहा कि हर मंडी में खरीद व्यवस्था की निगरानी के लिए एचसीएस स्तर के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। प्रशासनिक सचिव मंडियों का दौरा कर खरीद व उठान व्यवस्था की रिपोर्ट देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की बची धान को लेकर राइस मिलर्स के लिए विभागीय टीम गठित की गई थी। व्यापारियों की सुविधा के लिए 2777 प्रति क्विंटल की राशि निर्धारित की गई है।

◆ मंडियों में धान-बाजरे की खरीद और तत्काल उठान पर जोर

सरकार मंडियों में धान और बाजरे की सुचारू खरीद के साथ-साथ फसलों के तत्काल उठान की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा में अब तक पांच लाख क्विंटल धान खरीदा गया है। इसी के साथ मंडियों में आवक बढ़ाने के साथ उठान की गति बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार किसानों को बाजरे के लिए 2300 रुपए प्रति क्विंटल का एमएसपी सुनिश्चित करेगी। सीएम ने कहा कि खुले बाजार में 2300 से अधिक भाव मिलने पर 2900 रुपए एमएसपी भावांतर भरपाई की जाएगी। किसानों को भावान्तर भरपाई योजना के तहत किसानों को 600 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ मिलेगा। वहीं, बाजरे की खरीद निजी डीलरों के माध्यम से भी जारी रहेगी।

मुझे नोबेल नहीं दिया तो कमेटी की बदनामी होगी : ट्रंप

एजेंसी, वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक बार फिर नोबेल शांति पुरस्कार पर अपनी दावेदारी जताई। 2026 के



नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार, 9 अक्तूबर को होनी है। इससे एक दिन पहले ट्रंप ने कहा कि उन्हें यह पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर नोबेल समिति उन्हें यह पुरस्कार नहीं देती है, तो इससे नोबेल समिति की बहुत बदनामी होगी। ट्रंप ने कहा, 'मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ तथ्य बता रहा हूं। मैंने 8 युद्ध रुकवाए और दुनिया को तबाह होने से रोका। शायद किसी भी राष्ट्रपति ने इतने युद्ध नहीं सुलझाए।'

मुख्यमंत्री ने सेंट्रल पार्क में प्लांट मंडल रंगोली का किया शुभारंभ

हरित व सुंदर दिल्ली बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही सरकार : रेखा गुप्ता

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वीरवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के साथ 'प्लांट मंडला रंगोली' का शुभारंभ किया।

उन्होंने कहा कि जीवित पौधों से सजी यह सुंदर मंडला रंगोली हमारी भारतीय कला परंपरा और प्रकृति के प्रति प्रेम का अनूठा उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के साथ हम अपनी दिल्ली को भी हरित, सुंदर और विकसित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप भी अपने परिवार के साथ सेंट्रल पार्क जरूर आइए और इस सुंदर प्लांट मंडला



आर्ट का आनंद लीजिए। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, दिल्ली भाजपा प्रदेश महामंत्री योगिता सिंह एवं विधायक अशोक गोयल उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि इस रंगोली को बनाने के लिए छोटे गमलों में लगे सजीव पौधों, कटी हुई हरी पत्तियों और रंग-बिरंगे फूलों का इस्तेमाल एक निश्चित ज्यामितीय (सर्कुलर) पैटर्न में किया जाता है।

इसमें किसी भी तरह के कृत्रिम या हानिकारक केमिकल वाले रंगों का उपयोग नहीं होता, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मंडला आकृतियां और हरे-भरे पौधे मिलकर एकाग्रता, शांति और सकारात्मकता का माहौल बनाते हैं।

बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए आजीवन समर्पित रहे राम विलास : सीएम योगी

एजेंसी, लखनऊ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीरवार को सुशांत गोल्फ सिटी स्थित एक होटल में आयोजित पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल हुए।



श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 50 वर्ष पहले देश की राजनीति में एक ऐसे युवा नेता का उदय हुआ, जो समय के साथ दलितों, शोषितों और वंचितों की प्रखर आवाज बने। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जनार्दन ने उन्हें बहुत सम्मान दिया और देश में सबसे अधिक मतों के रिकॉर्ड से जिताकर भारत की संसद में भेजा था। रामविलास पासवान ने आजीवन भारतीय राजनीति के माध्यम से सामाजिक चेतना को जगाने और बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय पासवान के साथ संसद में बिताए अपने लंबे कार्यकाल को याद करते हुए कहा, 'मुझे संसद में उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। उनके मन में भारत की सनातन परंपरा के प्रति गहरा श्रद्धा और सम्मान का भाव था।' मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि रामविलास पासवान ने बिना किसी भेदभाव के सामाजिक लड़ाई को आगे बढ़ाया। चाहे वह श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल, एक केंद्रीय मंत्री के रूप में उनका व्यवहार हमेशा बेहद सहज, स्नेही और सदाशयता से पूर्ण रहता था, जो हर किसी के हृदय को छू लेता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भले ही रामविलास पासवान की भौतिक अनुपस्थिति हमें खलती है, लेकिन यह बेहद संतोषजनक है कि उनके पुत्र और वर्तमान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने पिता के उस अधूरे मिशन को पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं।

कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने कहा- 'मेरा गांव-मेरी जिम्मेदारी' की भावना से काम करें पंचायत प्रतिनिधि

सशक्त पंचायतें विकसित उत्तराखंड की मजबूत नींव : धामी

भारतेन्दु संवाददाता, हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीरवार को कहा कि सशक्त पंचायतें ही विकसित उत्तराखंड की मजबूत नींव हैं और पंचायत प्रतिनिधियों को 'मेरा गांव-मेरी जिम्मेदारी' की भावना के साथ काम करते हुए विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए।

मुख्यमंत्री धामी हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमता विकास के लिए आयोजित एकदिवसीय अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विकासखंडों में एक साथ 60 हजार से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण से जोड़ना ग्राम स्तर पर विकास को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा



◆ पंचायतों का धन जनता का एक-एक पाई का हिसाब हो

कि पंचायत प्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। स्थानीय समस्याओं की बेहतर समझ होने के कारण योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका है। उन्होंने प्रतिनिधियों से ग्राम सभाओं में लोगों के सुझाव लेकर स्थानीय आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने को कहा।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत योजना में स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा और अपेक्षित परिणाम निर्धारित किए जाएं। पेयजल, सड़क, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए तथा कमजोर और वंचित वर्गों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाए। धामी ने कहा कि वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 56 हजार से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया। राज्य की 7,817 ग्राम पंचायतों में से 5,972 में पंचायत भवन ग्राम सचिवालय के रूप में संचालित हो रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में 1,362 पंचायत भवनों का निर्माण और 584 की मरम्मत की गई है, जबकि एक हजार से अधिक ग्राम पंचायतों का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से पंचायतों की कार्ययोजनाओं, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा कार्यों की जियो टैगिंग की जा रही है।

डिजिटल पंचायत व्यवस्था का उद्देश्य कामकाज को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। उन्होंने कहा कि पंचायतों का धन जनता का धन है और उसकी एक-एक पाई का हिसाब जनता के सामने होना चाहिए।

कचरा प्रबंधन के लिए पंचायतों को उपलब्ध कराई मशीनें

मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से विकास कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यों की संख्या से अधिक उनका प्रभाव मायने रखता है। सड़कों की गुणवत्ता, पेयजल योजनाओं की उपयोगिता और पंचायत भवनों से मिलने वाली सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने स्वच्छता को जनभागीदारी से जोड़ने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जिला पंचायतों को ग्रामीण मोटर मार्गों और स्थानीय बाजारों की सफाई के लिए कचरा उठाने वाली मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। विकासखंड स्तर पर भी इस दिशा में मशीनें स्थापित की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने निभाया वायदा, स्कूल भवनों समेत विकास कार्यों के लिए 15.75 करोड़ किए जारी

रचौली और काशापाट स्कूल भवनों के लिए दो-दो करोड़ रुपए जारी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम के दौरान बच्चों और स्थानीय लोगों से किए वायदों को पूरा करते हुए शिमला जिले के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के भटवाड़ी और रामपुर विधानसभा क्षेत्र के काशापाट के लिए विकास कार्यों की सौगात दी है। इन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के अनुरूप योजना विभाग ने 15.75 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। इसमें स्कूल भवनों के निर्माण के लिए चार करोड़ रुपये भी शामिल हैं।



रामपुर में विद्यार्थियों के साथ संवाद के दौरान एक छात्रा ने मुख्यमंत्री से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रचौली के नए भवन के निर्माण के लिए दो करोड़ रुपये देने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने बच्चों की मांग को प्राथमिकता देते हुए इसकी घोषणा की थी। अब योजना विभाग ने इसके लिए दो करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी तरह काशापाट स्कूल के नए भवन के निर्माण के लिए भी दो करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इससे दोनों विद्यालयों में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान स्थानीय लोगों की मांगों पर की गई कुल नौ घोषणाओं के लिए 15.75 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इससे सड़क, पुल, फुट ब्रिज, क्रैश बैरियर और अन्य आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।

रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र की तांगणू-जांगलिक पंचायत के लोगों की मांग पर सुंदरु खड्ड पर पुल निर्माण के लिए चार करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा बरशील पुल के लिए एक करोड़ रुपये और शिशारा में फुट ब्रिज निर्माण के लिए 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। रोहड़ू में अंबेडकर भवन के निर्माण के लिए भी 50 लाख रुपये जारी किए गए हैं। इस संबंध में योजना विभाग ने स्वीकृति पत्र लोक निर्माण विभाग को भेज दिया है।

रामपुर विधानसभा क्षेत्र के काशापाट में धनदोल से काशापाट तक क्रैश बैरियर लगाने के लिए दो करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। जबल से खाबल सड़क के सुधार और क्रैश बैरियर लगाने के लिए भी दो करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों से क्षेत्र में सड़क सुरक्षा बेहतर होने के साथ स्थानीय लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी।

जनसमस्याओं के समाधान का मंच

'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम केवल जनसंवाद का माध्यम नहीं बल्कि लोगों की समस्याओं के समाधान और मौके पर किए गए वायदों को धरातल पर उतारने का प्रभावी मंच बन रहा है। मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान स्थानीय लोगों और विद्यार्थियों द्वारा रखी गई मांगों पर संबंधित विभागों के माध्यम से त्वरित कार्रवाई की जा रही है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक आम लोगों की मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान घोषित विकास कार्यों के लिए धनराशि जारी होने से क्षेत्रवासियों को अब इन कार्यों के शीघ्र शुरू होने की उम्मीद जगी है। इससे शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। इन विकास कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, सड़क संपर्क और सुरक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। धनराशि जारी होने के बाद संबंधित विभाग कार्यों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाएंगे।

एसआईआर विरोध पर रणधीर शर्मा ने कांग्रेस को घेरा

रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पर संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रणधीर शर्मा ने कांग्रेस के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध को लेकर निशाना साधा। शिमला में पत्रकार वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस संवैधानिक प्रक्रिया का विरोध कर जनता में भ्रम पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के तहत चुनाव आयोग को मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। उनके अनुसार एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है और पहले भी मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण किया जा चुका है।



रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता लंबे समय से मतदाता सूचियों में गड़बड़ी और 'वोट चोरी' के आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूचियों की जांच, दोहरे नामों की पहचान, अपात्र प्रविष्टियों को हटाना और पात्र मतदाताओं के नाम सुनिश्चित करना है, तो कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस अपने आरोपों को लेकर गंभीर है तो उसे पुनरीक्षण प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए।

भाजपा नेता ने कांग्रेस पर चुनाव परिणामों को लेकर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने पर कांग्रेस जनादेश स्वीकार करती है, जबकि हार के बाद ईवीएम और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकारें ईवीएम से हुए चुनावों के बाद बनीं। ऐसे में कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि जीत वाले चुनावों में ईवीएम विश्वसनीय और हार वाले चुनावों में संदिग्ध कैसे हो जाती है। रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मंत्रियों द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा होती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि यदि उन्हें चुनावी प्रक्रिया पर इतना अविश्वास है तो क्या वह अपनी चुनावी जीत पर भी सवाल उठाकर पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों का उल्लेख करते हुए कहा कि नगर निगम और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को भी समर्थन मिला है।

संवैधानिक प्रक्रिया में सहयोग की अपील

रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को चुनाव आयोग पर आरोप लगाने के बजाय अपनी नीतियों और संगठनात्मक स्थिति पर आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एसआईआर से संबंधित विषय न्यायालय के समक्ष भी विचाराधीन हैं और चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। आपत्ति होने पर राजनीतिक दलों को कानूनी और निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा मतदाता सूचियों की पारदर्शिता और शुद्धता के साथ प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा के पक्ष में है।

घनाहट्टी में वाहन से 10 ग्राम चिट्टा बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिमला पुलिस ने घनाहट्टी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस थाना वेस्ट शिमला की टीम ने नलहट्टी क्रॉसिंग के समीप एक वाहन में बैठे तीन व्यक्तियों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से करीब 10 ग्राम चिट्टा यानी हेरोइन बरामद हुई।



पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई 7 अक्तूबर 2026 को स्पेशल सेल शिमला की टीम ने की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान यशपाल ठाकुर पुत्र धनी राम ठाकुर, निवासी तहसील एवं जिला बिलासपुर, उम्र 25 वर्ष, ललित कुमार पुत्र स्वर्गीय लच्छी राम, निवासी तहसील अर्की, जिला सोलन, उम्र 34 वर्ष और निकिता दत्त पुत्री शिवदत्त, निवासी तहसील एवं जिला शिमला, उम्र 26 वर्ष के रूप में हुई है।

पुलिस ने बरामदगी के संबंध में पुलिस थाना वेस्ट शिमला में प्राथमिकी संख्या 213/2026 दर्ज की है। मामला स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत दर्ज किया गया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है। जांच के दौरान नशीले पदार्थ के स्रोत और आरोपियों की भूमिका से जुड़े अन्य पहलुओं का पता लगाया जा रहा है।

स्वरोजगार को बैंक ऋण से मिलेगी नई रफ्तार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने पर चर्चा

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की 181वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक शिमला में आयोजित हुई। बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, यूको बैंक, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों, अग्रणी जिला प्रबंधकों तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, वित्तीय समावेशन, ऋण वितरण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा की गई।



बैठक में यूको बैंक के प्रबंध निदेशक (प्रभारी) एवं कार्यकारी निदेशक राजेंद्र कुमार साबू ने कहा कि सभी हितधारकों को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समयबद्ध और पर्याप्त बैंक ऋण तथा बैंकिंग सेवाएं समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रदेश के हर क्षेत्र तक पहुंचें। उन्होंने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों और दूर-दराज क्षेत्रों में आबादी के बिखराव को देखते हुए बैंकिंग सेवाओं की पहुंच और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।

बैठक में हिमाचल प्रदेश में स्वरोजगार एवं रोजगार सृजन के लिए बैंक ऋण बढ़ाने की रणनीति पर विशेष चर्चा हुई। युवाओं के लिए स्वरोजगार, उद्यमिता और स्थायी आजीविका के अवसर बढ़ाने तथा सरकारी योजनाओं को बैंक ऋण से बेहतर ढंग से जोड़ने के उपायों पर विचार किया गया। साथ ही बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नेटवर्क के माध्यम से महिलाओं की बैंकिंग क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के शिमला क्षेत्रीय निदेशक पी. एस. खुआल ने ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नेटवर्क को मजबूत करने तथा इसमें महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई।

बैठक में 'हिमाचल का गौरव' कार्यक्रम के तहत सफल लाभार्थियों और प्रदेश के विशिष्ट नागरिकों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि समय पर संस्थागत ऋण, सरकारी योजनाओं, कौशल विकास और वित्तीय सहयोग से आजीविका में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। इससे उद्यमिता और रोजगार के स्थायी अवसर भी सृजित होते हैं।

इस दौरान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत एक लाभार्थी को दावा राशि का चेक प्रदान किया गया। इससे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के महत्व और वित्तीय सुरक्षा में बैंकों की भूमिका को रेखांकित किया गया।

यूको बैंक के हिमाचल प्रदेश एसएलबीसी संयोजक कमल शर्मा ने कहा कि बैठक में मिले सुझाव ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन, स्वरोजगार और रोजगार सृजन को मजबूत करने में सहायक होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त सचिव अभिषेक जैन ने कहा कि समिति की चर्चाएं केवल बैंकिंग प्रदर्शन की समीक्षा तक सीमित न रहकर व्यावहारिक और क्रियान्वयन योग्य रणनीतियों पर केंद्रित होनी चाहिए।

वन्यजीव आवास संरक्षण से स्वस्थ जीवन और आजीविका सुरक्षित : सुधा

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के वन्यजीव विंग की ओर से आयोजित वन्यजीव सप्ताह-2026 का समापन समारोह गेयटी थियेटर, शिमला में हुआ। कार्यक्रम में प्रधान सचिव वन एम. सुधा देवी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। समारोह की शुरुआत प्रदर्शनी के अवलोकन और दीप प्रज्वलन के साथ हुई।



एम. सुधा देवी ने कहा कि वन्यजीव सप्ताह केवल आयोजनों तक सीमित नहीं है, बल्कि वन्यजीव संरक्षण के प्रति सामूहिक संकल्प को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने इस वर्ष के विषय 'वन्यजीव आवासों का संरक्षण, स्वस्थ जीवन और आजीविका को बनाए रखना' पर जोर देते हुए कहा कि सुरक्षित वन्यजीव आवास वन्यजीवों के साथ जल, पर्यावरण, स्वास्थ्य, कृषि और आजीविका के लिए भी जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य का आधार है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी समृद्ध जैव विविधता, घने जंगलों, ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों और ठंडे मरुस्थलीय इलाकों के कारण विशिष्ट पहचान रखता है। इन प्राकृतिक संपदाओं की रक्षा करना सभी का साझा दायित्व है।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न पुस्तकों एवं प्रकाशनों का विमोचन किया गया। सप्ताह भर आयोजित प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। विभागीय वन्यजीव फोटोग्राफी प्रतियोगिता में वन रक्षक अक्षय भारद्वाज ने प्रथम, वन रक्षक वींकेश ने द्वितीय और वन खंड अधिकारी संतोष कुमार ठाकुर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

'जंगल से इंसान तक' नामक नाटक प्रस्तुत कर वन्यजीवों और पर्यावरण के बीच संबंध को दर्शाया गया। नाटक के माध्यम से दर्शकों को प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।

शिमला में काले रिबन बांधकर कांग्रेस का प्रदर्शन

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन प्रदर्शन कर सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जिला कांग्रेस कमेटी शिमला शहरी की ओर से जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में लोकतंत्र की रक्षा और विपक्ष की आवाज दबाए जाने के विरोध में शांतिपूर्ण मौन प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हाथों पर काले रिबन बांधकर सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया।



प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने विपक्ष के प्रमुख नेताओं को हिरासत में लेने और उनके साथ कथित बदसलूकी की भी निंदा की।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर भी चिंता जताई। नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की साख और निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखना आवश्यक है।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने वाले विपक्षी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस और प्रशासन के माध्यम से बल प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने इसे निंदनीय बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में असहमति की आवाज को सम्मान मिलना चाहिए। नेताओं ने कहा कि विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों को उठाता रहेगा और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगा।

पांच वन मंडलों के समूहों ने सजाए आकर्षक स्टॉल

रिज पर जाइका के प्राकृतिक उत्पाद बने सैलानियों की पहली पसंद

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। पहाड़ों की रानी शिमला के रिज पर जाइका वानिकी परियोजना से जुड़े स्वयं सहायता समूहों के प्राकृतिक और रसायन मुक्त उत्पाद स्थानीय लोगों के साथ सैलानियों की भी पहली पसंद बने। वन्यप्राणी सप्ताह के अंतिम दिन वीरवार को वन मंडल किन्नौर, बंजार, शिमला, रोहड़ू और चौपाल के स्वयं सहायता समूहों ने अपने उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शनी के लिए स्टॉल लगाए।

प्रधान सचिव वन एम. सुधा देवी ने सभी स्टॉल का निरीक्षण किया और स्वयं सहायता समूहों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जाइका वानिकी परियोजना से जुड़े समूह बेहतर उत्पाद तैयार कर अपनी आजीविका मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने लाहौल और किन्नौर जैसे दूरदराज क्षेत्रों से पहुंची महिलाओं के प्रयासों की विशेष रूप से प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि लाहौल का छरमा, किन्नौरी पारंपरिक वस्त्र, देसी घी, स्थानीय शहद, अचार, किन्नौरी राजमाह, लाल चावल, कोदे का आटा, गर्म जुराबें, पाइल नीडल उत्पाद और सीरा-बड़ी जैसे उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। प्राकृतिक और रसायन मुक्त होने के साथ उचित कीमतों पर उपलब्ध इन उत्पादों को खरीदने के लिए रिज पर लोगों की भीड़ उमड़ी।

इस अवसर पर वन बल प्रमुख एवं जाइका के मुख्य परियोजना निदेशक डॉ. संजय सूद, पीसीसीएफ वन्यजीव आलोक प्रेम नागर, अनु नागर, सीसीएफ के. थिरूमल, सीएफ वन्यजीव प्रीति भंडारी सहित वन विभाग और जाइका परियोजना के कई अधिकारी मौजूद रहे।

सीपीआईएम ने एसआईआर का विरोध कर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग उठाई

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। सीपीआईएम की लोकल कमेटी ने जिलाधीश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करने और गिरफ्तार करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने लोकतंत्र एवं चुनावी पारदर्शिता की रक्षा की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रही है।



प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने दावा किया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कई बार लिखित आपत्तियां दर्ज कराईं। उनके अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर बिना चर्चा के निर्णय लेने का आरोप लगाया है। वक्ताओं ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और अभिलेख अद्यतन करने की शक्तियों के केंद्रीकरण पर भी सवाल उठाए।

सीपीआईएम नेताओं ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि नए मतदाताओं से माता-पिता और दादा-दादी के पुराने दस्तावेजों की जानकारी मांगी जा रही है, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को परेशानी हो रही है।

चिट्टा तस्करी आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने की खारिज

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। चिट्टा तस्करी के मामले में शिमला पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी सूरज चौहान की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। पुलिस थाना बालूगंज (पश्चिम), शिमला में दर्ज अभियोग संख्या 133/2026 में आरोपी के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज है। पुलिस के अनुसार कुमारसैन निवासी सूरज चौहान पुत्र राम कुमार के कब्जे से करीब 242 ग्राम हेरोइन यानी चिट्टा बरामद किया गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों को एकत्र किया और आरोपी की भूमिका से संबंधित तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पुलिस ने बरामदगी और मामले की गंभीरता को आधार बनाते हुए जमानत याचिका का प्रभावी ढंग से विरोध किया। पुलिस ने बरामदगी और जांच के दौरान जुटाए साक्ष्यों को अदालत के समक्ष रखा। अदालत ने पुलिस की दलीलों और मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है और तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी जांची जा रही है।

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से पुलिस का संवाद, सुरक्षा और समन्वय पर हुई चर्चा

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। नगर पुलिस अधीक्षक मेहर पंवार ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं, चिंताओं और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस संवाद में विश्वविद्यालय के सभी प्रमुख छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस और छात्र समुदाय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के साथ विद्यार्थियों के विचारों और अपेक्षाओं को समझना रहा।



संवाद के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों को लेकर अपने विचार रखे। पुलिस अधिकारियों ने भी विद्यार्थियों की बातों को गंभीरता से सुना और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर आवश्यक जानकारी साझा की। विश्वविद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाए रखने, आपसी सहयोग बढ़ाने तथा किसी भी समस्या की स्थिति में पुलिस से संपर्क करने को लेकर भी चर्चा हुई।

नगर पुलिस अधीक्षक मेहर पंवार ने कहा कि विद्यार्थियों के साथ नियमित संवाद से उनकी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। पुलिस और छात्र समुदाय के बीच विश्वास मजबूत होना सुरक्षित एवं सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण के लिए जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की असुरक्षा या परेशानी होने पर पुलिस को जानकारी देने का आग्रह किया।

विद्यार्थियों ने पुलिस की इस पहल का सकारात्मक रूप से स्वागत किया। छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस तरह के संवाद से विद्यार्थियों को अपनी बात सीधे पुलिस अधिकारियों के सामने रखने का अवसर मिलता है।

विरोध रजनी पाटिल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, इस्तीफे की दोहराई मांग

ऊना में कांग्रेस का प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, ऊना। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने के विरोध में कांग्रेस ने गुरुवार को ऊना में काला दिवस मनाते हुए प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कांग्रेस ने 8 अक्तूबर को देशभर में काला दिवस मनाने और जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था।

ऊना में प्रदर्शन सर्किट हाउस से शुरू हुआ और बस स्टैंड होते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस विधायक, वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो' और 'वोट चोर गद्दी छोड़' जैसे नारे लगाए।

उपायुक्त कार्यालय पहुंचने के बाद कांग्रेस नेताओं ने अतिरिक्त उपायुक्त ऊना के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें पद से हटाने की मांग उठाई गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा उठाए जा रहे सवाल मतदाताओं के अधिकारों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हैं।



कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली में हुए व्यवहार के विरोध में कांग्रेस देशभर में प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कार्यप्रणाली को लेकर पार्टी की आपत्तियां दोहराईं। पाटिल ने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाएगी और मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखेगी।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूचियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों को जनता के सामने रख रही है और पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव तक अपनी बात पहुंचाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में लोगों के मतदान अधिकार से वंचित होने संबंधी सवालों का जवाब मिलना चाहिए। हालांकि ये आरोप कांग्रेस के राजनीतिक दावे हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर कांग्रेस एकजुट है तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहेगा।

भारतेन्दु Classifieds

नाम परिवर्तन

मैं, विशाल राणा पुत्र श्री जगदीश राणा निवासी गाँव गजेड़, डाकघर डोली, तहसील रामशहर, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश-174102 ब्यान करता हूं कि मैंने अपना नाम विशाल से बदलकर विशाल राणा रख लिया है। सभी नोट करें।

टीबी मुक्त भारत अभियान को गति देंगी पौड़ी की जोश टीमें



भारतेन्दु संवाददाता, पौड़ी गढ़वाल। भारत सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड के निर्देशों के तहत जनपद पौड़ी गढ़वाल में टीबी मुक्त भारत अभियान को गति देने के लिए ज्वाइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ (जोश) टीमों का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर वर्चुअल माध्यम से आयोजन हुआ, जिसका सीधा प्रसारण जनपद स्तर पर किया गया। इस अवसर पर विधायक राजकुमार पोरी, जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मेघना असवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अभियान के तहत जनपद के प्रत्येक विकासखंड से पांच-पांच युवाओं को मेरा भारत स्वयंसेवक और एनसीसी कैडेट्स के साथ टीबी मुक्त भारत टीम में शामिल किया गया है।

ये युवा अपने-अपने क्षेत्रों में घर-घर जाकर लोगों को टीबी के लक्षण, जांच, उपचार और सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मेघना असवाल ने बताया कि जोश टीम के सदस्य टीबी के संभावित लक्षणों के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ संदिग्ध मरीजों को समय पर जांच कराने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही पात्र मरीजों को निक्षय पोषण योजना सहित उपलब्ध सरकारी सहायता की जानकारी दी जाएगी।

कार्यक्रम के दौरान टीबी मुक्त घोषित ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ समुदाय और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। कार्यक्रम में जोश मोबाइल एप पर युवाओं का पंजीकरण कराया गया और सभी प्रतिभागियों को टीबी मुक्त भारत के निर्माण में सहयोग की शपथ दिलाई गई। युवाओं से अपील की गई कि वे टीबी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करते हुए लोगों को जांच और उपचार के लिए प्रेरित करें।

क्षतिग्रस्त मार्गों को ठीक करने के लिए 462 करोड़ के बजट की आवश्यकता : महाराज

कहा- सड़क-पुल निर्माण में लापरवाही पर तय होगी जिम्मेदारी

अनिल थपलियाल

देहरादून। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश की सड़कों और पुलों की गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग के अंतर्गत बनाए गए सभी पुलों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए और लंबित तथा निर्माणाधीन सड़कों की जनपदवार समीक्षा सुनिश्चित की जाए। सड़क और पुल निर्माण में गुणवत्ता, निर्माण सामग्री, डामरीकरण, सड़क की मोटाई, प्रयोगशाला परीक्षण और थर्ड पार्टी गुणवत्ता जांच पर विशेष ध्यान दिया जाए। यदि कहीं भी निर्माण कार्य में खराब गुणवत्ता सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसियों की जवाबदेही तय की जाए।

यमुना कॉलोनी स्थित लोनिवि सभागार में अधिकारियों के साथ



समीक्षा बैठक के दौरान लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज के साथ अन्य प्रतिनिधि सामूहिक चित्र में।

समीक्षा बैठक के दौरान महाराज ने वैकल्पिक मार्गों और डायवर्जन वाले स्थानों पर पर्याप्त साइन बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सड़क संकेतक स्पष्ट और उचित ऊंचाई पर लगाए जाएं, ताकि वाहन चालकों को समय रहते मार्ग परिवर्तन और संभावित खतरों की जानकारी मिल सके। उन्होंने सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया।

बैठक के बाद महाराज ने बताया कि वर्ष 2026-27 में आपदा के कारण प्रदेश में कुल 2360 मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनमें से 2329 मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है, जबकि शेष मार्गों को भी पूर्व स्थिति में लाने का काम जारी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 199 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिनके समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

समीक्षा बैठक में मंत्री ने गुणवत्ता युक्त कार्य के दिये निर्देश

मंत्री ने बताया कि गड्ढा पैच वर्क ऐप के माध्यम से प्राप्त 1953 शिकायतों में से 1327 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जबकि शेष 626 शिकायतें अन्य विभागों से संबंधित होने के कारण उन्हें हस्तांतरित कर दी गई हैं। इसके अलावा प्रदेश में 34 निष्प्रयोजित पुलों में से 21 पुलों को दोबारा उपयोग में लाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपदा से क्षतिग्रस्त मार्गों को खोलने और उन्हें पूर्व अवस्था में लाने के लिए 461.87 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता है। महाराज ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क और पुल निर्माण में किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो तथा गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाए। बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे, प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा, मुख्य अभियंता रंजीत रावत, मुकेश परमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्य सचिव ने किया नाबार्ड सेब महोत्सव 3 .0 का शुभारंभ

अनिल थपलियाल



देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने गुरुवार को नाबार्ड के शाखा कार्यालय, देहरादून में नाबार्ड से वित्तपोषित किसान उत्पादक संगठनों द्वारा आयोजित सेब महोत्सव 3.0 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न किसान उत्पादक संगठनों द्वारा उत्पादित सेब की विभिन्न प्रजातियों, कीवी, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने किसानों और एफपीओ प्रतिनिधियों से उत्पादों की जानकारी लेने के साथ उनकी समस्याओं पर भी चर्चा की।

मुख्य सचिव ने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों को केवल किसानों को एक मंच पर जोड़ने तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें मजबूत, आत्मनिर्भर और टिकाऊ संस्थाओं के रूप में विकसित किया जाना जरूरी है। इसके लिए एफपीओ को निरंतर मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, क्षमता विकास और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने कृषि एवं बागवानी उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए खरीद, विपणन और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ उन्हें उचित बाजार और बेहतर मूल्य से जोड़ने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। किसानों के उत्पादों के सुरक्षित भंडारण और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए शीत भंडारण की सुविधाओं के विस्तार पर भी उन्होंने जोर दिया। साथ ही उत्पादों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ट्रेसेबिलिटी व्यवस्था विकसित करने तथा जैविक उत्पादों के लिए जैविक प्रमाणन की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की बात कही।

मुख्य सचिव ने कहा कि एफपीओ को मजबूत बनाने के लिए नाबार्ड और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एफपीओ को टिकाऊ बनाने के लिए ऐसा इकोसिस्टम विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें योजनाओं और उपलब्ध संसाधनों को आपस में जोड़कर किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके।

उत्तराखंड में 39,815 परिवारों को मिली पक्की छत

अनिल थपलियाल

देहरादून। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद और बेघर परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वर्ष 2022 से अब तक प्रदेश के 39,815 परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इनमें ऊधमसिंह नगर में सर्वाधिक 4,882, हरिद्वार में 4,493 और रुद्रप्रयाग में 4,032 परिवारों को आवास का लाभ मिला है।

चमोली में 3,900, पिथौरागढ़ में 3,386, पौड़ी में 3,195, उत्तरकाशी में 3,057, देहरादून में 2,839 और चंपावत में 2,789 आवास बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री

◆धामी की पैरवी से गांवों में साकार हुआ पक्की छत का सपना

धामी जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के समक्ष लगातार पैरवी करते रहे हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य बेघर तथा कच्चे और जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का घर उपलब्ध कराना है। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1.30 लाख रुपये की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। इसके साथ ही रसोई सामग्री और बर्तन खरीदने के लिए दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता राशि को वर्ष 2022-23 से पांच हजार रुपये से बढ़ाकर छह हजार रुपये किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता भी दी जा रही है। आवास निर्माण के लिए मनरेगा के माध्यम से 95 दिन की मजदूरी का प्रावधान है। लाभार्थियों को पेयजल, उज्ज्वला गैस और विद्युत कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी जोड़ा जा रहा है।

इस योजना ने ग्रामीण परिवारों को केवल पक्का मकान ही नहीं दिया, बल्कि उनके जीवन में सुरक्षा, स्थायित्व और सम्मान भी बढ़ाया है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी पात्र परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे।

ऐप पर सवारी, लेकिन निगरानी किसकी ?

विकास बलूनी

देहरादून। देहरादून में रैपिडो, ओला और उबर जैसी ऐप आधारित कैब एवं बाइक सेवाओं का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। कुछ ही मिनटों में सवारी उपलब्ध हो जाती है और लोगों को सुविधा मिलती है। लेकिन सुविधा के इस दौर में एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है—इन सेवाओं से जुड़े वाहनों, चालकों और उनकी पृष्ठभूमि की निगरानी आखिर कितनी प्रभावी है?

कई बार शिकायतें सामने आती हैं कि ऐप पर दर्ज वाहन संख्या और मौके पर पहुंचने वाले वाहन का नंबर अलग होता है, या वाहन तो वही होता है लेकिन चालक कोई दूसरा व्यक्ति। यदि ऐसा हो रहा है तो यह महज तकनीकी चूक नहीं, बल्कि यात्री सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल है। जिस चालक और वाहन की जानकारी देखकर यात्री बुकिंग करता है, मौके पर भी वही चालक और वही वाहन होना चाहिए। सवाल दूसरे राज्यों से देहरादून आने वाले चालकों को लेकर भी है। क्या उनके ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, बीमा, फिटनेस और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की नियमित एवं गहन जांच होती है? क्या परिवहन विभाग और आरटीओ के पास ऐसे चालकों और वाहनों की प्रभावी निगरानी का कोई मजबूत तंत्र है?

सबसे गंभीर चिंता उन शिकायतों और



आशंकाओं को लेकर है, जिनमें कभी-कभी आरोप लगाए जाते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व परिवहन सेवाओं की आड़ में नशे जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं या घरों और इलाकों की रेकी कर सकते हैं। इन आरोपों की पुष्टि संबंधित जांच के बाद ही हो सकती है, लेकिन ऐसी शिकायतों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। यदि कोई चालक लगातार अलग-अलग इलाकों में सवारी लेकर पहुंचता है, तो उसकी पहचान और गतिविधियों का सत्यापन सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

एक और बड़ा सवाल वाहन के मालिक और वाहन चलाने वाले व्यक्ति को लेकर है। यदि वाहन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत है और उसे कोई अन्य व्यक्ति व्यावसायिक रूप से चला रहा है, तो क्या आरटीओ यह सुनिश्चित करता है कि चालक के सभी दस्तावेज वैध हैं? क्या वाहन का परमिट, बीमा, फिटनेस और अन्य आवश्यक कागजात नियमानुसार हैं? और यदि कोई निजी वाहन व्यावसायिक यात्री सेवा में इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी है?

यह सवाल किसी एक ऐप या कंपनी पर उंगली उठाने का नहीं, बल्कि व्यवस्था की जवाबदेही का है। शहर में ऐप आधारित वाहन लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या परिवहन विभाग और आरटीओ भी उसी अनुपात में उनकी निगरानी कर पा रहे हैं?

आरटीओ को समय-समय पर विशेष जांच अभियान चलाने की जरूरत है। वाहन नंबर, चालक की पहचान, वाहन मालिक, परमिट, बीमा, फिटनेस और ऐप पर दर्ज विवरण का मौके पर मिलान किया जाना चाहिए। दूसरे राज्यों से आने वाले चालकों के सत्यापन की व्यवस्था भी स्पष्ट होनी चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि ऐप पर जिस वाहन और चालक की तस्वीर एवं जानकारी दिखाई जा रही है, सवारी के लिए मौके पर वही वाहन और वही चालक पहुंचे। क्योंकि ऐप सुविधा दे सकता है, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी व्यवस्था की है। सवारी का भरोसा केवल मोबाइल स्क्रीन पर नहीं, बल्कि आरटीओ की निगरानी, परिवहन विभाग की सतर्कता और नियमों के सख्त पालन पर टिका है। जनसुरक्षा के मामले में छोटी-सी चूक भी बड़ी घटना का कारण बन सकती है। इसलिए अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि 'ऐप पर सवारी मिल रही है या नहीं?' बल्कि यह भी है—'ऐप पर सवारी तो मिल रही है, लेकिन उस सवारी और चालक की निगरानी आखिर कौन कर रहा है?

मसूरी में अवैध निर्माण पर एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई होटल अतिथि के 12 कमरे और बेसमेंट सील

भारतेन्दु संवाददाता, सुनील सोनकर



मसूरी। मसूरी में बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माण के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त सचिव/एसडीएम मसूरी राहुल आनंद के आदेश के बाद प्राधिकरण की टीम ने लाइब्रेरी क्षेत्र स्थित होटल अतिथि में अनधिकृत निर्माण के 12 कमरों और बेसमेंट को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। एमडीडीए की टीम ने निर्माण से संबंधित अभिलेखों और पूर्व में जारी आदेशों के आधार पर यह कार्रवाई की। प्रधिकरण के सहायक अभियंता अजय मलिक ने बताया कि संयुक्त सचिव के आदेश के बाद सीलिंग की कार्रवाई की गई। उन्होने बताया कि एमडीडीए की टीम ने होटल अतिथि परिसर में अनधिकृत रूप से निर्मित बताए जा रहे 12 कमरों और बेसमेंट को सील किया।

प्राधिकरण की कार्रवाई के बाद होटल परिसर में अनधिकृत निर्माण वाले हिस्से में आवाजाही रोक दी गई। एमडीडीए की कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब मसूरी में अनधिकृत निर्माण को लेकर प्राधिकरण पहले से कार्रवाई कर रहा है। प्राधिकरण की एक अन्य पत्रावली में संपत्ति भवन, डिक रोड मसूरी से संबंधित निर्माण का भी उल्लेख है। इसमें पूर्व निर्मित मुख्य भवन और आउट हाउस के भीतर आरसीसी कॉलम व बीम का निर्माण तथा पहाड़ की खुदाई कर पुश्ते और आरसीसी दीवार बनाने का मामला दर्ज किया गया था। प्राधिकरण के मुताबिक इस मामले में उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 की धारा 27 के तहत वाद दर्ज किया गया था। 24 अप्रैल 2026 को संबंधित पक्ष को कारण बताओ नोटिस और निर्माण कार्य रोकने का नोटिस जारी किया गया था।

उन्होने बताया कि क्षेत्रीय अभियंताओं की रिपोर्ट में मौके पर आरसीसी दीवारों, पुश्तों, कॉलम और बीम के निर्माण के साथ पहाड़ की खुदाई का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में विभिन्न स्थानों पर आरसीसी दीवार और पुश्ते बनाए जाने तथा पूर्व निर्मित ढांचे को बदलकर नए निर्माण की तैयारी किए जाने की बात कही गई है। एमडीडीए के अनुसार अनधिकृत निर्माण या विकास कार्य के लिए प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति लेना अनिवार्य है। संबंधित पक्ष को निर्माण से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने और आवश्यक होने पर शमन मानचित्र प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया था। प्राधिकरण का कहना है कि निर्धारित प्रक्रिया के बावजूद निर्माण से संबंधित आवश्यक स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई। मसूरी में बढ़ते निर्माण और पहाड़ों की कटिंग को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं।

शहर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई को लेकर एमडीडीए लगातार निगरानी कर रहा है। होटल अतिथि के 12 कमरों और बेसमेंट की सीलिंग की कार्रवाई को भी इसी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है।प्राधिकरण की कार्रवाई से होटल संचालकों और निर्माण कार्य से जुड़े लोगों में हलचल है। वहीं, स्थानीय स्तर पर भी इस कार्रवाई को मसूरी में भवन निर्माण नियमों के पालन से जोड़कर देखा जा रहा है। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण के सहायक अभियंता अजय मलिक, अवर अभियंता अनुज पांडेय, अवर अभियंता अनुराग नौटियाल, सुपरवाइजर संजीव कुमार, उदय नेगी और इंद्र देव नौटियाल सहित कर्मचारी मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा।

मसूरी में वन्यजीव सप्ताह के समापन पर विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कार

भारतेन्दु संवाददाता, सुनील सोनकर



मसूरी। जंगल, वन्यजीव और प्रकृति की कहानी किताबों तक सीमित न रह जाए, इसके लिए मसूरी वन प्रभाग ने वन्यजीव सप्ताह के दौरान विद्यार्थियों को जागरूकता की गतिविधियों से जोड़ा। चित्रकला में बच्चों ने अपनी कल्पनाओं के रंगों से वन्यजीवों और जंगल की तस्वीर उकेरी तो निबंध और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उन्होंने प्रकृति, जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े सवालों के जवाब तलाशे। वन्यजीव सप्ताह के समापन पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया।मसूरी स्थित प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए अधिकारियों ने कहा कि वन्यजीव संरक्षण की शुरुआत बचपन से प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता पैदा करने से होती है।

बच्चों को जंगल और वन्यजीवों के महत्व की जानकारी देकर उन्हें भविष्य का पर्यावरण प्रहरी बनाया जा सकता है। वन्यजीव सप्ताह के अवसर पर मसूरी वन प्रभाग की ओर से

◆अधिकारियों ने कहा- प्रकृति संरक्षण में बच्चों की भूमिका अहम

आमजन और विद्यार्थियों में वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा तथा जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिए चित्रकला, निबंध, प्रश्नोत्तरी सहित जागरूकता आधारित प्रतियोगिताएं कराई गईं।

चित्रकला प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने वन्यजीवों, जंगलों और प्राकृतिक वातावरण को अपनी कल्पना के अनुसार कागज पर उतारा। वहीं निबंध प्रतियोगिता में बच्चों ने वन्यजीव संरक्षण की आवश्यकता, जंगलों के महत्व और पर्यावरण को होने वाले नुकसान जैसे विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विद्यार्थियों की वन एवं वन्यजीवों से संबंधित जानकारी को परखा गया। वन्यजीव सप्ताह के समापन समारोह में प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। सम्मान मिलने पर बच्चों में खासा उत्साह नजर आया।

शिक्षकों ने भी वन विभाग की इस पहल को विद्यार्थियों को प्रकृति से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में मसूरी वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी देवी प्रसाद बलूनी, मसूरी रेंज के वन क्षेत्राधिकारी महेंद्र सिंह चौहान, केम्प्टी रेंज की वन क्षेत्राधिकारी अमिता थपलियाल, विनोग रेंज की वन क्षेत्राधिकारी अंजलि, उप वन क्षेत्राधिकारी जयपाल सिंह रांगड़, वन दरोगा अभिषेक सजवाण, अटल उत्कृष्ट घनानंद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रवि उनियाल, सरस्वती शिशु मंदिर केम्प्टी के प्रधानाचार्य सहित वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षिकाएं और विद्यार्थी मौजूद रहे।

समारोह में अधिकारियों ने विद्यार्थियों को वन्यजीवों और वनों के संरक्षण के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जंगल केवल पेड़-पौधों का समूह नहीं हैं, बल्कि इनमें अनेक प्रकार के जीव-जंतु, पक्षी और वनस्पतियां मिलकर एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। किसी एक कड़ी के कमजोर होने का असर पूरे पर्यावरण पर पड़ता है। वक्ताओं ने कहा कि वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है।

जंगलों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने, वन्यजीवों के प्रति संवेदनशील व्यवहार करने और प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करने की आदत बचपन से विकसित की जानी चाहिए।अधिकारियों ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने घर, स्कूल और आसपास के लोगों को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करें। उन्होंने कहा कि आज का जागरूक विद्यार्थी भविष्य में प्रकृति संरक्षण का जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। बच्चों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश परिवार और समाज तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है।

मतदाता सूची सुधार अभियान शुरू

भारतेन्दु संवाददाता,पौड़ी गढ़वाल। मतदाता सूची को अधिक समावेशी, त्रुटिरहित और अद्यावधिक बनाने के लिए जनपद में विशेष अभियान शुरू किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत चलाए जा रहे इस अभियान में मतदाता सूची से छूटे पात्र नागरिकों के साथ नए, युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

अभियान के पहले चरण में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा वर्तमान मतदाता सूची की एसआईआर से पूर्व की मतदाता सूची से तुलना की जाएगी। इस दौरान ऐसे मतदाताओं को चिन्हित किया जाएगा, जिनके नाम पूर्व की सूची में दर्ज थे, लेकिन किसी कारणवश वर्तमान सूची में शामिल नहीं हैं।

चिन्हित मतदाताओं की सूची तैयार कर प्रत्येक मतदान केंद्र पर 8 से 10 अक्टूबर तक तीन दिवसीय विशेष शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में बीएलओ नए, युवा और पहली बार मतदान करने वाले पात्र नागरिकों को नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी देने के साथ आवश्यक सहयोग भी करेंगे। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं का भी पुन: सत्यापन किया जाएगा।

इसके लिए 12 से 20 अक्टूबर तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इस दौरान संबंधित मतदाता की वर्तमान स्थिति की जानकारी जुटाई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति 1 अक्टूबर 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए पात्र पाया जाता है तो उसे फार्म-6 के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी।

जाखणीधार में अभिमुखीकरण संवाद एवं विकास संकल्प सेतु सम्मेलन आयोजित

भारतेन्दु संवाददाता, नई टिहरी। जाखणीधार ब्लॉक मुख्यालय टिपरी में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक दिवसीय अभिमुखीकरण संवाद एवं विकास संकल्प सेतु सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में पंचायत प्रतिनिधियों को स्वच्छ भारत मिशन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित पंचायतों से जुड़े विभिन्न विषयों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक किशोर उपाध्याय ने किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने और विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

ब्लॉक प्रमुख राजेश नौटियाल



की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवैधानिक पद पर 25 वर्ष पूरे किए हैं और जनकल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है।

शिवालिक एजुकेशन वेलफेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स सोसाइटी देहरादून के सचिव उत्तम रावत और मास्टर ट्रेनरों ने जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों तथा उपप्रधानों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान सूचना का अधिकार, सेवा का अधिकार, सिटीजन चार्टर, ओसीआर, केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की नौ थीम तथा पंचायत सूचकांक सहित विभिन्न विषयों की विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई वि0/यां0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर
Office of the Excutive Engineer,
Ty. E/M Division, P.W.D., Gopeshwar (Uttarakhand)
Phone/Fax-01372-253454, E-mail-eeem.pwd.gopeshwer@gmail.com
पत्रांक :-1394/निविदा दिनांक 03-10-2026

निष्प्रयोज्य मशीनों की नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड की ओर से लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड की निष्प्रयोज्य मशीन जैसा है, जहां है (As it is, Where it is) के आधार पर सार्वजनिक नीलामी हेतु निविदा (सील्ड बिड) आमंत्रित की जाती है। सील्ड निविदा दिनांक 23.10.2026 को आमंत्रित की जाती है। नीलामी प्रपत्र दिनांक 09.10.2026 से दिनांक 22.10.2026 तक किसी भी कार्यदिवस में निम्न कार्यालयों से प्राप्त किये जा सकते है तथा दिनांक 23.10.2026 को अपरान्ह 3:00 बजे तक इन्हीं कार्यालयों में डाले जा सकते हैं।

1 कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, 11वां वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
2 कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई वि0/ या0 खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर।
3 कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, वि0/ यां0 खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	धरोहर राशि (☐)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (☐)
1.	अस्थाई वि0/यॉ0 खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर की निष्प्रयोज्य मशीन की नीलामी।	☐1,50,000.00	☐1000.00 + G.S.T. 18%

सील्ड निविदा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 24.10.2026 को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति द्वारा अपराह्न 12:00 बजे खोली जाएगी। नीलामी की शर्तें निविदा प्रपत्रों में देखी जा सकती है। किसी भी निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित होगा।

सड़क परियोजनाओं के लिए पेड़ों की कटाई की भरपाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा प्रस्ताव

विकास कार्यों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन साधने को पंजाब सरकार से मांगी ठोस कार्ययोजना

भारतेंदु संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में लगातार घटते वन क्षेत्र और सड़क परियोजनाओं के लिए पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने पंजाब सरकार से उन क्षेत्रों में क्षतिपूर्ति पौधारोपण के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मांगा है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को सड़क निर्माण के लिए जमीन की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में वन क्षेत्र लगातार कम होने और पौधारोपण की योजनाओं के प्रभावी तरीके से लागू नहीं होने पर चिंता जताई। पीठ ने यह जानने का प्रयास किया कि सड़क परियोजनाओं के लिए जिन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई की जाती है, वहां उनकी भरपाई के लिए पौधारोपण करने की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि विकास परियोजनाओं के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पांच किलोमीटर के दायरे में जमीन को लेकर सवाल : सुनवाई के दौरान एनएचएआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर लगातार रोक लगा रखी है। इसके कारण सार्वजनिक महत्व की कई सड़क परियोजनाओं के निर्माण में परेशानी आ रही है। उन्होंने कहा कि पेड़ों की कटाई की भरपाई के लिए पौधारोपण करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

तुषार मेहता ने कहा कि पंजाब सीमावर्ती राज्य है और रणनीतिक दृष्टि से कई सड़कों का निर्माण जरूरी है। ऐसे में केवल पेड़ों की कटाई के कारण आवश्यक सड़क परियोजनाओं को लंबे समय तक नहीं रोका जा सकता। उन्होंने अदालत को बताया कि संबंधित परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय नियमों के तहत क्षतिपूर्ति पौधारोपण



की व्यवस्था की जाती है।

इस पर पीठ ने पूछा कि जिन स्थानों पर पेड़ों की कटाई की जाती है, वहां से पांच किलोमीटर के दायरे में क्षतिपूर्ति पौधारोपण के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाती है या नहीं। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि कुछ मामलों में इस दायरे में जमीन उपलब्ध हो जाती है, जबकि कई मामलों में पांच किलोमीटर के भीतर उपयुक्त भूमि मिलना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में दूसरी जगह पौधारोपण किया जाता है।

सड़क परियोजनाएं प्रभावित होने पर भी चिंता : एनएचएआई की ओर से अदालत को बताया गया कि हाई कोर्ट के निर्देशों के कारण सार्वजनिक परियोजनाओं पर असर पड़ रहा है। पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं मिलने के कारण सड़क निर्माण के कई काम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इससे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में देरी हो रही है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह उन क्षेत्रों में क्षतिपूर्ति पौधारोपण के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव अदालत के समक्ष पेश करे, जहां सड़क निर्माण के लिए एनएचएआई को जमीन की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचा विकास के बीच संतुलन कायम करने के लिए व्यावहारिक व्यवस्था जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को याचिका की प्रति पंजाब सरकार को उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। साथ ही राज्य सरकार से मामले में जवाब मांगा गया है। अदालत इस मामले में आगे की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पेश किए जाने वाले प्रस्ताव और पौधारोपण की व्यवस्था पर विचार करेगी।

पंजाब में केवल 3.67 प्रतिशत क्षेत्र वन : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 24 दिसंबर 2025 को पंजाब में लगातार घटते वन क्षेत्र पर चिंता जताई थी। हाई कोर्ट ने विभिन्न परियोजनाओं और अन्य गतिविधियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी। बाद में परिस्थितियों के अनुसार इस आदेश में समय-समय पर बदलाव भी किया गया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पंजाब के कुल क्षेत्रफल का केवल 3.67 प्रतिशत हिस्सा ही वन क्षेत्र है। यह राजस्थान के 4.87 प्रतिशत वन क्षेत्र से भी कम है।

राजोआना की फांसी पर केंद्र का विरोध सुप्रीम कोर्ट में 28 अक्टूबर को होगी सुनवाई



भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी पूर्व पंजाब पुलिस कांस्टेबल बलवंत सिंह राजोआना की मृत्युदंड की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग का केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। केंद्र ने कहा कि पंजाब की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए राजोआना की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलना फिलहाल अनुकूल नहीं होगा।

केंद्र के इस रुख के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब वह राजोआना की याचिका पर उसके गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करेगा। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ में न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह भी शामिल हैं।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सालिसिटर जनरल केएम नटराज ने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार राजोआना की सजा कम करने की मांग का विरोध करती है। उन्होंने पंजाब की मौजूदा स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि इस समय मृत्युदंड को उम्रकैद में बदलने का निर्णय लेना उचित नहीं होगा।

इस पर पीठ ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने सजा कम करने का विरोध कर दिया है तो अब अदालत मामले की मेरिट पर सुनवाई करेगी। केंद्र की ओर से तैयारी के लिए समय मांगे जाने पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख तय की।

राजोआना की याचिका का मुख्य आधार उसकी दया याचिका पर लंबे समय से फैसला नहीं होना है। राजोआना की ओर से कहा गया है कि उसकी दया याचिका वर्ष 2012 से राष्ट्रपति के पास लंबित है। 14 साल से अधिक समय तक मृत्युदंड की अनिश्चितता में रहने के कारण उसे मानसिक पीड़ा और असहनीय तनाव का सामना करना पड़ा है।

याचिका में दलील दी गई है कि दया याचिका पर फैसला लेने में अत्यधिक देरी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से जुड़े मुद्दे को जन्म देती है। राजोआना के वकील सुप्रीम कोर्ट के उन पूर्व फैसलों का हवाला भी दे सकते हैं, जिनमें दया याचिका पर असाधारण देरी को मृत्युदंड को उम्रकैद में बदलने का आधार माना गया है।

बलवंत सिंह राजोआना को 31 अगस्त 1995 को चंडीगढ़ स्थित पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर हुए आत्मघाती बम विस्फोट मामले में दोषी ठहराया गया था। विस्फोट में तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह समेत 17 लोगों की मौत हुई थी। जांच में राजोआना को मामले में बैकअप बम हमलावर बताया गया था। विशेष अदालत ने जुलाई 2007 में राजोआना को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। इसके बाद पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 2010 में उसकी सजा बरकरार रखी।

मोहाली अदालत ने बीकेआई से जुड़े तीन समेत चार आरोपितों को भगोड़ा किया घोषित



भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) से जुड़े तीन आरोपितों समेत चार लोगों को मोहाली की विशेष एनआइए अदालत ने भगोड़ा घोषित किया है। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद आरोपितों के नहीं मिलने पर अदालत ने उनके खिलाफ उद्घोषणा जारी की। अदालत ने चारों को 16 नवंबर 2026 को पेश होने के निर्देश दिए हैं।

भगोड़ा घोषित किए गए आरोपितों में जसविंदर सिंह उर्फ बागी उर्फ मन्नू अगवान उर्फ जस्सा, करण सिंह उर्फ अभी, मलविंदर सिंह उर्फ सुख और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी नवाशहरियां शामिल हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, इन आरोपितों के खिलाफ आतंकी साजिश, हथियारों की तस्करी और देश-विरोधी गतिविधियों से जुड़े गंभीर आरोप हैं।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने इस मामले में 22 मई 2025 को प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में प्रतिबंधित आतंकी संगठन बीकेआई से जुड़े नेटवर्क की गतिविधियों की जांच की जा रही है। आरोपितों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आर्म्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष आए दस्तावेजों के अनुसार, जसविंदर सिंह उर्फ बागी को बीकेआई का सक्रिय सदस्य बताया गया है। उस पर आतंकी साजिश रचने, लोगों में भय पैदा करने और देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। जांच में उसके नेटवर्क के हथियारों की तस्करी, लक्षित हत्या और जबरन वसूली जैसी गतिविधियों से जुड़े होने की भी बात सामने आई है।

करण सिंह उर्फ अभी और मलविंदर सिंह उर्फ सुख के नाम भी इसी नेटवर्क से जुड़े मामले में सामने आए हैं। दोनों पर जसविंदर सिंह और उसके साथियों के साथ मिलकर आपराधिक तथा देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। सुरक्षा एजेंसियां पंजाब में आतंकी संगठनों और आपराधिक गिरोहों के बीच संभावित संपर्कों की भी जांच कर रही हैं।

मतदाता सूची सुधार के लिए कर्ण बीर सिद्धू ने समय बढ़ाने की मांग की

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से छूट गए पात्र लोगों को नाम जुड़वाने का अवसर देने के लिए हर मतदान केंद्र पर विशेष शिविर लगाने की मांग की गई है। पंजाब के पूर्व विशेष मुख्य सचिव कर्ण बीर सिंह सिद्धू ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा को पत्र भेजकर एसआईआर की प्रक्रिया कम से कम दो सप्ताह बढ़ाने का आग्रह किया है। पत्र की प्रति मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी भेजी गई है। सिद्धू ने कहा कि छूटे हुए पात्र मतदाताओं के लिए ऑनलाइन और कागजी दोनों माध्यमों से फार्म-6 भरने की सुविधा जारी रहनी चाहिए। उन्होंने पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी में स्पष्ट सार्वजनिक सूचना जारी करने की मांग की, ताकि किसी पात्र नागरिक को नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को लेकर भ्रम न रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं और बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर भी मतदाताओं की सहायता कर रहे हैं। इसी तरह पंजाब में भी विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। सिद्धू ने बीएलओ को घर-घर जाकर छूटे मतदाताओं की जानकारी जुटाने और मतदाता सूचियां राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के प्रतिनिधियों के साथ साझा करने की मांग की।

रेपो रेट बढ़ने से एमएसएमई पर बढ़ेगा ब्याज का बोझ

रेपो रेट बढ़ोतरी से कारोबारियों की लागत बढ़ने और त्योहारी मांग प्रभावित होने की आशंका

भारतेंदु संवाददाता, लुधियाना। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से रेपो रेट में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी कर इसे 5.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत किए जाने पर वर्ल्ड एमएसएमई फोरम ने चिंता जताई है। फोरम ने केंद्रीय वित्त मंत्री से हस्तक्षेप कर इस फैसले के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा करने की मांग की है।

वर्ल्ड एमएसएमई फोरम के अध्यक्ष बादिश जिंदल ने कहा कि महंगाई पर नियंत्रण जरूरी है, लेकिन वर्तमान में महंगाई पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, ऊर्जा लागत, भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान जैसे आपूर्ति पक्ष के कारणों का अधिक प्रभाव है। ऐसे में ब्याज दर बढ़ाने से आयातित महंगाई पर सीमित असर पड़ सकता है, जबकि उद्योगों, कारोबारियों और उपभोक्ताओं के लिए कर्ज महंगा हो जाएगा।



फोरम के अनुसार रेपो रेट में बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है, जब देश त्योहारी सीजन में प्रवेश कर रहा है। दीपावली से पहले उपभोक्ता वस्तुओं, वाहन, आवास, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और औद्योगिक उत्पादों की मांग बढ़ती है। ब्याज दर बढ़ने से गृह ऋण, वाहन ऋण, एमएसएमई ऋण और कार्यशील पूंजी की लागत बढ़ सकती है। इससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति और कारोबारियों के नए निवेश पर असर पड़ने की आशंका है।

फोरम ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सकल घरेलू उत्पाद में करीब 30 प्रतिशत और निर्यात में लगभग 45 प्रतिशत योगदान देता है तथा 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ऐसे में इस क्षेत्र को सस्ती और आसानी से उपलब्ध वित्तीय सुविधा मिलना जरूरी है।

बादिश जिंदल ने कहा कि ब्याज दर बढ़ने से एमएसएमई की उत्पादन लागत बढ़ सकती है। इससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित होने के साथ विस्तार और रोजगार सृजन की योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है। खासकर छोटी इकाइयों के लिए कर्ज की लागत में मामूली वृद्धि भी नकदी प्रवाह पर दबाव बढ़ा सकती है।

फोरम ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि बैंक आरबीआई की 25 आधार अंक की बढ़ोतरी का पूरा भार कर्जदारों पर डालते हैं तो एक करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी सुविधा लेने वाले विनिर्माण एमएसएमई पर सालाना करीब 25 हजार रुपये का अतिरिक्त ब्याज भार पड़ सकता है। वहीं पांच करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी सीमा वाली मध्यम आकार की इकाई पर यह अतिरिक्त बोझ करीब 12.5 लाख रुपये सालाना तक पहुंच सकता है।

दोसांझ कलां में दीवार पर खालिस्तान समर्थक नारे, जांच में जुटी पुलिस



भारतेंदु संवाददाता, जालंधर। पंजाबी गायक और अभिनेता दलजीत दोसांझ के पैतृक गांव दोसांझ कलां के पास एक मकान की दीवार पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि विवादित नारे दलजीत दोसांझ के पैतृक घर की दीवार पर लिखे गए हैं। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह दावा सही नहीं है।

बताया जा रहा है कि गोराया के नजदीक स्थित दोसांझ कलां में कुछ लोगों ने एक मकान की दीवार पर स्प्रे से विवादित नारे लिख दिए। घटना की जानकारी मिलने के बाद दीवार पर लिखे गए नारों को मिटा दिया गया। हालांकि, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने लगा।

मामले में सामने आई जानकारी के अनुसार जिस मकान की दीवार पर नारे लिखे गए हैं, वह दलजीत दोसांझ का पैतृक घर नहीं है। स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के मुताबिक नारे उनके घर के बजाय किसी अन्य व्यक्ति के मकान की दीवार पर लिखे गए थे।

इसके बावजूद वायरल वीडियो के साथ यह दावा किया जा रहा है कि नारे दलजीत दोसांझ के घर के बाहर लिखे गए हैं। इससे सोशल मीडिया पर भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। घटना और वायरल दावे में अंतर होने के कारण वीडियो साझा करते समय तथ्यों की पुष्टि करने की जरूरत बताई जा रही है।

डंपिंग ग्राउंड में रिश्वत का खेल, ठेकेदार से 14 लाख मांगने वाला अधिकारी गिरफ्तार

डंपिंग ग्राउंड में रिश्वत का खेल, ठेकेदार से 14 लाख मांगने वाला अधिकारी गिरफ्तार



भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड में कचरा निपटान के काम को लेकर रिश्वत मांगने के मामले में सीबीआई ने बुधवार को निगम के अधिकारी शक्ति शर्मा को ट्रैप लगाकर गिरफ्तार किया। आरोप है कि ठेकेदार से उसकी बकाया राशि जारी करने के एवज में 14 लाख रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। ठेकेदार ने इसकी शिकायत सीबीआई से की थी, जिसके बाद जांच एजेंसी ने कार्रवाई की।

जानकारी के अनुसार, डंपिंग ग्राउंड में जेसीबी के माध्यम से कचरे की खुदाई कर उसे उठाने का काम चल रहा है। ठेकेदार का हर महीने करीब 10 लाख रुपये का बिल बनता है। आरोप है कि इस भुगतान के बदले हर महीने एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। ठेकेदार से कुल 14 लाख रुपये की मांग की गई थी। निगम ने डंपिंग ग्राउंड में कचरा उठाने के लिए एक दर्जन से अधिक जेसीबी मशीनें लगा रखी हैं।

सीबीआई को आशंका है कि रिश्वत के इस खेल में नगर निगम के कई बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, सेनेटरी विंग के अलावा एमओएच और इंजीनियरिंग विभाग के कुछ अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। सीबीआई अधिकारियों की कॉल डिटेल और अन्य रिकॉर्ड खंगालने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि सीबीआई एक अन्य अधिकारी के खिलाफ भी ट्रैप की कार्रवाई करने की तैयारी में थी, लेकिन किसी कारणवश यह कार्रवाई सफल नहीं हो सकी।

मैड संधू हत्याकांड में गुजरात से दो आरोपी गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, अमृतसर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू (मधु सूदन) हत्याकांड में अमृतसर पुलिस ने अहम सफलता हासिल की है। अहमदाबाद अपराध शाखा के सहयोग से पंजाब पुलिस ने गुजरात से दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब हत्या की साजिश, मुख्य हमलावरों और वारदात में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों में परविंदर प्रसाद उर्फ परमिंदर काका शामिल है। उससे पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हत्या की योजना किसने बनाई और हमलावरों को किसने निर्देश दिए। मामले में एक अन्य आरोपित की गिरफ्तारी बाकी है, जबकि पनाह देने के आरोप में दो लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

एमओएच विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप, कैंथ ने जांच की मांग की



भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम के मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ (एमओएच) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद पूर्व उपमहापौर सतीश कैंथ ने प्रशासक गुलाबचंद कटारिया को पत्र लिखकर स्वतंत्र जांच की मांग की है। कैंथ ने आरोप लगाया कि विभाग लंबे समय से भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों को लेकर सवालों के घेरे में है, लेकिन पूर्व में की गई शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

कैंथ ने पत्र में कहा कि चंडीगढ़ की सिविल सोसायटी, गैर सरकारी संगठनों और पार्षदों की ओर से डंपिंग साइट पर होने वाले खर्च और टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर कई बार शिकायतें की गई हैं। इसके बावजूद संबंधित मामलों में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।

उन्होंने कहा कि अब सेनेटरी इंस्पेक्टर से जुड़े पांच लाख रुपये की रिश्वत के मामले के सामने आने के बाद एमओएच विभाग की कार्यप्रणाली पर फिर सवाल उठ रहे हैं। कैंथ के अनुसार, निगम में इस बात की चर्चा है कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी कथित गतिविधियों की जानकारी थी। ऐसे में यह तय किया जाना चाहिए कि यदि अनियमितताएं हुईं तो उनकी जिम्मेदारी किसकी है।

पूर्व उपमहापौर ने कहा कि नगर निगम जनता से प्राप्त करों से संचालित होता है और सार्वजनिक धन का इस्तेमाल पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए।

अनिल मदान बने चंडीगढ़ टेंट एसोसिएशन अध्यक्ष

कारोबारियों की समस्याएं सुलझाने का दिया भरोसा

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। सिटी ब्यूटीफुल टेंट एसोसिएशन की सेक्टर-38 में आयोजित जनरल हाउस की बैठक में अनिल मदान को सर्वसम्मति से एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया। बैठक में नई कार्यकारिणी का भी सर्वसम्मति से गठन किया गया। सदस्यों ने सभी पदों के लिए सहमति जताते हुए नई टीम को जिम्मेदारी सौंपी।

अध्यक्ष चुने जाने के बाद अनिल मदान ने सभी सदस्यों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सदस्यों ने उन पर जो विश्वास जताया है, वह उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि टेंट कारोबार से जुड़े लोगों की समस्याओं और मांगों को प्रमुखता से उठाना उनकी प्राथमिकता रहेगी।

मदान ने कहा कि शहर में टेंट कारोबारियों को समय-समय पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए एसोसिएशन प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों से मुलाकात करेगी। कारोबारियों की जायज मांगों को उचित मंच पर उठाकर उनके समाधान का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि एसोसिएशन को मजबूत और संगठित बनाना भी उनकी प्राथमिकता है। सभी सदस्यों को साथ लेकर कारोबारियों के हितों की रक्षा के लिए काम किया जाएगा। इसके साथ ही एसोसिएशन सामाजिक और जनकल्याण से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी करेगी।

नई कार्यकारिणी में जगजीत सिंह को चेयरमैन बनाया गया। अनिल मदान (जन्नत टेंट) को अध्यक्ष, संजय को उपाध्यक्ष, जतिंदर राय को वित्त सचिव, सतीश कुमार को महासचिव और सौरभ बंसल को सचिव चुना गया। रिंटकू को उप सचिव, धर्मिंदर



कुमार को सलाहकार, करण कुमार को कानूनी सलाहकार तथा दिनेश कुमार को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। राजू को भी कार्यकारिणी में शामिल किया गया।

अनिल मदान ने कहा कि नई कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों के सहयोग से एसोसिएशन को नई दिशा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संगठन के सामने आने वाली समस्याओं पर सामूहिक रूप से चर्चा कर समाधान निकाला जाएगा।

समन्वय 2027 चुनाव से पहले कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं को साथ लाने की कवायद की तेज

परगट-वड़िंग मुलाकात से कांग्रेस में बढ़ी एकजुटता



भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह की ताजपोशी के बाद पार्टी के भीतर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। बुधवार को पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने दिल्ली में परगट सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष पद में बदलाव के बाद दोनों नेताओं की यह पहली महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है। यह बैठक ऐसे समय हुई है, जब कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने और नेताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रही है।

जानकारी के अनुसार, राजा वड़िंग नए प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह को बधाई देने उनके आवास पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। इस दौरान पंजाब कांग्रेस की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों, संगठन की गतिविधियों और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। हालांकि, मुलाकात में किन मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इसके बावजूद दोनों नेताओं की मुलाकात को कांग्रेस के भीतर एकजुटता के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

मुलाकात के दौरान परगट सिंह ने राजा वड़िंग को गुरुवार को अमृतसर आने का न्योता भी दिया। नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर परगट सिंह आठ अक्टूबर को पंजाब दौरे की शुरुआत अमृतसर से करने जा रहे हैं। वह श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर भी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किए जाने की उम्मीद है।

इस कार्यक्रम में पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। पार्टी की कोशिश है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर परगट सिंह की पहली बड़ी गतिविधि में पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को साथ लाकर संगठन में एकजुटता का संदेश दिया जाए। ऐसे में राजा वड़िंग की संभावित मौजूदगी इस कार्यक्रम के राजनीतिक महत्व को और बढ़ा सकती है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद में बदलाव के बाद अमृतसर कार्यक्रम ऐसा पहला बड़ा अवसर हो सकता है, जब पूर्व अध्यक्ष राजा वड़िंग और नए अध्यक्ष परगट सिंह एक साथ नजर आएं। कांग्रेस के भीतर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर राजनीतिक चर्चाओं के बीच दोनों नेताओं की मुलाकात और फिर अमृतसर आने का न्योता संगठन में आपसी समन्वय बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

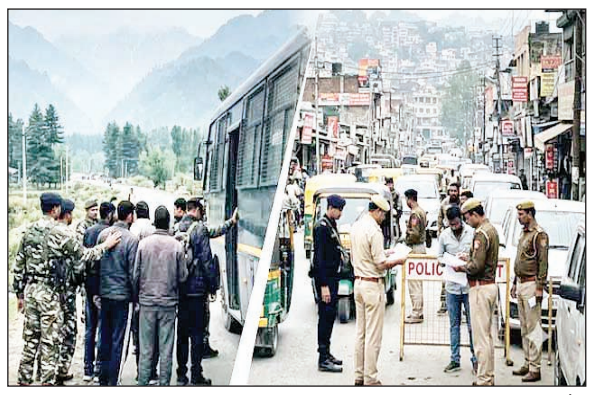
2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के साथ वरिष्ठ नेताओं और अलग-अलग गुटों को एक मंच पर लाने की है। पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के अलावा भाजपा और अकाली दल भी चुनावी तैयारियों में जुटे हैं।

कश्मीर से तीन दिन में 310 बांग्लादेशी भेजे गए वापिस

जम्मू में भी बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाने की उठी मांग

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। बुधवार को 160 बांग्लादेशियों को विशेष विमान से असम के कुंभीग्राम भेजा गया। इनमें 116 पुरुष और 44 महिलाएं शामिल हैं। वहां बीएसएफ की निगरानी में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन्हें बांग्लादेशी अधिकारियों के हवाले किया जाएगा। इससे पहले सोमवार को 150 बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल के बागडोगरा भेजा गया था। इस तरह तीन दिनों में कश्मीर से कुल 310 बांग्लादेशियों को वापस भेजा जा चुका है।

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, वापस भेजे गए बांग्लादेशी कश्मीर के विभिन्न इलाकों में मजदूरी और अन्य छोटे-मोटे काम कर रहे थे। आतंकियों की ओर से दूसरे राज्यों से आए श्रमिकों को निशाना बनाए जाने की धमकियों के बाद सुरक्षा



एजेंसियों ने श्रमिकों का पंजीकरण शुरू किया था। इसी दौरान उनके दस्तावेजों की जांच में कई तरह की विसंगतियां सामने आईं। इसके बाद एजेंसियों ने बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और उनके कश्मीर पहुंचने के रास्तों की भी पड़ताल शुरू की।

कश्मीर में हुई इस कार्रवाई के बाद अब जम्मू संभाग में भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग उठने लगी है। सामाजिक संगठनों का कहना है कि जम्मू और आसपास के क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग रह रहे हैं, जो अपनी पहचान छिपाकर मजदूरी और सब्जी बेचने जैसे काम कर रहे हैं। संगठनों ने प्रशासन से इन लोगों के दस्तावेजों की जांच करने और संदिग्ध मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।

जम्मू में रोहिंग्याओं की बस्तियों पर भी उठे सवाल : बांग्लादेशियों के अलावा जम्मू में रोहिंग्याओं की बस्तियों को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार जम्मू-कश्मीर में 15 हजार से अधिक रोहिंग्या रह रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या जम्मू शहर और आसपास के इलाकों में होने की बात कही जाती है। इसी वर्ष अगस्त में जनसांख्यिकीय बदलाव का अध्ययन करने जम्मू पहुंची केंद्र की उच्चस्तरीय समिति के सामने भी स्थानीय संगठनों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की मौजूदगी को लेकर चिंता जताई थी।

समिति से जुड़े दस्तावेज में जम्मू-कश्मीर में 504 बांग्लादेशियों के रहने का उल्लेख किया गया है। हालांकि स्थानीय संगठनों का दावा है कि दस्तावेजों की विस्तृत जांच और पहचान सत्यापन के बाद वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक सामने आ सकती है।

बसाने में मदद करने वालों की भी हो पहचान : जम्मू-कश्मीर मामलों के जानकार डॉ. अजय च्रंगू ने कहा कि बांग्लादेशियों को वापस भेजने के साथ उन लोगों की भी पहचान होनी चाहिए, जिन्होंने उन्हें जम्मू-कश्मीर में बसाने में मदद की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के राशन कार्ड बनवाने के साथ बिजली और पानी के कनेक्शन तक उपलब्ध करवाए गए। ऐसे मामलों की जांच कर जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए।

जम्मू में भी अभियान चलाने की मांग : विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने गृह मंत्रालय और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल का आभार जताते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र को घुसपैठियों से पूरी तरह मुक्त करने के लिए प्रभावी अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अन्य राज्य भी इसी तरह तेजी से कार्रवाई करेंगे।

लद्दाख में देश की पहली हिम तेंदुआ सफारी शुरू, संरक्षण संग रोजगार को मिलेगा बढ़ावा



भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। लद्दाख में अब पर्यटक हिम तेंदुए समेत हिमालयी भूरे भालू, भेड़िये और अन्य वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में करीब से देख सकेंगे। लेह में देश की पहली उच्च हिमालयी हिम तेंदुआ वन्यजीव सफारी शुरू की गई है। इसका उद्देश्य वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय समुदायों को संरक्षण और रोजगार से जोड़ना है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को लेह में सफारी का शुभारंभ किया।

पहले चरण में सफारी का संचालन रुमबक, शांग और उले क्षेत्रों में किया जाएगा। बाद में इसे लद्दाख के अन्य वन्यजीव क्षेत्रों तक विस्तारित करने की योजना है। प्रशिक्षित स्थानीय चालक और वन्यजीव गाइड छह खुले वाहनों के माध्यम से पर्यटकों को निर्धारित क्षेत्रों में ले जाएंगे। सफारी के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक आवास में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करने का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

लद्दाख में बड़ी संख्या में हिम तेंदुए पाए जाते हैं। देशभर में इनकी संख्या करीब 718 बताई गई है। हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक हिम तेंदुओं को उनके प्राकृतिक आवास में देखने के लिए लद्दाख पहुंचते हैं। ऐसे में सफारी को व्यवस्थित रूप देने से पर्यटन के साथ संरक्षण गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

उपराज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। स्थानीय समुदायों को भी इसमें सक्रिय भागीदार बनाया जाना चाहिए। वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय लोगों की आजीविका के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्थानीय गाइड को हिम तेंदुए की साइटिंग से आय और महिलाओं को संरक्षण आधारित हस्तशिल्प से लाभ मिलना चाहिए।

करीब 20 स्थानीय युवाओं को पक्षियों की पहचान, पक्षी-दर्शन और वन्यजीवों की पहचान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें दूरबीन उपलब्ध कराने के साथ प्रमुख पक्षी-दर्शन स्थलों पर सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे स्थानीय युवाओं के लिए वन्यजीव गाइड, पक्षी गाइड और प्रकृति व्याख्याकार के रूप में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

न्यूज ब्रीफ

बड़ी ब्राह्मणा में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत

भारतेंदु संवाददाता, सांबा। सांबा जिले के बड़ी ब्राह्मणा इलाके में गुरुवार सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसा बड़ी ब्राह्मणा पुलिस थाने के पास हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को मृत पाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक की पहचान झारखंड निवासी 22 वर्षीय लुलैन सुरैन के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे में शामिल वाहन और उसके चालक की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। दुर्घटना के कारणों की भी जांच की जा रही है।

सेब के पेड़ से गिरा युवक, 13 दिन बाद जिंदगी की जंग हारा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के बेहिबाग इलाके में सेब तोड़ते समय पेड़ से गिरकर घायल हुए 17 वर्षीय युवक की गुरुवार को मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि युवक 13 दिन पहले सेब तोड़ते समय पेड़ से गिर गया था। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए श्रीनगर भेज दिया गया। करीब 13 दिन तक अस्पताल में उपचार चलने के बावजूद गुरुवार को उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बेहिबाग, कुलगाम निवासी समीर हुसैन (17) के रूप में हुई है। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

मेंढर में एलओसी के पास मिली बारूदी सुरंग सेना ने की नष्ट

भारतेंदु संवाददाता, पुंछ। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर उपमंडल में नियंत्रण रेखा के पास सेना के जवानों ने गुरुवार को एक बारूदी सुरंग का पता लगाकर उसे सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, बालाकोट अग्रिम क्षेत्र में नियमित गश्त के दौरान जवानों की नजर बारूदी सुरंग पर पड़ी। इसके बाद बम निरोधक दल को मौके पर बुलाया गया और सुरक्षात्मक उपायों के साथ सुरंग को नष्ट किया गया। अधिकारियों ने बताया कि घुसपैठ रोधी व्यवस्था के तहत अग्रिम क्षेत्रों में बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। बारिश के दौरान पानी के बहाव से कई बार ये सुरंगें अपने स्थान से खिसक जाती हैं। ऐसे में किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा बल समय-समय पर तलाशी अभियान चलाकर इन्हें खोजकर नष्ट करते हैं।

गांदरबल में सेवानिवृत्त कर्मचारी घर में फंदे से लटके मिले

भारतेंदु संवाददाता, गांदरबल। गांदरबल जिले के वुस्सान इलाके में गुरुवार को पुष्पकृषि विभाग के 62 वर्षीय सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने घर में मृत पाए गए। पुलिस के अनुसार, वह फंदे से लटके मिले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कानूनी व चिकित्सकीय प्रक्रिया शुरू की। मृतक की पहचान फिलहाल उजागर नहीं की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

बारामूला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

भारतेंदु संवाददाता, बारामूला। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर गुरुवार को बारामूला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बारामूला विधायक इरफान हफीज लोन, वरिष्ठ कांग्रेस नेता फैयाज अहमद मीर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मीर इकबाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने मांग के समर्थन में नारेबाजी की और डीसी कार्यालय की ओर बढ़ने का प्रयास किया। हालांकि, पुलिस और सुरक्षाबलों ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवान तैनात रहे। अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान स्थिति पर लगातार नजर रखी गई और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।

गंडोह में अवैध खनन पर कार्रवाई, टिपर जेसीबी जब्त, 60,336 रुपए जुर्माना



खनिज परिवहन में नियम उल्लंघन पर विभाग ने अलग-अलग आर्थिक दंड किए तय

भारतेंदु संवाददाता, डोडा। अवैध खनन और खनिज सामग्री के अनधिकृत परिवहन के खिलाफ जारी अभियान के तहत डोडा पुलिस ने गंडोह थाना क्षेत्र के कहारा इलाके में कार्रवाई करते हुए एक टिपर और जेसीबी मशीन जब्त की है। दोनों वाहनों को अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के बाद कब्जे में लिया गया। खनन विभाग ने दोनों मामलों में कुल 60,336 रुपये का जुर्माना लगाया है।

पुलिस के अनुसार, पुलिस पोस्ट कहारा की टीम ने प्रभारी अधिकारी के नेतृत्व में क्षेत्र में जांच के दौरान एक टिपर और जेसीबी को रोका। जांच में दोनों के अवैध खनन और खनिज सामग्री के अनधिकृत परिवहन से जुड़े होने की बात सामने आई।

जब्त टिपर का पंजीकरण नंबर जेके06ए-3405 है। यह इरशाद हुसैन पुत्र मोहम्मद रुस्तम शेख से संबंधित है। टिपर में करीब छह मीट्रिक टन नाले के पत्थर अवैध रूप से ले जाए जा रहे थे। इस पर खनन विभाग ने 15,036 रुपये का जुर्माना लगाया।

वहीं, जेसीबी का पंजीकरण नंबर जेके06बी-1626 है, जो अमजद हुसैन पुत्र ताहिर हुसैन से संबंधित है। जांच में जेसीबी करीब 50 मीट्रिक टन नाले के पत्थरों से जुड़ी अवैध खनन गतिविधि में शामिल पाई गई। विभाग ने इस मामले में 45,300 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया।

पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर पुलिस पोस्ट कहारा में रखा है।

जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों में पीएनजी-सीएनजी नेटवर्क का होगा विस्तार



भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू-कश्मीर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति-2026 अधिसूचित कर दी है। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश के सभी 20 जिलों में चरणबद्ध तरीके से पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) का नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इससे घरेलू उपभोक्ताओं, दुकानों, उद्योगों और परिवहन क्षेत्र को प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने का रास्ता साफ होगा।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद अधिसूचित नीति का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन की पहुंच बढ़ाने के साथ औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा की उपलब्धता मजबूत करना है। जम्मू-कश्मीर के गैस बुनियादी ढांचे को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने में गुरदासपुर-जम्मू गैस पाइपलाइन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

नीति को अंतिम रूप देने और इसके क्रियान्वयन में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए सरकार ने छह अप्रैल 2026 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित की थी। समिति में वित्त, लोक निर्माण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आवास एवं शहरी विकास, उद्योग एवं वाणिज्य, ग्रामीण विकास और श्रम एवं रोजगार विभागों के प्रशासनिक सचिव शामिल थे। समिति को विभागों के बीच समन्वय, परियोजनाओं की मंजूरी में तेजी और बाधाओं के समाधान की जिम्मेदारी दी गई थी।

नीति में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को गैस नेटवर्क से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है। कठुआ, सांबा और पुलवामा सहित औद्योगिक क्षेत्रों में गैस कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी जाएगी। पाइपलाइन बिछाने के लिए रास्ते के अधिकार से जुड़े नियमों को मानकीकृत करने के साथ एकल खिड़की और समयबद्ध मंजूरी की व्यवस्था भी की गई है।

सेब की कटाई से शोपियां में बढ़ा जाम, सड़कों पर ट्रकों की लगी कतारें



भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के प्रमुख सेब उत्पादक जिले शोपियां में सेब की कटाई का मौसम चरम पर पहुंचने के साथ ही यातायात जाम की समस्या भी बढ़ गई है। बागों से सेब शोपियां फल मंडी तक पहुंचाने के लिए रोजाना बड़ी संख्या में ट्रक शहर में प्रवेश कर रहे हैं। सड़कों पर भारी वाहनों की बढ़ती आवाजाही से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिरमल और रंगकदल पुल के आसपास, खासकर अगलर मंडी की ओर जाने वाले मार्ग पर दिन के व्यस्त समय में लंबा जाम लग रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, कटाई का मौसम शुरू होने के बाद से स्थिति लगातार बिगड़ी है। कार्यालय और अन्य काम से आने-जाने वाले लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लग रहा है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से फल लदे भारी वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की मांग की है। लोगों का सुझाव है कि व्यस्त समय में ट्रकों को शहर में प्रवेश देने के बजाय उनके लिए निर्धारित समय तय किया जाए। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि सेब उद्योग स्थानीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है और किसानों की फसल को समय पर मंडियों तक पहुंचाना जरूरी है। इसलिए यातायात व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिससे किसानों और व्यापारियों के काम पर असर न पड़े तथा आम लोगों को भी जाम से राहत मिले।

मोहम्मद जैद मलिक ने संभाली एनआईए जम्मू शाखा की अहम जिम्मेदारी



भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर पुलिस सेवा (जेकेपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद जैद मलिक ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की जम्मू शाखा में पुलिस अधीक्षक (एसपी) का पद संभाल लिया है। वह एनआईए के जम्मू स्थित स्थानीय कार्यालय की कमान संभालने वाले जेकेपीएस कैडर के पहले अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति को जम्मू-कश्मीर पुलिस सेवा के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

मलिक को 29 सितंबर को प्रतिनियुक्ति के आधार पर एनआईए में शामिल किया गया था। एनआईए मुख्यालय के आदेश के तहत उन्हें जम्मू शाखा में एसपी नियुक्त किया गया है। वह चार वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर एनआईए में आए हैं, जिसे नियमों के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है।

वर्ष 2001 में जम्मू-कश्मीर पुलिस सेवा में शामिल हुए मलिक को दो दशक से अधिक समय तक पुलिसिंग और आतंकवाद विरोधी अभियानों का व्यापक अनुभव है। उन्होंने अपने सेवाकाल में कई संवेदनशील क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। वह अवंतीपोरा और बांडीपोरा में जिला पुलिस की कमान भी संभाल चुके हैं।

इसके अलावा मलिक ने बारामुला, बांडीपोरा और अनंतनाग में पुलिस अधीक्षक अभियान के रूप में काम किया और आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन किया। उनके लंबे मैदानी अनुभव को नई जिम्मेदारी में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

एनआईए जम्मू शाखा में एसपी के रूप में मलिक के सामने आतंकवाद, आतंकी नेटवर्क और उससे जुड़े मामलों की जांच की निगरानी की जिम्मेदारी होगी। जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और उनके वित्तीय व सहयोगी नेटवर्क की जांच में एनआईए की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पुलिसिंग और आतंकवाद विरोधी अभियानों का स्थानीय अनुभव रखने वाले मलिक की नियुक्ति से जम्मू-कश्मीर पुलिस और एनआईए के बीच बेहतर समन्वय की उम्मीद है।

इलेक्ट्रिक बसों से जम्मू में परिवहन व्यवस्था होगी और बेहतर

जम्मू में दौड़ेंगी 75 नई इलेक्ट्रिक बसें संकरे मार्गों पर आसान होगा सफर

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुविधाजनक और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में जम्मू स्मार्ट सिटी में 75 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। सात मीटर लंबी और वातानुकूलित ये बसें शहर के संकरे और भीड़भाड़ वाले मार्गों पर यात्रियों को सुगम एवं आरामदायक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएंगी। केंद्र सरकार के पीएम-ईबस सेवा कार्यक्रम के तहत बसों की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। निविदा प्रक्रिया में मेसर्स पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जम्मू-कश्मीर के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी यानी एल-1 के रूप में सामने आई है। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने इसकी जानकारी जम्मू-कश्मीर प्रशासन को दे दी है। अब औपचारिक अनुबंध की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बसों की आपूर्ति शुरू होने की उम्मीद है। जम्मू शहर में फिलहाल जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के माध्यम से 100 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं।



भीड़भाड़ वाले मार्गों पर यात्रियों को मिलेगी सुगम और आरामदायक आवाजाही सुविधा।

संकरे मार्गों पर मिलेगी सुविधा

नई बसों की लंबाई सात मीटर होगी। इनके वातानुकूलित होने से यात्रियों को गर्मी के मौसम में भी आरामदायक सफर मिलेगा। छोटे आकार के कारण ये बसें शहर के संकरे, व्यस्त और अधिक यातायात वाले मार्गों पर आसानी से संचालित की जा सकेंगी। सात, नौ और 12 मीटर लंबाई की बसों का मिश्रित बेड़ा होने से प्रशासन को अलग-अलग मार्गों की जरूरत के अनुसार बसों का संचालन करने में सुविधा होगी।

स्वच्छ परिवहन को मिलेगा बढ़ावा : जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. देवांश यादव ने बताया कि 75 बसें पीएम-ईबस सेवा निविदा-3 के लाट-16 के तहत जम्मू के लिए आवंटित की गई हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल शहर को स्वच्छ, आधुनिक और भरोसेमंद सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

नवरात्र में वैष्णो देवी दर्शन के लिए चलेंगी दो विशेष ट्रेनें

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। त्योहारी सीजन में श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा के बीच दो अतिरिक्त फेरे लगाने का निर्णय लिया है। आरक्षित फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन संख्या 04083/04084 नौ, 10, 16 और 17 अक्टूबर को यात्रियों को सुविधा देगी। इससे त्योहारों के दौरान दिल्ली, पंजाब, जम्मू और कटड़ा के बीच बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

ट्रेन संख्या 04083 नई दिल्ली से नौ और 16 अक्टूबर को दोपहर दो बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह तीन बजे श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04084 कटड़ा से 10 और 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे रवाना होकर उसी दिन रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।

करीब 655 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस विशेष ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक एलएचबी के 22 कोच लगाए जाएंगे। ट्रेन का संचालन आरक्षित श्रेणी में किया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा की योजना पहले बनाने और समय रहते टिकट बुक कराने की अपील की है।



फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला कैंट, ढंडारी कलां, जालंधर कैंट, पठानकोट कैंट, शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ, जम्मू तवी और शहीद कैप्टन तुषार महाजन ऊधमपुर रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। इससे इन क्षेत्रों के यात्रियों को भी कटड़ा तक पहुंचने का अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।

इसके अलावा नई दिल्ली-कटड़ा-नई दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन संख्या 04081/04082 का संचालन भी जारी है। यह ट्रेन 26 अक्टूबर तक यात्रियों को सुविधा देती रहेगी। त्योहारी अवधि में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू-कश्मीर पहुंचते हैं।

आंधी-बारिश ने धान की फसल गिराई, किसानों की बढ़ी चिंता

भारतेंदु संवाददाता, आरएसपुरा। तेज बारिश और आंधी से आरएसपुरा क्षेत्र में खेतों में खड़ी धान की फसल जगह-जगह जमीन पर गिर गई। फसल कटाई के करीब होने के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। उन्हें उत्पादन प्रभावित होने के साथ दाने की गुणवत्ता खराब होने का डर सता रहा है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, धान की फसल के गिरने से कटाई का काम कठिन हो जाता है। खेतों में अधिक नमी रहने पर जमीन पर पड़ी बालियों में दाने खराब होने या अंकुरित होने का खतरा बढ़ जाता है। यदि बारिश का दौर जारी रहा तो किसानों की परेशानी और बढ़ सकती है। पूर्व कृषि अधिकारी रीज कुमार ने बताया कि भारी बारिश और तेज हवाओं से गिरी फसल को लंबे समय तक खेत में छोड़ना नुकसानदायक हो सकता है। नमी अधिक रहने से दानों की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ उत्पादन में भी कमी आ सकती है। किसान सुरजीत सिंह ने बताया कि धान की फसल पककर तैयार होने वाली थी, लेकिन बुधवार की बारिश ने काफी क्षेत्र में फसल गिरा दी। किसान तारा चंद ने कहा कि पहले से मौसम को लेकर चिंता थी, अब तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने मुश्किल बढ़ा दी है।

नए कानूनों से कारोबार आसान होगा, पूर्व विधायकों की पेंशन भी बढ़ेगी

उपराज्यपाल की मंजूरी से जम्मू-कश्मीर में छह नए कानून लागू होने का रास्ता साफ

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विधानसभा के 21 से 30 सितंबर तक चले शरदकालीन सत्र में पारित छह महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में इन कानूनों के प्रावधान लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। संबंधित विभाग अब नियम, दिशा-निर्देश और अधिसूचनाएं जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।



मंजूर विधेयकों में सहकारी समितियां (संशोधन), नगरपालिका (संशोधन), ईज आफ डूइंग बिजनेस, वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन), राज्य विधानमंडल सदस्यों की पेंशन (संशोधन) और जन विश्वास तृतीय (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक शामिल हैं।

ईज आफ डूइंग बिजनेस कानून के तहत उद्यमों को अनुमोदन, अनुमति, पंजीकरण, लाइसेंस और अन्य नियामकीय प्रक्रियाओं से संबंधित निरीक्षण या कार्रवाई से तीन वर्ष तक संरक्षण मिलेगा। हालांकि, संबंधित उपायुक्त की अनुमति से निरीक्षण या कार्रवाई की जा सकेगी। स्वीकृत औद्योगिक पार्कों में स्थापित होने वाले उद्यमों को जिला सशक्त समितियों के माध्यम से तीन कार्य दिवस में सैद्धांतिक मंजूरी प्रमाणपत्र देने का भी प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना तथा कारोबार से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।

जन विश्वास संशोधन के तहत मामूली नियामकीय उल्लंघनों के लिए कारावास के बजाय आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 23 अधिनियमों में संशोधन और दो अप्रासंगिक पुराने कानूनों को समाप्त करने की व्यवस्था की गई है। इससे कारोबारियों और संस्थानों पर अनावश्यक आपराधिक कार्रवाई का बोझ कम होने की उम्मीद है।

रामबन में अनियंत्रित होकर पलटी सूमो, एक की मौत, आठ घायल



◆ हादसे के कारणों की जांच जारी, घायलों की हालत पर नजर रखे हुए पुलिस

भारतेंदु संवाददाता, रामबन। जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में गुरुवार को सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हो गए। हादसा उखेरहल के सेनाबती इलाके में उस समय हुआ, जब एक सूमो वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, चालक का वाहन पर से नियंत्रण हटने के बाद सूमो दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल दो लोगों को जिला अस्पताल रामबन रेफर किया गया, जबकि छह अन्य घायलों को बेहतर उपचार के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग भेजा गया।

हादसे में मृत व्यक्ति की पहचान चुनथन, सेनाबती निवासी विजय सिंह (पुत्र राज सिंह) के रूप में हुई है। जिला अस्पताल रामबन भेजे गए घायलों में सोनी चंद (पुत्र अमर चंद) और सुनील सिंह (पुत्र प्यार सिंह) शामिल हैं। सोनी चंद के सिर में चोट आई है।

अनंतनाग रेफर किए गए घायलों की पहचान आनंद सिंह, अनिल चंद, नरेश सिंह, जतिंदर सिंह, रविंदर सिंह और रवित सिंह के रूप में हुई है। सभी का उपचार जारी है। पुलिस ने हादसे का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में वाहन के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है। पुलिस हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

पहाड़ों का बार-बार

दरकना, हम सबके लिए एक चेतावनी



पहाड़ सदियों से प्रकृति के प्रहरी रहे हैं। वे नदियों के उद्गम स्थल, जंगलों और जैव विविधता के संरक्षक तथा करोड़ों लोगों के जीवन और आजीविका का आधार हैं। लेकिन आज जब पहाड़ बार-बार दरक रहे हैं, भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला तेज होता दिखाई दे रहा है, तब इसे केवल स्थानीय समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह प्रकृति की ओर से मानव समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है।

हिमालय जैसे युवा और संवेदनशील पर्वत प्राकृतिक रूप से भूगर्भीय गतिविधियों, भारी वर्षा, भूकंपीय हलचलों और प्राकृतिक कटाव के प्रति संवेदनशील हैं। चिंता की बात यह है कि मानवीय गतिविधियों ने इस संवेदनशीलता को कई स्थानों पर और बढ़ा दिया है। अंधाधुंध निर्माण, बिना उचित योजना के सड़क निर्माण, पहाड़ों की कटाई, जंगलों का कम होना और प्राकृतिक जल निकासी तंत्र से छेड़छाड़ पर्वतीय क्षेत्रों पर अतिरिक्त दबाव डाल रहे हैं।

विकास हर क्षेत्र की आवश्यकता है। पहाड़ों में सड़क, अस्पताल, विद्यालय, संचार और अन्य आधारभूत सुविधाएं लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी हैं। लेकिन विकास का अर्थ प्रकृति की सीमाओं की अनदेखी नहीं हो सकता। जब किसी पहाड़ को बिना पर्याप्त वैज्ञानिक अध्ययन के काटा जाता है, ढलानों पर अत्यधिक निर्माण होता है या प्राकृतिक जलमार्गों को बंद कर दिया जाता है, तो वर्षा के दौरान पानी अपना रास्ता खोजता है और कमजोर ढलानों पर दबाव बढ़ जाता है। इससे मिट्टी और चट्टानों के खिसकने का खतरा बढ़ जाता है।

पर्वतीय क्षेत्रों की सुरक्षा में जंगलों और वनस्पतियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेड़-पौधे मिट्टी को बांधे रखने और जल को प्राकृतिक रूप से जमीन में समाने में मदद करते हैं। इसलिए वृक्षारोपण को केवल औपचारिक अभियान तक सीमित रखने के बजाय स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पौधारोपण, उनकी देखभाल और प्राकृतिक वनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा।

बदलते मौसम ने भी पर्वतीय क्षेत्रों की चुनौतियां बढ़ाई हैं। लंबे समय तक वर्षा न होने के बाद अचानक कम समय में अत्यधिक बारिश होना ढलानों पर भारी दबाव डाल सकता है। ऐसी परिस्थितियों में संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, समय रहते चेतावनी और आपदा से निपटने की तैयारी बेहद आवश्यक है। आपदा आने के बाद राहत और बचाव जरूरी हैं, लेकिन उससे पहले जोखिम को समझना और उसे कम करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है।

भवन, सड़क, होटल और अन्य निर्माण कार्य स्थानीय भूगर्भीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए। हर ढलान की क्षमता समान नहीं होती। इसलिए निर्माण से पहले वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए। प्राकृतिक जलधाराओं, नालों और पुराने जलमार्गों को बाधित करना भविष्य में गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। प्रकृति की अपनी व्यवस्था है और उसके साथ संतुलन बनाए रखना ही सुरक्षित विकास का आधार है।

पर्वतीय क्षेत्रों के स्थानीय समुदायों के अनुभव को भी विकास योजनाओं में महत्व दिया जाना चाहिए। स्थानीय लोग वर्षों के अनुभव से जलधाराओं के पुराने रास्तों, भूमि की प्रकृति और संवेदनशील स्थानों को समझते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन और स्थानीय ज्ञान एक-दूसरे के पूरक बनकर पर्वतीय क्षेत्रों को अधिक सुरक्षित बना सकते हैं।

पहाड़ों का संरक्षण केवल सरकार या किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। आम नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जंगलों और जलस्रोतों की रक्षा, प्राकृतिक जलमार्गों में कचरा न डालना, असुरक्षित निर्माण के प्रति जागरूक रहना और लगाए गए पौधों की देखभाल करना सामूहिक जिम्मेदारी है। विद्यालयों, पंचायतों, सामाजिक संस्थाओं और प्रशासन को मिलकर पर्यावरण तथा आपदा जागरूकता को जनआंदोलन बनाना चाहिए।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)



केशव शर्मा 'रसिक'
स्वतन्त्र लेखक

संपादकीय

बुजुर्गों के लिए थोड़ा ठहरें

आज की जिंदगी बहुत तेज हो गई है। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को बिस्तर पर जाने तक इंसान किसी न किसी काम में व्यस्त रहता है। पढ़ाई, नौकरी, कारोबार, परिवार, मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने जीवन को सुविधाओं से तो भर दिया है, लेकिन इसी भागदौड़ में कहीं कुछ बेहद जरूरी पीछे छूटता जा रहा है। हमारे घर के वे बुजुर्ग, जिन्होंने कभी हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया था, आज अक्सर उसी घर में हमारे कुछ मिनटों के समय के लिए तरसते दिखाई देते हैं। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना शायद यही है कि हमारे पास दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से बात करने का समय है, लेकिन अपने घर में बैठे माता-पिता या दादा-दादी के पास बैठने के लिए समय नहीं।

बुजुर्ग किसी परिवार की जिम्मेदारी भर नहीं होते, वे उस परिवार की स्मृतियों, अनुभवों और संस्कारों का जीवित खजाना होते हैं। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा परिवार को बनाने और संवारने में लगा दिया। अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर बच्चों की जरूरतों को प्राथमिकता दी। जिस उम्र में उन्हें आराम, अपनापन और साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी उम्र में कई बार उन्हें घर के एक कमरे तक सीमित कर दिया जाता है। उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। वे बार-बार वही पुरानी बातें बताते हैं, वही किस्से सुनाते हैं और शायद हमें लगता है कि यह सब हम पहले सुन चुके हैं। लेकिन उनके लिए वह कहानी दोहराना केवल बीती बातों को याद करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को किसी के साथ बांटना होता है।

बचपन में जब हम बीमार पड़ते थे तो मां रात भर जागती थी। पिता अपनी परेशानियों को छिपाकर हमारी जरूरतें पूरी करते थे। दादा-दादी हमारी शरारतों पर मुस्कुराते थे और कई बार माता-पिता की डांट से हमें बचा लेते थे। समय का पहिया घूमता है और वही बच्चे बड़े होकर अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। बुजुर्गों की जरूरतें बहुत बड़ी नहीं होतीं। उन्हें महंगे उपहारों से ज्यादा दो मीठे शब्द, थोड़ी बातचीत और अपनेपन का एहसास चाहिए। कई बार उनके लिए हमारा दस मिनट पास बैठना किसी बड़ी सौगात से कम नहीं होता।

आज तकनीक ने दूरी कम करने के अनेक साधन दिए हैं, लेकिन भावनात्मक दूरी बढ़ाने का खतरा भी पैदा किया है। एक ही कमरे में बैठे परिवार के सदस्य अपने-अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। बुजुर्ग कुछ कहना चाहते हैं तो सामने वाला कह देता है, 'अभी व्यस्त हूं।' यह 'अभी' धीरे-धीरे महीनों और वर्षों में बदल जाता है। फिर एक दिन हमें एहसास होता है कि जिनसे बातें करने के लिए पूरा जीवन पड़ा था, उनके पास अब शायद सुनने के लिए समय ही नहीं बचा। इसलिए जरूरी है कि हम समय रहते अपने रिश्तों को समय दें।

बुजुर्गों के साथ रहना केवल उनकी सेवा करना नहीं है, बल्कि उनसे सीखना भी है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में जीवन जिया है। उनके अनुभव हमें कई ऐसी बातें सिखा सकते हैं, जो किसी किताब या इंटरनेट पर नहीं मिलेंगी। उन्होंने अभाव देखे हैं, रिश्तों को निभाया है, असफलताओं से उबरना सीखा है और छोटी-छोटी खुशियों का महत्व समझा है। आज जब हम छोटी-सी परेशानी में तनावग्रस्त हो जाते हैं, तब किसी बुजुर्ग की जीवन यात्रा हमें धैर्य का अर्थ समझा सकती है।

यह भी समझना होगा कि बुजुर्गों को हर बात में हमारी मदद की जरूरत नहीं होती। कई बार वे केवल यह चाहते हैं कि परिवार उन्हें महत्व दे। उनसे घर के छोटे-बड़े फैसलों पर राय लेना उन्हें यह एहसास कराता है कि वे आज भी परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बच्चों को भी दादा-दादी और नाना-नानी के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे एक पीढ़ी का अनुभव दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है और परिवार की जड़ें मजबूत होती हैं।

बुजुर्गों की देखभाल केवल बेटे या बहू की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। यह पूरे परिवार की साझा जिम्मेदारी है। यदि माता-पिता हमारे बचपन की हर जरूरत के लिए हमारे साथ खड़े रहे, तो उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में हमारा साथ उनके प्रति किसी एहसान का नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते और संस्कार का परिचय है। उन्हें अकेला छोड़कर हम केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि अपने परिवार की एक पूरी पीढ़ी की स्मृतियों और अनुभवों को खो देते हैं।

जिंदगी कितनी भी तेज क्यों न हो जाए, रिश्तों के लिए कुछ पल निकालना जरूरी है। सफलता, पैसा, पद और प्रतिष्ठा जीवन को सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन अपनापन नहीं खरीद सकते। इसलिए जब अगली बार घर में कोई बुजुर्ग आपको आवाज दे, तो मोबाइल कुछ देर के लिए किनारे रख दीजिए। उनके पास बैठिए, उनकी बात सुनिए, उनका हाथ पकड़िए और पूछिए कि वे कैसे हैं। हो सकता है उन्हें किसी बड़ी चीज की जरूरत न हो, केवल आपके साथ की जरूरत हो। याद रखिए, समय कभी लौटकर नहीं आता। आज हमारे पास जिन बुजुर्गों का साथ है, वह हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए इस तेज रफ्तार दुनिया में थोड़ा ठहरिए, पीछे मुड़कर देखिए और उन लोगों को समय दीजिए, जिन्होंने कभी आपके लिए अपनी पूरी दुनिया रोक दी थी। क्योंकि जिंदगी की असली दौड़ में सबसे बड़ी जीत यही है कि हम आगे बढ़ते हुए अपनी जड़ों को न भूलें।

-शिवांश धाकड़

विश्व अर्थव्यवस्था की बदलती दिशा और भारत पर उसका असर



विश्व अर्थव्यवस्था इस समय विकास और अनिश्चितता के दोहरे दौर से गुजर रही है। युद्ध, महंगा कच्चा तेल, व्यापारिक तनाव, ऊंची ब्याज दरें, बढ़ता सरकारी कर्ज और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भारी निवेश वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा को प्रभावित कर रहे हैं। सितंबर 2026 के आकलन के अनुसार, 2026 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि करीब तीन प्रतिशत रहने का अनुमान है। ऐसे में दुनिया के सामने विकास की गति बनाए रखने के साथ महंगाई, ऊर्जा सुरक्षा, कर्ज और भू-राजनीतिक तनाव के बीच संतुलन कायम करने की चुनौती है।

इस वैश्विक माहौल में भारत अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में दिखाई देता है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.8 प्रतिशत रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 6.9 प्रतिशत से अधिक है। निवेश, घरेलू खपत, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र ने इस वृद्धि को मजबूती दी है। हालांकि तेज जीडीपी वृद्धि निश्चित रूप से भारत की आर्थिक क्षमता को दर्शाती है, लेकिन केवल आर्थिक विकास दर को आम लोगों की खुशहाली का पैमाना नहीं माना जा सकता। रोजगार की गुणवत्ता, वास्तविक मजदूरी, छोटे कारोबारों की स्थिति और परिवारों की क्रय शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।

भारत के सामने सबसे बड़ी बाहरी चुनौतियों में ऊर्जा सुरक्षा प्रमुख है। मध्य-पूर्व में संघर्ष और भू-राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। तेल महंगा होने से परिवहन, बिजली, उर्वरक, रसायन और औद्योगिक उत्पादन की लागत बढ़ती है। इसका असर आयात बिल, रुपये की विनिमय दर और अंतत: आम नागरिक की जेब पर पड़ सकता है। इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा, घरेलू उत्पादन, विद्युत वाहन, ऊर्जा दक्षता और रणनीतिक तेल भंडार में निवेश बढ़ाना आवश्यक है।



राधिका सैनी, तहसीलदार
नूरपुर, जिला कांगड़ा, हि.प्र.

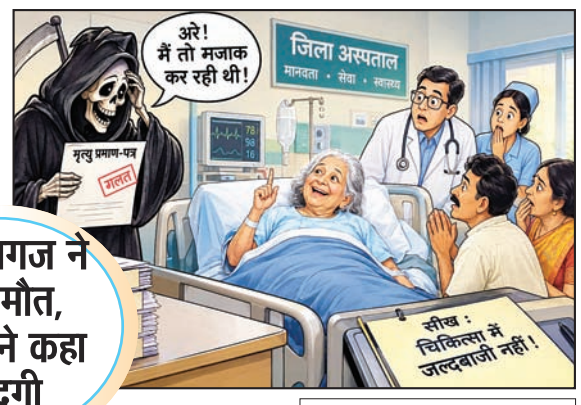
वैश्विक वित्तीय परिस्थितियां भी भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका की ब्याज दरें और डॉलर की मजबूती अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह को प्रभावित करती हैं। दूसरी ओर चीन की आर्थिक सुस्ती भारत के लिए चुनौती के साथ अवसर भी पैदा कर सकती है। चीन से बाहर आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थानांतरित करने की कोशिश कर रही वैश्विक कंपनियों के लिए भारत आकर्षक विकल्प बन सकता है। लेकिन इसके लिए प्रतिस्पर्धी लागत, कुशल श्रम, बेहतर बुनियादी ढांचा, विश्वसनीय बिजली और आसान कारोबारी माहौल जरूरी होगा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी भारत के आर्थिक भविष्य को प्रभावित करने वाला बड़ा क्षेत्र है। डेटा केंद्र, सेमीकंडक्टर, डिजिटल सेवाएं और एआई आधारित तकनीक भारत के लिए नए निवेश और रोजगार के अवसर पैदा कर सकती हैं। हालांकि स्वचालन के कारण पारंपरिक नौकरियों का स्वरूप बदलने की संभावना भी है। इसलिए युवाओं को नई तकनीक के अनुरूप कौशल प्रदान करना जरूरी होगा। तेज आर्थिक वृद्धि तभी सार्थक होगी जब वह पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा करे।

भारत की घरेलू मांग उसकी सबसे बड़ी ताकतों में है, लेकिन महंगाई और परिवारों की वास्तविक आय पर भी ध्यान देना होगा। खाद्य पदार्थ, ईंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की बढ़ती लागत परिवारों की क्रय शक्ति को प्रभावित करती है। साथ ही वैश्विक व्यापार में बढ़ता संरक्षणवाद भारतीय निर्यात के लिए चुनौती बन सकता है। ऐसे में नए बाजार तलाशने के साथ घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना आवश्यक है।

(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

जब मौत ने कहा— 'मैं तो मजाक कर रही थी!



एक कागज ने कहा मौत, सांसों ने कहा जिंदगी

अस्पतालों में मरीज इलाज और बेहतर स्वास्थ्य की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर बीमारी की पहचान कर उपचार शुरू करते हैं और परिवार इस भरोसे के साथ अस्पताल के हर निर्णय को स्वीकार करता है कि वहां जीवन बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन कभी-कभी चिकित्सा व्यवस्था से जुड़ी ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं, जो गंभीर सवाल खड़े करने के साथ-साथ अपने आप में किसी व्यंग्य से कम नहीं होतीं। रीवा के एक अस्पताल में करीब 80 वर्षीय महिला को जांच के बाद मृत घोषित किया गया, लेकिन अगले दिन जब उनकी सांसें चलती मिलीं तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। घटना ने चिकित्सा प्रक्रिया, जल्दबाजी और मृत्यु की पुष्टि के मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

कल्पना कीजिए, परिवार ने जिस व्यक्ति को मृत मानकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी हो, अगले दिन वही व्यक्ति सांस लेता हुआ मिल जाए तो परिजनों की हालत क्या होगी। इस घटना में कुछ ऐसा ही हुआ। महिला को चिकित्सकीय जांच के बाद मृत घोषित किया गया था। परिवार ने भारी मन से इस दुखद सूचना को स्वीकार किया और अस्पताल की औपचारिकताएं आगे बढ़ने लगीं। लेकिन अगले दिन महिला में जीवन के संकेत मिलने के बाद पूरा घटनाक्रम ही बदल गया। डॉक्टरों ने तत्काल उन्हें गंभीर रोगी वार्ड में भर्ती किया और उपचार शुरू किया।

व्यंग्य का सबसे दिलचस्प पक्ष यही है कि मौत का प्रमाण-पत्र तैयार हो गया, लेकिन जिंदगी ने उस कागज पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। मानो महिला खुद अस्पताल से कह रही हों— 'साहब, कागज बाद में देखिए, पहले मुझे सांस तो लेने दीजिए।' आम तौर पर अस्पतालों में इलाज को लेकर 'फास्ट सर्विस' की उम्मीद की जाती है। जांच जल्दी, रिपोर्ट जल्दी, दवा जल्दी और छुट्टी भी जल्दी। लेकिन मृत्यु की घोषणा ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें जल्दबाजी की कोई जगह नहीं हो सकती। यह कोई ऑनलाइन टिकट या खाने का आर्डर नहीं है कि कुछ मिनट में प्रक्रिया पूरी कर दी जाए।

इस घटना का व्यंग्यात्मक पहलू हमें एक गंभीर सच्चाई की ओर भी ले जाता है। अस्पताल के दस्तावेजों में किसी व्यक्ति की मृत्यु दर्ज होना महज कागजी कार्रवाई नहीं है। उसके साथ परिवार की भावनाएं, अंतिम संस्कार की तैयारियां और अनेक सामाजिक तथा कानूनी प्रक्रियाएं जुड़ी होती हैं। ऐसे में यदि किसी जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाए तो इसका असर केवल अस्पताल की व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार को मानसिक आघात से गुजरना पड़ सकता है।

मौत और जिंदगी के बीच फैसला बेहद संवेदनशील विषय है। इसलिए किसी मरीज को मृत घोषित करने से पहले निर्धारित चिकित्सकीय प्रक्रिया, आवश्यक जांच और सभी मानकों का पूरी सावधानी से पालन किया जाना चाहिए। एक छोटी सी लापरवाही भी किसी परिवार के लिए जीवनभर की पीड़ा बन सकती है। डॉक्टरों पर मरीजों और उनके परिजनों का भरोसा इसी बात पर टिका होता है कि उनका हर निर्णय वैज्ञानिक आधार और पूरी जिम्मेदारी के साथ लिया जाएगा।

बेशक यह घटना पहली नजर में हास्यास्पद लग सकती है और इस पर व्यंग्य भी किया जा सकता है। लेकिन इसके पीछे छिपा सवाल बेहद गंभीर है। यदि किसी मरीज की मृत्यु की पुष्टि में चूक हो सकती है तो अस्पतालों को अपनी प्रक्रियाओं की समीक्षा करनी चाहिए। आखिर जिंदगी कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसे एक हस्ताक्षर से समाप्त घोषित कर दिया जाए।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)



संजय एम तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)

आज की प्रमुख हस्ती

सयानी का सिनेमा सफर

भारतीय अभिनेत्री सयानी गुप्ता का जन्म 9 अक्टूबर 1985 को हुआ। हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाने वाली सयानी गुप्ता ने अभिनय की बारीकियां फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से सीखी हैं। रंगमंच और अभिनय की दुनिया में रुचि रखने वाली सयानी ने अपने करियर की शुरुआत संघर्ष के दौर से की और धीरे-धीरे फिल्मों में अपनी जगह बनाई। उन्होंने वर्ष 2012 में फिल्म 'सेकंड मैरिज डॉट कॉम' से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की।



सयानी गुप्ता
जन्म : 9 अक्टूबर 1985

इसके बाद सयानी ने कई फिल्मों में सहायक और महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। वर्ष 2016 में आई फिल्म 'फैन' में उनके अभिनय को दर्शकों ने देखा। इसके बाद 'जॉली एलएलबी 2' और 'आर्टिकल 15' जैसी फिल्मों में भी उन्होंने प्रभावशाली भूमिकाएं निभाईं। हालांकि, सयानी को सबसे अधिक चर्चा फिल्म 'मार्गरिटा विद ए स्ट्रॉ' में निभाए गए खानुम के किरदार से मिली। इस फिल्म में उन्होंने एक दृष्टिबाधित पाकिस्तानी-बांग्लादेशी समलैंगिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाई थी। उनके अभिनय को इस चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील किरदार के लिए काफी सराहना मिली।

सयानी गुप्ता की खासियत यह रही है कि उन्होंने केवल पारंपरिक नायिका की भूमिकाओं तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने अलग-अलग सामाजिक पृष्ठभूमि और जटिल भावनाओं वाले किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया। उनके अभिनय में सहजता और संवेदनशीलता दिखाई देती है, जिसके कारण वह अपनी पीढ़ी की अलग पहचान रखने वाली अभिनेत्रियों में शामिल हुईं।

फिल्मों के अलावा सयानी ने डिजिटल माध्यम पर भी काम किया और विभिन्न तरह के किरदारों के जरिए अपनी अभिनय क्षमता का विस्तार किया। उनकी यात्रा यह दिखाती है कि मजबूत अभिनय और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को चुनकर कलाकार बिना पारंपरिक मुख्यधारा की छवि के भी दर्शकों के बीच अपनी पहचान बना सकता है।

विकास की राह में प्रकृति को न भूलें



वर्तमान समय में विश्व जिन गंभीर संकटों का सामना कर रहा है, उनमें पर्यावरण का निरंतर ह्रास सबसे चिंताजनक है। मानव सभ्यता ने विकास और प्रगति के नाम पर प्रकृति के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया है, उससे पृथ्वी का प्राकृतिक संतुलन गहराई से प्रभावित हुआ है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, वनों की अंधाधुंध कटाई, खनन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन ने पर्यावरण को ऐसे संकट की ओर धकेल दिया है, जहां मानव जीवन का अस्तित्व भी चुनौती के घेरे में दिखाई देने लगा है। ऐसे समय में वन एवं पर्यावरण विभाग की भूमिका और उत्तरदायित्व पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

मानव इस धरती का सबसे समझदार और जागरूक प्राणी माना जाता है। इसलिए प्रकृति और उसके संसाधनों के संरक्षण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी मानव की ही है। पर्यावरण का ह्रास अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह मानव गतिविधियों के लंबे , म का परिणाम है। वनों की अंधाधुंध कटाई इसका प्रमुख कारण है। वन केवल पेड़ों का समूह नहीं होते, बल्कि वे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के आधार स्तंभ हैं। वे जलचक्र को संतुलित रखते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, जैव विविधता को संरक्षण देते हैं और जलवायु को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पिछले कुछ दशकों में सड़क निर्माण, बड़े बांधों, उद्योगों और शहरी विस्तार के कारण प्राकृतिक वन क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप कई स्थानों पर जलस्रोतों के सूखने, मिट्टी के कटाव और प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में इसका प्रभाव और गंभीर हो सकता है। यहां की भौगोलिक परिस्थितियां अत्यंत संवेदनशील हैं। अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन, अचानक बाढ़ और बादल फटने जैसी घटनाएं पर्वतीय क्षेत्रों की नाजुकता को सामने लाती हैं।

पर्यावरणीय ह्रास का व्यापक प्रभाव जलवायु परिवर्तन के रूप में भी सामने आ रहा है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, हिमनदों का पिघलना और मौसम के स्वरूप में बदलाव चिंता का विषय है। पहाड़ी क्षेत्रों में कभी नियमित रहने वाली वर्षा का अनियमित होना, कभी अत्यधिक बारिश और कभी लंबे समय तक वर्षा का अभाव कृषि, जल संसाधनों और स्थानीय जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण को केवल एक विभागीय कार्य न मानकर व्यापक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखना आवश्यक है। इन परिस्थितियों में वन एवं पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी केवल जंगलों की रक्षा तक सीमित नहीं रह सकती। वनों का संरक्षण और संवर्धन उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाना आवश्यक है, लेकिन केवल पौधे लगा देना पर्याप्त नहीं है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)



विक्रम वर्मा, गैहरा वग्वा
हिमाचल प्रदेश



किस्मत

वीरेन्द्र शर्मा वात्स्यायन, लोअर अरनियाला
ऊना (हिमाचल प्रदेश)

उद्यमशीलता, कर्मशीलता
बदल देते हैं किस्मत,
याद रखो—किस्मत से नहीं,
हम खुद से हैं,
फिर किस्मत के आगे
निठल्ले बैठकर क्या बदल जाएगा?
किस्मत क्यों रोते हो,
किस्मत पर अधिक मिलने पर
सब्र कहाँ रहता है?
लालसा कभी खत्म नहीं होती,
मन की चाहत
कभी पूरी नहीं होती।
तनिक विचार करो,
समय से पहले
और किस्मत से अधिक
कभी कुछ नहीं मिलता,
फिर क्यों कोसते हो
किस्मत को?
समझ लो—
कर्म प्रधान है जीवन हमारा,
यही है इस लोक-परलोक का आधार।
मेहनत को साथी बनाओ,
सद्कर्मों को राह बनाओ,
हर दिन अपने सपनों के
दरवाजे पर दस्तक दो।

'भारतेन्दु शिखर'

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

नेशनल हाईवे बना मलबे का डंपिंग ग्राउंड

रात में धड़ल्ले से डाला जा रहा मलबा, कई जगह सिंगल लेन हुई सड़क

रितेश चौहान, भारतेन्दु संवाददाता, सरकाघाट। जालंधर-हमीरपुर-कोटली-धर्मपुर वाया सरकाघाट नेशनल हाईवे-003 के किनारे निर्माण कार्यों का मलबा डाले जाने से सड़क कई जगह संकरी हो गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय चंद्रकाड़ी जंगल के पास हाईवे किनारे मलबा डाला जा रहा है। इससे कई स्थानों पर सड़क सिंगल लेन रह गई है और वाहन चालकों व पैदल चलने वालों को परेशानी हो रही है।

हाईवे किनारे मलबा जमा होने से वाहनों को पास लेने में दिक्कत हो रही है। वहीं, चंद्रकाड़ी के पास भारी वाहनों की पार्किंग के लिए तैयार की गई जगह पर भी मलबा डाल दिया गया है। इससे भारी वाहनों की पार्किंग प्रभावित होने के साथ यातायात व्यवस्था पर असर पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि हाईवे अथॉरिटी द्वारा जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर क्रैश बैरियर लगाने के बाद अब मलबा सड़क किनारे ही डाला जा रहा है। शहरवासियों ने मलबा फेंकने वालों पर कार्रवाई, जुर्माना लगाने और रात में निगरानी बढ़ाने की मांग की है।

नगर परिषद ईओ एवं एसडीएम सरकाघाट राजेंद्र गौतम ने कहा कि शिकायतें मिली हैं। पुलिस को संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई और छापेमारी के निर्देश दिए जा रहे हैं। हाईवे अथॉरिटी को सड़क किनारे पड़ा मलबा हटाने के लिए कहा गया है।



सरकाघाट में नेशनल हाईवे किनारे डाला गया निर्माण सामग्री का मलबा।

वन विभाग ने मलबा फेंकते पकड़ा टिप्पर : मदन लाल

वन विभाग के आरओ मदनलाल ने बताया कि जंगल और सड़क किनारे निर्माण सामग्री फेंकने से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। वन विभाग इस मामले में कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने बताया कि मौके पर एक टिप्पर को मलबा फेंकते हुए पकड़ा गया है। इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पैदल चलने वालों को हर समय हादसे का डर

चंद्रकाड़ी जंगल से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर शहर के सैकड़ों लोग रोजाना मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए निकलते हैं। इसके अलावा रेस्ट हाउस, एसडीएम कार्यालय, पुलिस थाना, वार्ड नंबर 1 व 2 और विद्युत विभाग कार्यालय आने-जाने वाले लोगों के लिए भी यह प्रमुख रास्ता है। हाईवे किनारे मलबे के ढेर लगने के कारण पैदल चलने वालों को सड़क पर उतरकर चलना पड़ रहा है। इसी दौरान तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही के कारण हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है।

वहीं, गबर कंपनी के साइट इंजीनियर श्रीकांत ने बताया कि हाईवे पर रोजाना सैकड़ों टन अवैध निर्माण सामग्री फेंकी जा रही है। इससे निर्माणाधीन सड़क को नुकसान हो रहा है। कंपनी को भी इससे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हाईवे पर इस तरह मलबा फेंकना सड़क निर्माण कार्य के लिए भी परेशानी पैदा कर रहा है।

एसपीयू मंडी के दो वैज्ञानिक स्टैनफोर्ड की शीर्ष दो प्रतिशत सूची में शामिल

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी



सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) मंडी के दो वैज्ञानिकों ने शोध के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए विश्वविद्यालय का नाम वैश्विक स्तर पर रोशन किया है। रसायन विज्ञान विभाग के डीन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. लखवीर सिंह तथा भौतिक विज्ञान विभाग के डीन सीडीसी एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अक्षय कुमार को स्टैनफोर्ड ग्लोबल टॉप-2% वैज्ञानिकों की सूची-2026 में स्थान मिला है। दोनों शिक्षकों की इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय में खुशी का माहौल है।

स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और एल्सेवियर की ओर से तैयार की जाने वाली इस वैश्विक सूची में वैज्ञानिकों के शोध की गुणवत्ता, शोध के सामाजिक प्रभाव, प्रकाशित शोध-पत्रों की संख्या और उनके उद्धरण सहित विभिन्न मानकों के आधार पर वैज्ञानिकों का मूल्यांकन किया जाता है। दुनिया के प्रभावशाली वैज्ञानिकों की इस सूची में स्थान मिलना शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है।

डॉ. लखवीर सिंह का शोध कार्य मुख्य रूप से जैव-विद्युत रासायनिक प्रौद्योगिकी, जैव-हाइड्रोजन उत्पादन और सूक्ष्मजीवी ईंधन कोशिका जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है। उन्होंने अब तक 170 से अधिक शोध-पत्र प्रकाशित किए हैं। इसके अलावा वह 30 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं और उनके नाम चार पेटेंट भी हैं। उनके शोध कार्यों को 9,800 से अधिक बार उद्धृत किया जा चुका है। उनका एच-इंडेक्स 58 और आई-10 इंडेक्स 117 है। डॉ. सिंह लगातार पिछले चार वर्षों से ऊर्जा एवं पर्यावरण के क्षेत्र में स्टैनफोर्ड की वैश्विक शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में स्थान बना रहे हैं। यह उनके निरंतर शोध और वैज्ञानिक योगदान को दर्शाता है।

वहीं, डॉ. अक्षय कुमार का शोध मुख्य रूप से टिकाऊ नैनो प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी तथा नैनोकंपोजिट्स के क्षेत्र में केंद्रित है। उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों पर 50 से अधिक शोध-पत्र और दो पुस्तकें प्रकाशित की हैं। उनके शोध कार्यों को 3,439 से अधिक बार उद्धृत किया जा चुका है। उनका एच-इंडेक्स 33 तथा आई-10 इंडेक्स 58 है। डॉ. कुमार को पहली बार स्टैनफोर्ड ग्लोबल टॉप-2% वैज्ञानिकों की सूची में स्थान मिला है। उनकी उपलब्धि विश्वविद्यालय के लिए विशेष महत्व रखती है।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ललित कुमार अवस्थी ने दोनों शिक्षकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि एसपीयू जैसे नवोदित विश्वविद्यालय के लिए यह गौरवपूर्ण उपलब्धि है कि उसके दो संकाय सदस्य विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुए हैं।

कोटली में रिटेनिंग दीवार ढही, सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, भगत सिंह गुलेरिया, मंडी। कोटली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 52.50 से 30 फीट ऊंची सपोर्टिंग/रिटेनिंग दीवार गिरने की घटना ने निर्माण गुणवत्ता, सुरक्षा व्यवस्था और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। समाजसेवी प्रो. अनुपमा सिंह ने कहा कि यह केवल दीवार गिरने का मामला नहीं, बल्कि निर्माण कार्यों में तकनीकी मानकों के पालन और गुणवत्ता जांच की पारदर्शिता से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पहाड़ों की अनियोजित कटिंग, मलबे के अनुचित निस्तारण, जलस्रोतों को नुकसान और स्थानीय घरों व जमीनों पर बढ़ते खतरे को लेकर पहले भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। उन्होंने मांग की कि निर्माण कार्यों की स्वतंत्र जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और स्पष्ट किया जाए कि कार्य निर्धारित डीपीआर व तकनीकी मानकों के अनुसार हुए हैं या नहीं। साथ ही प्रभावित परिवारों की संपत्ति और जलस्रोतों को नुकसान होने पर जिम्मेदारी तय करने की मांग की। उन्होंने मलबे के कथित अवैज्ञानिक निस्तारण का मुद्दा भी उठाया। बताया कि एनजीटी की कार्यवाही में गावर कंस्ट्रक्शन से जुड़े मलबा निस्तारण और पर्यावरणीय नुकसान के मामले दर्ज हैं।

न्यूज ब्रीफ

यूएई में इलेक्ट्रीशियन-फिटर भर्ती 14 अक्टूबर तक आवेदन

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि जिला रोजगार कार्यालय एवं मॉडल कैरियर सेंटर, मंडी के माध्यम से हिमाचल के युवाओं को संयुक्त अरब अमीरात में इलेक्ट्रीशियन और फिटर पदों पर रोजगार का अवसर दिया जा रहा है। भर्ती वर्तिव गल्फ एलएलसी के लिए होगी। अभ्यर्थी के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई या डिप्लोमा होना चाहिए। फ्रेशर और अनुभवी दोनों आवेदन कर सकते हैं तथा आयु सीमा 20 से 45 वर्ष है। चयनित अभ्यर्थियों को 1100 से 1300 एईडी मासिक वेतन, आठ घंटे की ड्यूटी और नियमानुसार अतिरिक्त समय का भुगतान मिलेगा। अनुबंध के अनुसार भोजन या भत्ता, आवास, परिवहन, वीजा और चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध होगी। वैध पासपोर्ट अनिवार्य है। इच्छुक अभ्यर्थी 14 अक्टूबर तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। साक्षात्कार 16 और 17 अक्टूबर को होगा। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय मंडी के दूरभाष 01905-235508 पर संपर्क किया जा सकता है।

एसआईआर विरोध पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर: विजय अग्निहोत्री

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में कांग्रेस के आंदोलन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संवैधानिक व्यवस्था का विरोध कर जनता में भ्रम पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21 के तहत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का अधिकार है। यह प्रक्रिया पहले भी अपनाई जाती रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता लगातार मतदाता सूचियों में फर्जी और दोहरे नामों का मुद्दा उठाते रहे हैं। ऐसे में जब एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूचियों की जांच, दोहरे नामों की पहचान और अपात्र प्रविष्टियों को हटाना है, तो कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस वोट चोरी के आरोपों को लेकर गंभीर है तो उसे पुनरीक्षण प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए।

पोंग झील में दुर्लभ श्राइक पक्षियों की पहली मौजूदगी दर्ज



भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. अभिनव चौधरी ने पोंग झील क्षेत्र में दो दुर्लभ प्रवासी पक्षियों की पहचान कर हिमाचल के पक्षी रिकॉर्ड में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने 13 सितंबर को नगरोटा सूरियां क्षेत्र में रेड-टेल्ड श्राइक और 20 सितंबर को रेड-बैक्ड श्राइक को कैमरे में कैद किया। दोनों पक्षी युवा अवस्था में थे, जिससे उनकी पहचान चुनौतीपूर्ण थी। श्राइक प्रजाति के युवा पक्षी एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं और इसाबेलाइन श्राइक से भी समानता रखते हैं। पुष्टि के लिए डॉ. चौधरी ने तस्वीरें देश-विदेश के विशेषज्ञ पक्षी वैज्ञानिकों को भेजीं, जिन्होंने गहन जांच के बाद दोनों की पहचान प्रमाणित की।

डीसी कार्यालय में सड़क सुरक्षा, दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात सुधार पर मंथन



भारतेन्दु संवाददाता, केलांग। जिला मुख्यालय स्थित उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति की अध्यक्ष किरण भड़ाना ने की। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने और सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक में सड़क की ज्यामितीय संरचना, चौराहों का प्रबंधन, सड़क निर्माण सामग्री, यातायात नियंत्रण उपकरण, सड़क किनारे सुरक्षा उपायों और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सुधार पर विचार किया गया। विद्यार्थियों और आम लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने, सुरक्षित यातायात आदतें अपनाने तथा दुर्घटना के समय मदद करने वाले नागरिकों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए दुर्घटना के बाद के महत्वपूर्ण समय में त्वरित चिकित्सा सहायता और एंबुलेंस सेवाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। यातायात नियमों के उल्लंघन की निगरानी और आवश्यक कार्रवाई के संबंध में भी अधिकारियों ने विचार साझा किए।

बैठक में तेज गति, मानवीय त्रुटियों और यातायात नियमों के उल्लंघन से होने वाली दुर्घटनाओं के आंकड़ों की समीक्षा की गई। चिह्नित दुर्घटना संभावित स्थानों पर किए गए कार्यों की भी समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने पर जोर दिया गया।

देई उत्सव में 25 स्कूलों की बालिकाओं ने दिखाई प्रतिभा

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित उत्सव में छात्राओं ने खेलकूद और रचनात्मक प्रतियोगिताओं में प्रतिभा दिखाई

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी







अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग मंडी की ओर से संस्कृत सदन, कांगणीधार में 'देई उत्सव-2026' आयोजित किया गया। इस वर्ष उत्सव की थीम 'बाल विवाह की कुप्रथा समाप्त हो और बालिकाओं के अधिकारों को बढ़ावा दें' रही। कार्यक्रम में नगर निगम मंडी की अतिरिक्त आयुक्त अपराजिता चंदेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं।

उन्होंने कहा कि आज की बेटियां किसी से कम नहीं हैं और प्रत्येक युवती में अपार संभावनाएं हैं। 'देई उत्सव' का उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना तथा उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की पहचान उसके पहनावे से नहीं, बल्कि उसके कार्य और उपलब्धियों से होनी चाहिए। प्रशासन की ओर से बालिकाओं को समान अवसर देने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अजय बदरेल ने बताया कि उत्सव में जिले के 25 स्कूलों की बालिकाओं ने भाग लिया। आयोजन 'बच्चों द्वारा, बच्चों के लिए' की अवधारणा पर आधारित रहा। बालिकाओं ने खेलकूद और रचनात्मक प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, नारा लेखन, पोस्टर निर्माण, रस्साकशी और 'जस्ट ए मिनट' जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। रस्साकशी में सेंट फ्रांसिस जेवियर्स कॉन्वेंट स्कूल की टीम प्रथम रही, जबकि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल लूणापानी और पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय मंडी की टीमों ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया।

इस अवसर पर वर्ष 2025-26 में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की दसवीं और जमा दो की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर मंडी जिले का नाम रोशन करने वाली मेधावी छात्राओं को भी सम्मानित किया गया।

उत्सव में ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े स्वयं सहायता समूहों ने स्थानीय व्यंजनों के फूड स्टॉल लगाए। बच्चों को कूपन के माध्यम से निःशुल्क स्थानीय व्यंजन परोसे गए। इसके अलावा विभिन्न मनोरंजक खेलों के स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र रहे।

तंजानिया में भारतीय समुदाय से मिले अनुराग सिंह ठाकुर, भारत-तंजानिया संबंधों पर जोर



भारतेन्दु संवाददाता, सुरेंद्र कटोच, हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने तंजानिया में भारतीय उच्चायोग की ओर से आयोजित भारतीय प्रवासी एवं सामुदायिक स्वागत समारोह में भाग लिया। वह राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के नेतृत्व में तंजानिया पहुंचे भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रतिनिधिमंडल 153वीं अंतर-संसदीय संघ सभा में भाग लेने के लिए तंजानिया पहुंचा है।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने तंजानिया में रह रहे भारतीय समुदाय और प्रमुख प्रवासी प्रतिनिधियों से संवाद किया। इस अवसर पर भारत और तंजानिया के बीच मजबूत मैत्रीपूर्ण संबंधों, आपसी सद्भाव और जन-से-जन संपर्क को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। भारतीय समुदाय के तंजानिया के विकास में योगदान को भी रेखांकित किया गया।

कार्यक्रम में तंजानिया स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। इनके माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सभ्यतागत विविधता और विदेशों में भारतीय संस्कृति की जीवंत उपस्थिति प्रदर्शित की गई। अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय समुदाय को भारत का स्थायी सांस्कृतिक दूत बताया। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों की उद्यमशीलता, प्रतिभा और समर्पण भारत-तंजानिया के ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

हमीरपुर की 87 पंचायतें टीबी मुक्त, उपायुक्त ने किया सम्मानित



भारतेन्दु संवाददाता, अनिल कुमार, हमीरपुर। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिला हमीरपुर की 87 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित कर सम्मानित किया गया। बचत भवन में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने पंचायत प्रतिनिधियों को पुरस्कार प्रदान किए। इनमें 10 पंचायतों को स्वर्ण, नौ को रजत और 68 पंचायतों को कांस्य पुरस्कार मिला। स्वर्ण पुरस्कार उन पंचायतों को दिया गया, जहां तीन वर्षों से टीबी का कोई नया मामला सामने नहीं आया। दो वर्षों से नए मामले नहीं मिलने वाली नौ पंचायतों को रजत तथा एक वर्ष से मामला नहीं मिलने वाली 68 पंचायतों को कांस्य पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम के दौरान टीबी मुक्त अभियान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 'जोश' टीमों का शुभारंभ भी किया गया। इनमें एनसीसी कैडेटों और युवा स्वयंसेवकों को शामिल किया गया है। ये टीमें लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करने, समय पर जांच और उपचार के लिए प्रेरित करने में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करेंगी। उपायुक्त ने पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि टीबी मुक्त होने के बाद भी पंचायतों को लगातार जागरूकता गतिविधियां चलानी चाहिए।

'एक पेड़ मां के नाम' को शैक्षणिक श्रेय से जोड़ेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश

◆ पौधों की देखभाल पर विद्यार्थियों को मिलेगा विशेष शैक्षणिक श्रेय



भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने पर्यावरण संरक्षण को विद्यार्थियों की शिक्षा और अकादमिक जिम्मेदारी से जोड़ते हुए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को एकेडमिक क्रेडिट से जोड़ने की पहल की है। शाहपुर परिसर में कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल ने अपनी माता परमेश्वरी देवी की स्मृति में पौधा रोपकर अभियान की शुरुआत की। इसके बाद विद्यार्थियों ने भी अपनी माताओं के नाम पर पौधे लगाए। कुलपति ने कहा कि पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा और नियमित देखभाल भी जरूरी है। विद्यार्थियों को पौधों के संरक्षण के आधार पर विशेष शैक्षणिक श्रेय दिया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय की वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में पहली बार 701-800 वर्ग में स्थान प्राप्त करने की उपलब्धि का भी जश्न मनाया गया। कुलपति ने कहा कि यह पूरे विश्वविद्यालय परिवार के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने विश्वविद्यालय का अगला लक्ष्य विश्व के 500 श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में स्थान बनाना बताया। इसके लिए शोध की गुणवत्ता, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, उद्योगों के साथ साझेदारी, नवाचार और विद्यार्थियों के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

कुलपति ने बताया कि जनवरी 2027 में विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस तथा अप्रैल 2027 में अंतरराष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित की जाएगी। इनमें देश-विदेश के वैज्ञानिक और शोधकर्ता भाग लेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों के आदान-प्रदान, संयुक्त शोध परियोजनाओं, बाहरी विशेषज्ञों से शोध प्रबंधों के मूल्यांकन, विदेशी विद्यार्थियों के प्रवेश और उद्योगों को विश्वविद्यालय की विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।

कांग्रेस की भ्रांतियों से जनता को करें सावधान : परमार

भारतेन्दु संवाददाता, पालमपुर



प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष एवं सुलह विधायक विपिन सिंह परमार ने 'मेरे सपनों का भारत' चित्र सेवा कार्यक्रम में बच्चों की प्रतिभा की सराहना की। उन्होंने कहा कि बच्चों के सपनों में विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की कल्पना दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं को रोजगार, किसानों को समृद्धि और महिलाओं को सम्मान व सुरक्षा देने वाला भारत बनाना लक्ष्य होना चाहिए।

परमार ने कहा कि 'मेरे सपनों का भारत' केवल चित्र बनाने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि बच्चों की कल्पनाओं, आकांक्षाओं और राष्ट्र के प्रति भावनाओं को समझने का अवसर है। नई पीढ़ी राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण शक्ति है और उसे सही दिशा तथा अवसर देना आवश्यक है।

इसके बाद सुलह में भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए परमार ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जनजागरण अभियान प्रभावी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष में कांग्रेस जनता के बीच भ्रम और भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर सकती है। भाजपा कार्यकर्ता इसका जवाब तथ्यों, उपलब्धियों और निरंतर जनसंवाद के माध्यम से दें।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले प्रदेश की जनता से दस गारंटियों सहित कई वादे किए थे। कार्यकर्ता घर-घर जाकर जनता को बताएं कि इनमें कितने वादे पूरे हुए और कितने अधूरे हैं।

गठजोड़ विकास मंच के दो सदस्यों की भूमिका से जिला परिषद सत्ता गठन में नया राजनीतिक समीकरण उभरा

लाहौल-स्पीति जिला परिषद में कांग्रेस-भाजपा गठजोड़ से बदले समीकरण

भारतेन्दु संवाददाता, केलांग



धनेश गौतम। लाहौल-स्पीति की राजनीति में जिला परिषद चुनाव के बाद सत्ता के नए समीकरणों ने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। जिला परिषद की सत्ता के लिए लंबे समय से एक-दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रहे कांग्रेस और भाजपा के साथ आने की चर्चा ने कई सवाल खड़े किए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को पूर्व मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा और उनके नेतृत्व वाले लाहौल-स्पीति विकास मंच के बढ़ते प्रभाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जिला परिषद की नौ सीटों में कांग्रेस के चार, भाजपा के तीन और विकास मंच के दो सदस्य निर्वाचित हुए। संख्या के लिहाज से कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनकर उभरी, जबकि भाजपा के तीन और विकास मंच के दो सदस्यों की भूमिका सत्ता गठन में निर्णायक मानी गई। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में समीकरण पूरी तरह बदल गए। तीन सदस्यों वाली भाजपा अध्यक्ष पद हासिल करने में सफल रही और उपाध्यक्ष पद भी इसी गठबंधन के खाते में गया। कांग्रेस के पास चार सदस्य होने के बावजूद वह सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस और भाजपा का यह तालमेल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों दल लंबे समय से एक-दूसरे के आमने-सामने रहे हैं।

जिला परिषद के सत्ता समीकरण में पूर्व विधायक रवि ठाकुर की भूमिका को लेकर भी चर्चा जारी है। नौ सदस्यीय परिषद में विकास मंच के दो सदस्यों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण साबित हुई। अब सवाल यह है कि यह तालमेल केवल जिला परिषद की सत्ता तक सीमित रहेगा या भविष्य की व्यापक राजनीति को भी प्रभावित करेगा। फिलहाल कांग्रेस-भाजपा के साथ आने से लाहौल-स्पीति में पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों पर बहस तेज हो गई है।

जिला परिषद में बदले समीकरणों के बीच आने वाले दिनों में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। कांग्रेस और भाजपा के इस अप्रत्याशित तालमेल ने विकास मंच की भूमिका को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

विकास मंच के दो सदस्यों की भूमिका पर उठे सवाल

जिला परिषद में बने इस समीकरण के बाद राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र डॉ. रामलाल मारकंडा का विकास मंच और उसके दो निर्वाचित सदस्य हैं। कांग्रेस नेता गौतम ठाकुर ने दावा किया कि डॉ. मारकंडा भाजपा आलाकमान के संपर्क में हैं और भाजपा के एक बड़े नेता से लगातार संवाद में रहते हैं। ठाकुर ने आरोप लगाया कि इसी राजनीतिक संपर्क के चलते विकास मंच के दो जिला परिषद सदस्यों ने भाजपा की देचेन ठिल्ले को अध्यक्ष बनाने में समर्थन दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि दो बार मंत्री रह चुके अनुभवी नेता बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ या शर्त के भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में क्यों आए। ठाकुर का यह भी दावा है कि भाजपा नेतृत्व लाहौल-स्पीति में कांग्रेस को चुनौती देने की स्थिति में डॉ. मारकंडा को महत्वपूर्ण राजनीतिक चेहरा मानता है।

जोगिंदर नगर की नौ पंचायतें टीबी मुक्त, 'जोश टीम' का शुभारंभ



भारतेन्दु संवाददाता, जोगिंदर नगर। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जोगिंदर नगर एसडीएम कार्यालय में 'जोश टीम' के शुभारंभ को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम मनीश चौधरी ने की। इस दौरान उन्होंने टीम में शामिल पांच एनसीसी कैडेट्स और पांच माय भारत स्वयंसेवकों को टीबी रोग के प्रति जागरूक किया।

एसडीएम ने युवाओं से टीबी उन्मूलन अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवक लोगों को टीबी के लक्षणों, बचाव, समय पर जांच और उपचार के बारे में जागरूक करें। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य केवल स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी जरूरी है। युवा स्वयंसेवक और पंचायत प्रतिनिधि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

◆ टीबी उन्मूलन अभियान में युवाओं की भागीदारी

नौ पंचायतें सम्मानित

इस अवसर पर एसडीएम ने उपस्थित लोगों को टीबी मुक्त हिमाचल और टीबी मुक्त भारत की शपथ दिलाई। बैठक के बाद उन्होंने टीबी मुक्त पंचायतों को प्रशस्ति पत्र और समृद्धि चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

विकासखंड चौंतड़ा की ग्राम पंचायत ऐहजू, बदेहड़, पीपली, कोलंग, खुड्डी और लड़भड़ोल को कांस्य पदक प्रदान किया गया। वहीं विकासखंड दरंग की ग्राम पंचायत चलाहरग को स्वर्ण तथा गुम्मा और बाता री बिहूं को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया।

हरियाणा में बनेगा अल्पसंख्यक आयोग, राज्यपाल ने दी मंजूरी

तीन साल का होगा अल्पसंख्यक आयोग के पदाधिकारियों का कार्यकाल, आयोग को मिलेंगी सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



हरियाणा में अल्पसंख्यकों के हितों और उनके अधिकारों की निगरानी के लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाएगा। राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम को मंजूरी दे दी है। नए कानून के तहत गठित होने वाला आयोग अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े मामलों की निगरानी करने के साथ उनके अधिकारों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित विषयों पर सरकार को सुझाव और सिफारिशें देगा। आयोग को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए सिविल कोर्ट जैसी कुछ शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। इसके तहत आयोग किसी व्यक्ति को बुलाकर उससे पूछताछ कर सकेगा, जरूरी दस्तावेज तलब कर सकेगा और सरकारी कार्यालयों से संबंधित रिकॉर्ड हासिल कर सकेगा। इसके अलावा गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए भी आयोग आवश्यक आदेश जारी कर सकेगा। किसी मामले की जांच के दौरान सरकार की मंजूरी से सरकारी एजेंसियों की सहायता भी ली जा सकेगी।

राज्य अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच गैर-सरकारी सदस्य होंगे। हालांकि सरकार आवश्यकता के अनुसार सदस्यों की संख्या में बदलाव कर सकेगी। अध्यक्ष पद के लिए सामाजिक क्षेत्र में अनुभव और प्रतिष्ठा रखने वाले व्यक्ति का चयन किया जाएगा। वहीं उपाध्यक्ष के लिए अल्पसंख्यकों के कल्याण, शिक्षा, अधिकारों की सुरक्षा, सामाजिक विकास या आर्थिक सशक्तीकरण से जुड़े कार्यों का अनुभव होना आवश्यक होगा। आयोग के प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए हरियाणा सिविल सेवा के एक अधिकारी को सचिव नियुक्त किया जाएगा। इससे आयोग के कामकाज को व्यवस्थित रूप से संचालित करने और विभिन्न विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी।

कानून के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पदभार संभालने की तारीख से तीन वर्ष का होगा। सरकार को निर्धारित परिस्थितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटाने का अधिकार भी दिया गया है। इनमें दिवालिया होना, गंभीर अपराध में दोषसिद्ध होना, कार्य करने में असमर्थता, लगातार तीन बैठकों में बिना अनुमति अनुपस्थित रहना अथवा पद का दुरुपयोग करना शामिल है।

आयोग के समक्ष बयान रहेगा सुरक्षित

आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति की ओर से दिया गया बयान भी कानून के तहत संरक्षित रहेगा। झूठी गवाही के मामले को छोड़कर आयोग के सामने दिया गया बयान किसी दीवानी या आपराधिक मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

आयोग देगा सरकार को रिपोर्ट और सिफारिशें

नए कानून में आयोग को सरकार के समक्ष समय-समय पर अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति से जुड़े विषयों का अध्ययन कर सरकार को आवश्यक कदम उठाने की सलाह दे सकेगा। सरकार को आयोग की सिफारिशों पर की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी विधानमंडल के समक्ष रखनी होगी। इस व्यवस्था से आयोग की सिफारिशों पर सरकारी कार्रवाई को सार्वजनिक जवाबदेही से जोड़ने का प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर नए कानून के लागू होने से हरियाणा में अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों की संस्थागत निगरानी के लिए एक अलग व्यवस्था स्थापित होगी।

पंचकूला में कांग्रेस का प्रदर्शन पैदल मार्च से गरमाई सियासत

भारतेन्दु संवाददाता, पंचकूला

'लोकतंत्र बचाओ सप्ताह' और कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी 'वोट बचाओ-देश बचाओ' अभियान के तहत हरियाणा कांग्रेस की ओर से पंचकूला में विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। कांग्रेस

◆ **लोकतंत्र बचाओ सप्ताह में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन**

कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर अपनी आवाज बुलंद की और सेक्टर-17 स्थित राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय की ओर कूच किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव व्यवस्था बेहद जरूरी है तथा मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।

प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। सेक्टर-17 तथा राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए भी आवश्यक प्रबंध किए। मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित न हो, इसके लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया।

बाजार में उच्च गुणवत्ता वाली चेरी की मांग

कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पैदल मार्च के कारण क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि मताधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है और चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता को लेकर जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रशासन की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया। कांग्रेस का यह अभियान प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी जारी रखने की बात कही गई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि 'वोट बचाओ-देश बचाओ' अभियान के माध्यम से लोकतांत्रिक अधिकारों और चुनावी पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों को जनता के बीच प्रमुखता से उठाया जाएगा।

हरियाणा में 23.31 लाख एकड़ मिसमैच भूमि का 91 फीसदी सत्यापन पूरा

मिसमैच भूमि के सत्यापन में जुटे प्रदेश के 4400 पटवारी

भारतेन्दु संवाददाता, भिवानी

हरियाणा के 23 जिलों में किसानों की फसल संबंधी जानकारी में सामने आए 23 लाख 31 हजार 540 एकड़ मिसमैच भूमि के भौतिक सत्यापन का काम 91 प्रतिशत पूरा हो चुका है। कृषि एवं राजस्व विभाग के करीब 4400 पटवारी इस कार्य में जुटे हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार शेष भूमि का सत्यापन भी जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। मिसमैच डाटा के कारण किसानों को फसल बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पोर्टल पर भूमि और फसल संबंधी जानकारी में अंतर दर्ज होने के चलते उन्हें सरकारी खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और निजी बोली पर भावांतर भरपाई का लाभ मिलने में दिक्कत आ रही है। भौतिक सत्यापन पूरा होने के बाद ही पोर्टल पर दर्ज मिसमैच डाटा को दुरुस्त किया जा सकेगा और किसानों के लिए फसल बिक्री की प्रक्रिया आसान होगी।

प्रदेश में सबसे अधिक भौतिक सत्यापन कुरुक्षेत्र जिले में हुआ है, जहां 99.89 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके बाद अंबाला में 99.50 प्रतिशत भूमि का सत्यापन हो चुका है। वहीं सिरसा जिले में सत्यापन की प्रगति सबसे कम 69.97 प्रतिशत है। विभाग की ओर से सभी जिलों में सत्यापन कार्य को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। पटवारी किसानों की ओर से मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर दर्ज की गई जानकारी का मौके पर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। यह स्थिति उस समय सामने आई जब किसानों ने अपनी फसल का विवरण पोर्टल पर दर्ज कराया और बाद में उपलब्ध उपग्रह चित्रों से उसका मिलान किया गया।



फाइल फोटो

◆ **मिसमैच डाटा से किसानों की बढ़ी परेशानी**

पोर्टल पर गलत भूमि डाटा होगा दुरुस्त

भिवानी जिले में प्रदेश में सबसे अधिक 3 लाख चार हजार 744 एकड़ भूमि का डाटा मिसमैच सामने आया था। जिले में 200 से अधिक पटवारी इस सत्यापन कार्य में लगाए गए हैं। दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के राज्य उपप्रधान विकास राठी के अनुसार प्रदेशभर में पटवारियों ने अब तक 91.33 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है और शेष डाटा का सत्यापन भी जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। भिवानी तहसीलदार जयवीर सिंह ने बताया कि जिले में सत्यापन कार्य अंतिम चरण में है और रिपोर्ट तैयार होने के बाद पोर्टल पर मिसमैच डाटा को दुरुस्त किया जा सकेगा।

बीबीएमबी में तैनाती से नहीं बदलेगा हरियाणा कर्मचारी का कैडर

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पंजाब के नंगल में पति की तैनाती के आधार पर हरियाणा सरकार की महिला कर्मचारी को दंपती मामले के तहत 10 मेरिट अंक देने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में हरियाणा के हिस्से के कोटे के पद पर कार्यरत कर्मचारी का मूल कैडर हरियाणा सरकार का ही रहता है। केवल कार्यस्थल पंजाब में होने से कर्मचारी की सेवा का मूल चरित्र नहीं बदलता। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग में नियमित सहायक प्रोफेसर (भौतिकी) के पद पर कार्यरत महिला कर्मचारी की याचिका स्वीकार करते हुए उसे दंपती मामले के तहत 10 मेरिट अंक देने के निर्देश दिए। कोर्ट ने सरकार को संशोधित मेरिट के आधार पर उसके तबादले के दावे पर दोबारा विचार करने को भी कहा।

संत समागम के लिए रेलवे ने 34 ट्रेनों को दी मंजूरी

हिमाचल के श्रद्धालुओं की मांग, संत समागम के लिए हिमाचल एक्सप्रेस भी रोकी जाए

भारतेन्दु संवाददाता, करनाल

संत निरंकारी मंडल के 79वें वार्षिक अंतरराष्ट्रीय संत समागम को लेकर रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष तैयारी की है। समागम 23 से 27 अक्टूबर तक पानीपत जिले के समालखा स्थित संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर आयोजित होगा। यह स्थल दिल्ली-अंबाला रेलखंड पर भोडवाल माजरी रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है। समागम में देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए रेलवे ने कई प्रमुख ट्रेनों को भोडवाल माजरी स्टेशन पर अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है।

उत्तर रेलवे ने 20 सितंबर से 31 अक्टूबर तक 34 ट्रेनों के दो मिनट के अस्थायी ठहराव को मंजूरी दी है। इनमें कई महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं, जिनका करनाल रेलवे स्टेशन पर भी नियमित ठहराव है।



ऐसे में करनाल और आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं को समागम स्थल तक पहुंचने में सुविधा होगी। प्रस्तावित ट्रेनों में 15707 कटिहार-अमृतसर, 12471 स्वराज, 12473 सर्वोदय, 12217 संपर्क क्रांति, 12497 शान-ए-पंजाब, 12925 पश्चिम एक्सप्रेस, 14507 दिल्ली-फाजिल्का, 12715 सचखंड एक्सप्रेस, 12057 जनशताब्दी, 20433 जम्मू मेल, 18101 टाटा-जम्मू, 12413 पूजा एक्सप्रेस, 12445 उत्तर संपर्क क्रांति, 12449 गोवा संपर्क क्रांति, 11057 मुंबई-अमृतसर, 12919 मालवा, 11077 झेलम, 12311 नेताजी एक्सप्रेस और 22455 कालका एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनें शामिल हैं।

हिमाचल एक्सप्रेस के ठहराव की मांग

मंडल का कहना है कि हिमाचल एक्सप्रेस हिमाचल क्षेत्र के श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण ट्रेन है। डाउन हिमाचल एक्सप्रेस दिल्ली से आते हुए रात करीब दो बजे करनाल पहुंचती है, जबकि अप ट्रेन दिल्ली की ओर जाते समय रात करीब डेढ़ बजे करनाल में रुकती है। यदि भोडवाल माजरी में इसका ठहराव नहीं दिया गया तो हिमाचल और करनाल क्षेत्र से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को रात के समय करनाल या पानीपत उतरकर सड़क मार्ग से समालखा पहुंचना पड़ेगा। मंडल ने 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक हिमाचल एक्सप्रेस को भोडवाल माजरी में दो मिनट का अस्थायी ठहराव देने की मांग की है।

निवेश के नाम पर आठ करोड़ की ठगी मर्सिडीज दिखाकर लोगों को फंसाया

भारतेन्दु संवाददाता, पंचकूला

कढ़ी-चावल की रेहड़ी लगाने वाले राजेश उर्फ नाना पर ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोप है। साइबर क्राइम पुलिस की जांच में कथित तौर पर आठ करोड़ रुपये से अधिक के निवेश घोटाले का पता चला है। पुलिस के अनुसार राजेश को उसके दोस्त प्रमोद कंबोज ने ब्लूम कंपनी नामक पोर्टल से जोड़ा था। शुरुआत में राजेश ने इसमें 7,500 रुपये का निवेश किया। इसके बाद कंपनी बंद हो गई तो उसने दूसरी योजना में करीब दो लाख रुपये लगाए। पुलिस जांच के मुताबिक इसके बाद राजेश ने निवेशकों का अपना नेटवर्क तैयार करना शुरू किया और अधिक से अधिक लोगों को ऑनलाइन निवेश के नाम पर जोड़ने लगा।

जांच में सामने आया है कि राजेश ने निवेश पर आकर्षक रिटर्न का भरोसा दिलाकर लोगों को इस योजना में पैसा लगाने के लिए प्रेरित किया। उसके संपर्क में आने वाले कई लोगों ने कथित तौर पर अपनी जमा पूंजी और बचत की रकम निवेश कर दी। धीरे-धीरे निवेशकों की संख्या बढ़ती गई और रकम भी करोड़ों में पहुंच गई। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों, बैंक खातों और पैसों के लेनदेन की जांच कर रही है।



साइबर क्राइम पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कथित ठगी की रकम किन-किन खातों में पहुंची और इसमें अन्य लोग भी शामिल थे या नहीं। जांच एजेंसी डिजिटल लेनदेन, निवेश पोर्टल से जुड़े दस्तावेज और आरोपितों के संपर्क में रहे लोगों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस का कहना है कि ऑनलाइन निवेश से जुड़े मामलों में लोगों को बिना सत्यापन किसी योजना में पैसा लगाने से बचना चाहिए। खासकर कम समय में अत्यधिक मुनाफे का लालच देने वाली योजनाओं को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है। मामले की जांच जारी है और पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाल रही है।

मुस्लिम परिवारों के हाथों सजे रावण, दिखी गंगा-जमुनी तहजीब

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा में दशहरे के अवसर पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले तैयार करने की परंपरा सांप्रदायिक सौहार्द और सांझी संस्कृति की अनूठी मिसाल बन रही है। पानीपत में मुस्लिम परिवार कई दशकों से रामलीला के पुतले तैयार कर रहे हैं। असगर अली का परिवार इस हुनर को पीढ़ियों से आगे बढ़ा रहा है। उनके बेटे भी नौकरी और आधुनिक पेशे के विकल्पों के बावजूद पारिवारिक कारीगरी में हाथ बंटाते हैं। इस बार करीब 50 कारीगरों की टीम पानीपत के अलग-अलग रामलीला मैदानों के लिए बड़े आकार के पुतले तैयार कर रही है।

यमुनानगर में रावलपिंडी से चली पुतले बनाने की कारीगरी करीब चार दशक बाद भी जारी है। महेंद्र मनचंदा का परिवार इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। महंगाई के कारण सुतली, कौड़ी और कपड़े समेत पुतले बनाने की सामग्री की लागत काफी बढ़ गई है, लेकिन कारीगरों का उत्साह कम नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र में पुतले बनाने का हुनर कैथल से शुरू होकर पांचवीं पीढ़ी तक पहुंच चुका है। परिवार इस बार 101 फीट ऊंचा रावण तैयार कर रहा है और आसपास के कई क्षेत्रों के लिए भी पुतले बना रहा है। वहीं भिवानी में यह परंपरा वर्ष 1902 से चली आ रही है। यहां परिवार की कई पीढ़ियां इस कला को आगे बढ़ा रही हैं। समय के साथ पुतलों के आकार और डिजाइन बदले हैं, लेकिन बांस मोड़ने, कागज साधने और चेहरे में भाव भरने की कला आज भी जीवित है।



अजय चौटाला ने सरकार को घेरा एमएसपी और खाद पर उठाए सवाल

अजय चौटाला बोले, किसान परेशान, सरकार बनी हुई मूकदर्शक

भारतेन्दु संवाददाता, भिवानी

जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय चौटाला ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर किसानों, युवाओं और खिलाड़ियों से जुड़े मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी स्थिति इसके विपरीत है। मंडियों में बाजरा और धान की बिक्री को लेकर किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश का किसान खाद की किल्लत से भी जूझ रहा है और खाद लेने के लिए किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है।



◆ **अपराध, खाद संकट और एमएसपी को लेकर सरकार पर बरसे अजय**

अजय चौटाला भिवानी में पूर्व पार्षद भरपूर सांई के बेटे और लॉन टेनिस के राष्ट्रीय खिलाड़ी रोहित के निधन पर शोक जताने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। उन्होंने प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर भी कटाक्ष करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

उन्होंने चुनाव आयोग और केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। अजय चौटाला ने कहा कि चुनाव आयोग, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर जनता के पैसे के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया।

पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला के क्षेत्रीय दलों के वजूद संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय चौटाला ने कहा कि उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनके पिता, भाई, स्वयं उन्होंने या उनकी चौथी पीढ़ी ने क्षेत्रीय राजनीति के बिना क्या हासिल किया है। उन्होंने कहा कि रणजीत चौटाला दो बार राष्ट्रीय पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अजय चौटाला ने बताया कि जेजेपी की ओर से दो अक्टूबर से प्रदेशभर में जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है।

ड्रग-मुक्त हरियाणा के तहत न्यूट्रास्युटिकल्स की जांच तेज

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। 'ड्रग-मुक्त हरियाणा' अभियान के तहत प्रदेश सरकार ने अब न्यूट्रास्युटिकल्स, प्रोटीन पाउडर और ऊर्जा पेय की बिक्री और गुणवत्ता की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। फिटनेस और शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के नाम पर युवाओं को प्राकृतिक उत्पाद बताकर बेचे जा रहे इन पदार्थों की जांच की जा रही है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीमों ने प्रदेशभर में 61 स्थानों पर छापामारी कर 73 नमूने एकत्र किए हैं। इन नमूनों को जांच के लिए भेजा जा रहा है, ताकि उत्पादों में किसी प्रतिबंधित या हानिकारक पदार्थ की मिलावट का पता लगाया जा सके। विभाग ने विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नाबालिगों और गर्भवती महिलाओं को चिकित्सक की पर्ची के बिना प्रोटीन पाउडर और ऊर्जा पेय न बेचे जाएं। अधिकारियों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य युवाओं को ऐसे उत्पादों के संभावित दुरुपयोग और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से बचाना है।

रेजांगला में वीर सैनिकों के सम्मान में झुके सिर

गुरुग्राम में वायु सेना दिवस पर वीर सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम

आसमान की ऊंचाइयों से देश की सीमाओं की रक्षा करने वाली भारतीय वायु सेना के शौर्य, साहस और पराक्रम को वायु सेना दिवस पर श्रद्धापूर्वक सलाम किया गया। बृहस्पतिवार सुबह रेजांगला युद्ध स्मारक पर आयोजित समारोह में पूर्व सैन्य अधिकारियों और क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को नमन किया। समारोह के दौरान वीर जवानों की बहादुरी और उनके अदम्य साहस को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

वक्ताओं ने कहा कि भारतीय वायु सेना के जवान विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा और साहस के साथ करते हैं। देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सैनिकों के बलिदान के कारण ही देशवासी सुरक्षित वातावरण में अपना जीवन जी पा रहे हैं।



इस अवसर पर वक्ताओं ने युवाओं से आह्वान किया कि वे वीर सैनिकों के जीवन और उनके त्याग से प्रेरणा लें। देशभक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य भावना के रूप में दिखाई देनी चाहिए। समारोह में उपस्थित लोगों ने देश की रक्षा में बलिदान देने वाले सभी वीर जवानों को नमन करते हुए उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

परेशानी सरकारी खरीद में देरी से किसान परेशान, मंडियों में बढ़ी बेचैनी

जींद में धान खरीद को लेकर किसानों का हंगामा प्रदर्शन

भारतेन्दु संवाददाता, पानीपत

प्रदेशभर की अनाज मंडियों में धान की आवक तेज होने के साथ ही सरकारी खरीद में देरी को लेकर किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। मंडियों में पीआर धान की सरकारी खरीद 29 सितंबर से शुरू हो चुकी है, लेकिन कई जिलों में राइस मिलर्स के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण खरीद एजेंसियां अपेक्षित गति से खरीद शुरू नहीं कर पा रही हैं। इससे मंडियों में धान लेकर पहुंच रहे किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है। बुधवार को जींद की अलेवा अनाज मंडी में धान की खरीद शुरू नहीं होने से नाराज किसानों ने जींद-असंध मार्ग के मुख्य चौक पर जाम लगा दिया।

किसानों का कहना था कि मंडियों में फसल पहुंचने के बाद भी खरीद में देरी होने से उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने मांग की कि सरकारी एजेंसियां तत्काल खरीद शुरू करें और मंडियों में फसल की तौल व उठान की व्यवस्था भी सुचारू की जाए।



मंडियों में धान की बंपर आवक, खरीद व्यवस्था पर उठे सवाल।

जींद जिले में अब तक 31,380 मीट्रिक टन धान मंडियों में पहुंच चुका है, जबकि केवल 5,253 मीट्रिक टन की खरीद हो सकी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आवक की तुलना में खरीद की गति कितनी धीमी है। वहीं अंबाला जिले की सभी मंडियों में पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि खरीद सीजन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। दूसरी ओर यमुनानगर में मंगलवार को हुई वर्षा ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों को आशंका है कि खुले में पड़ी फसल के भीगने से उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

दिल्ली के 21 हजार से ज्यादा परिवारों को मिलेगा पक्का घर, डीडीए ने शुरू की प्रक्रिया

डीडीए का बड़ा फैसला, दिल्ली के 45 झुग्गी क्लस्टरों में मिलेंगे पक्के मकान

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने राजधानी के 45 झुग्गी-झोपड़ी यानी जेजे क्लस्टरों के इन-सीटू पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन क्लस्टरों में रहने वाले करीब 21,229 परिवारों को उनकी मौजूदा जगह पर ही पक्के मकान उपलब्ध कराने की योजना है। इससे इन परिवारों को अपना इलाका छोड़कर दूर किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस योजना से एक लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।

अधिकारियों के अनुसार, डीडीए ने दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में करीब 135.74 एकड़ क्षेत्र में फैले इन 45 जेजे क्लस्टरों से संबंधित 15 परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए तीन लेन-देन सलाहकारों की नियुक्ति की जाएगी। डीडीए ने इस संबंध में प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए अनुरोध पत्र जारी किया है। चयनित सलाहकार इन झुग्गी क्लस्टरों की पुनर्वास संबंधी जरूरतों, उपलब्ध जमीन, विकास की संभावनाओं और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का विस्तृत आकलन करेंगे। इसके आधार पर परियोजनाओं को किस तरह विकसित किया जाए, इसका खाका तैयार किया जाएगा।

पुनर्वास के साथ अतिरिक्त आवास और व्यावसायिक विकास के लिए भी भूमि उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। इन-सीटू पुनर्वास का मुख्य उद्देश्य झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों को उनके मौजूदा सामाजिक और आर्थिक परिवेश से अलग किए बिना बेहतर आवास उपलब्ध कराना है। इससे लोगों को रोजगार, स्कूल, बाजार और अन्य



जरूरी सुविधाओं से दूर जाने की समस्या से भी बचाया जा सकेगा। इस योजना का संबंध दिल्ली के दीर्घकालिक शहरी विकास की व्यापक रणनीति से भी जोड़ा जा रहा है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अगस्त में दिल्ली के 2047 के मास्टर प्लान को अधिसूचित किया था। इसके तहत राजधानी में ऊंची इमारतों और अधिक घनत्व वाले नए क्षेत्रों के विकास का रास्ता साफ हुआ है।

योजना के व्यापक स्तर पर लागू होने पर दिल्ली के 650 से अधिक जेजे क्लस्टरों में रहने वाले करीब 17 लाख लोगों के इन-सीटू पुनर्वास का लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा चरण में डीडीए ने 45 क्लस्टरों को प्राथमिकता देते हुए प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। लेन-देन सलाहकारों का चयन आर्थिक मामलों के विभाग या राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के साथ सूचीबद्ध कंपनियों में से किया जाएगा।

राजघाट जाएंगे विपक्षी सांसद, दिल्ली के इन मार्गों पर लग सकता है भीषण जाम



विपक्षी मार्च से दिल्ली में जाम

एजेंसी ,नई दिल्ली

दिल्ली में विपक्षी सांसदों और इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन को देखते हुए यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस ने विशेष परामर्श जारी किया है। 8 अक्टूबर को प्रदर्शन का तीसरा दिन है। विपक्षी सांसदों ने घोषणा की है कि वे कनॉट प्लेस में दोपहर के भोजन के बाद राजघाट की ओर जाएंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों और वाहनों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन और पैदल मार्च के कारण राजघाट-किसान घाट रोड तथा आसपास के प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित हो सकता है।

पुलिस ने वाहन चालकों से इन मार्गों पर जाने से बचने और आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस की ओर से प्रमुख चौराहों और संवेदनशील मार्गों पर अतिरिक्त यातायात कर्मियों की तैनाती की जा सकती है। अधिकारियों का कहना है कि यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए स्थिति के अनुसार वाहनों का मार्ग बदला जा सकता है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा के लिए पर्याप्त अतिरिक्त समय लेकर निकलें।

कनॉट प्लेस से राजघाट की ओर विपक्षी सांसदों के जाने के दौरान मध्य दिल्ली के कई हिस्सों में वाहनों की गति प्रभावित होने की आशंका है। विशेष रूप से राजघाट, किसान घाट और आसपास के संपर्क मार्गों पर दबाव बढ़ सकता है। यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में वाहन लेकर न जाएं और पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें।

पति के इलाज के लिए संपत्ति बेचने की मांग, पत्नी ने हाई कोर्ट से लगाई गुहार

एजेंसी ,नई दिल्ली

गाजियाबाद की एक महिला ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपने कोमा में चल रहे पति के नाम दर्ज संपत्ति को बेचने की अनुमति मांगी है। महिला का कहना है कि पति के इलाज पर लगातार खर्च हो रहा है और परिवार के पास इलाज का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त धन नहीं बचा है। ऐसे में पति के नाम दर्ज संपत्ति बेचकर ही उपचार का खर्च पूरा किया जा सकता है।

महिला ने अदालत के समक्ष अपनी परेशानी रखते हुए संपत्ति बेचने की अनुमति देने की गुहार लगाई है। याचिका में बताया गया कि उसके पति की तबीयत गंभीर है और वह कोमा में हैं। उनकी देखभाल और इलाज के लिए लगातार आर्थिक संसाधनों की जरूरत पड़ रही है।

पत्नी के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि संपत्ति पति के नाम दर्ज है और उनकी वर्तमान स्थिति के कारण वह स्वयं संपत्ति की बिक्री से संबंधित आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में सक्षम नहीं हैं। इसी वजह से महिला ने न्यायालय का रुख किया है। महिला का कहना है कि पति के इलाज को जारी रखने के लिए संपत्ति ही आर्थिक सहारा है।

गुरुग्राम नगर निगम का एक्शन, कचरा फेंकने वाले पर 10 हजार का चालान



एजेंसी ,नई दिल्ली

नमो भारत ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को जल्द ही यात्रा के दौरान भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति और समृद्ध विरासत को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एनसीआरटीसी) ने नमो भारत स्टेशनों के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विरासत को लोगों तक पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस समझौते का उद्देश्य नमो भारत स्टेशनों को केवल यात्रियों के आवागमन का केंद्र न रखकर उन्हें भारतीय कला और संस्कृति के प्रचार-प्रसार के महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित करना है। इसके तहत स्टेशनों पर विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। यात्रियों को साहित्यिक कार्यक्रमों, कला प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं और अन्य सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से देश की विविध विरासत से परिचित कराया जाएगा।

इस पहल से यात्रियों को अपनी दैनिक यात्रा के दौरान भारतीय इतिहास और संस्कृति को समझने का अवसर मिलेगा। साथ ही, स्थानीय और पारंपरिक कला को भी नया मंच मिलने की उम्मीद है। स्टेशन परिसर में होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियां यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाएंगी तथा सार्वजनिक परिवहन को संस्कृति से जोड़ने का काम करेंगी।

प्रयागराज में बसाई जाएगी नई हाईटेक टाउनशिप, भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू

एजेंसी ,नई दिल्ली

प्रयागराज-रीवा राजमार्ग से सटे घूरपुर के पास स्थित इरादतगंज हवाई पट्टी की भूमि अब शहर के विस्तार का नया केंद्र बनने जा रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में 400 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर हाईटेक टाउनशिप विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस परियोजना के जरिए प्रयागराज के नियोजित विस्तार को नई दिशा देने की योजना है। हाईटेक टाउनशिप विकसित करने के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संबंधित विभागों और अधिकारियों के स्तर पर जमीन को प्राधिकरण के अधीन लाने की कार्रवाई की जा रही है।

इसके साथ ही प्रस्तावित क्षेत्र में मौजूद अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। प्रशासन का उद्देश्य परियोजना के लिए भूमि को व्यवस्थित और



अतिक्रमण मुक्त करना है, ताकि विकास कार्यों में किसी तरह की बाधा न आए। इरादतगंज हवाई पट्टी का क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यह प्रयागराज-रीवा राजमार्ग के नजदीक स्थित है, जिससे प्रस्तावित टाउनशिप को प्रमुख सड़क मार्ग से बेहतर संपर्क मिलने की संभावना है। शहर के बढ़ते विस्तार और आवासीय जरूरतों को देखते हुए इस क्षेत्र को नए विकास केंद्र के रूप में तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। प्रस्तावित हाईटेक टाउनशिप में आधुनिक शहरी सुविधाओं को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है। नियोजित आवासीय क्षेत्र के साथ सड़क, जल निकासी, बिजली, पेयजल, हरित क्षेत्र और अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाओं को विकसित किया जा सकता है। इससे शहर पर बढ़ते आबादी और यातायात के दबाव को व्यवस्थित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। भूमि हस्तांतरण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी होने के बाद परियोजना के अगले चरण में विकास का विस्तृत खाका तैयार किया जाएगा।

'बोलती सड़क' से अगरबत्ती मशीन तक

एजेंसी, नई दिल्ली

मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सर छोटूराम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में गुरुवार को 'सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज-2026' के तहत विद्यार्थियों ने अपने तकनीकी प्रोजेक्ट और मॉडल प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में कुल 38 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया। विद्यार्थियों ने रोजमर्रा की समस्याओं को तकनीक के जरिए हल करने के लिए कई नए और उपयोगी विचार पेश किए। इनमें 'बोलती सड़क' का मॉडल खास आकर्षण रहा। इसके अलावा कृषि, जल संरक्षण, रोजगार और करियर मार्गदर्शन जैसे क्षेत्रों से जुड़े नवाचार भी प्रस्तुत किए गए। छात्रों ने अगरबत्ती सुखाने की मशीन समेत ऐसे मॉडल तैयार किए, जिनका उद्देश्य काम को आसान बनाना और समय तथा संसाधनों की बचत करना है। प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों ने अपने प्रोजेक्ट की कार्यप्रणाली, उपयोगिता और संभावित लाभ के बारे में जानकारी दी।

न्यूज ब्रीफ

रेवाड़ी के स्कूलों में बदली बच्चों की थाली, अब मिलेंगे रागी-मिलेट और सोया



एजेंसी ,नई दिल्ली रेवाड़ी के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मिड-डे मील का नया शेड्यूल जारी किया गया है। अब विद्यार्थियों को हर दिन अलग-अलग पौष्टिक व्यंजन परोसे जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से तैयार नए मेन्यू में करीब 20 तरह के व्यंजन शामिल किए गए हैं। बच्चों की थाली में अब कढ़ी-पकौड़ा-चावल, सोया खिचड़ी, रागी का पुआ और राजमा-चावल जैसे व्यंजन मिलेंगे। इसके अलावा रागी और अन्य मिलेट आधारित पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी भोजन का हिस्सा बनाए गए हैं। नए मेन्यू का उद्देश्य बच्चों को स्वादिष्ट भोजन के साथ जरूरी पोषण उपलब्ध कराना है। प्रतिदिन अलग व्यंजन मिलने से बच्चों को भोजन में विविधता भी मिलेगी। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को नए शेड्यूल के अनुसार मिड-डे मील तैयार कर बच्चों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। रेवाड़ी के सरकारी स्कूलों में बच्चों के पोषण को ध्यान में रखते हुए मिड-डे मील का नया मेन्यू लागू किया गया है। शिक्षा विभाग ने नया शेड्यूल जारी करते हुए भोजन में कई पौष्टिक विकल्प जोड़े हैं।

प्रयागराज में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन भवन का हिस्सा गिरने से एक की मौत



एजेंसी, नई दिल्ली प्रयागराज के खुल्दाबाद इलाके में गुरुवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। नगर निगम के निर्माणाधीन जोनल कार्यालय भवन का एक हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे के दौरान मलबे की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया गया कि मृतक किसी काम से वहां खसरा बनवाने के लिए आया था। इसी दौरान निर्माणाधीन भवन का हिस्सा अचानक गिर पड़ा और वह मलबे में दब गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल राहत और बचाव की कोशिश शुरू की। हादसे की सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारी और बचाव दल मौके पर पहुंचे। मलबा हटाकर दबे व्यक्ति को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद निर्माणाधीन भवन की सुरक्षा व्यवस्था और निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन की ओर से हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं। इस दर्दनाक हादसे से मृतक के परिवार में मातम पसरा है। अधिकारियों ने घटना की जानकारी जुटाकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

गुरुग्राम में सियासी हलचल तेज, 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर कांग्रेस का विरोध मार्च

एजेंसी ,नई दिल्ली

गुरुग्राम में चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस तथा इंडिया गठबंधन ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज डावर ने किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और गठबंधन के नेताओं ने कमान सराय स्थित कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च शुरू किया और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए आगे बढ़े। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सवाल उठाए और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की।

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों के जरिए योग्य मतदाताओं के नाम प्रभावित किए जा रहे हैं। पार्टी ने इन आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी उठाई है। इस प्रदर्शन में हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह,



हरियाणा प्रभारी संजय दत्त और पूर्व सांसद राज बब्बर समेत कई नेता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी रखी।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उठ रहे सवालों का पारदर्शी तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए। पंकज डावर ने कहा कि कांग्रेस मतदाताओं के अधिकार और चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता के मुद्दे को लेकर अपनी आवाज उठाती रहेगी। वहीं गठबंधन के नेताओं ने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की अनियमितता लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनता के विश्वास से जुड़ा गंभीर विषय है।

रेवाड़ी नगर परिषद के नए वाइस चेयरमैन बने निखिल मांढैया

एजेंसी ,नई दिल्ली

रेवाड़ी नगर परिषद के बहुप्रतीक्षित वाइस चेयरमैन पद के चुनाव में वार्ड नंबर 12 के पार्षद निखिल मांढैया ने जीत हासिल कर ली है। कड़े और सीधे मुकाबले में उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी पार्षद चेतराम सैनी को पांच मतों के अंतर से हराया। चुनाव में निखिल मांढैया को कुल 19 वोट मिले, जबकि चेतराम सैनी उनके मुकाबले पीछे रह गए। निखिल की जीत के साथ ही रेवाड़ी नगर परिषद को नया वाइस चेयरमैन मिल गया है। इस चुनाव को स्थानीय राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि लंबे समय से इस पद को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज थीं। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद निखिल मांढैया के समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। समर्थकों ने उनकी जीत पर बधाई दी और उम्मीद जताई कि नए वाइस चेयरमैन के नेतृत्व में नगर परिषद के विकास कार्यों को गति मिलेगी।

'मैं जिंदा हूं, बचा लो'... सीमापुरी हादसे में गर्भवती गुलाफ्शां की दर्दनाक मौत

एजेंसी ,नई दिल्ली

दिल्ली के सीमापुरी इलाके में जर्जर पांच मंजिला भवन के अचानक ढहने से चार माह की गर्भवती गुलाफ्शां की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा सीमापुरी के ई-ब्लॉक में हुआ, जहां कमजोर और जर्जर इमारत देखते ही देखते मलबे में बदल गई। हादसे के वक्त गुलाफ्शां अपनी तीन वर्षीय बेटी के साथ डी-ब्लॉक स्थित अपनी मां से मिलने पहुंची थी। भवन गिरने के दौरान वह बाहर खड़ी थी, लेकिन अचानक गिरे मलबे की चपेट में आ गई।हादसे के बाद गुलाफ्शां मलबे के नीचे दब गई।

बताया गया कि वह काफी देर तक होश में थी और मोबाइल फोन के जरिए अपने पिता तथा बहन सबीना से संपर्क करती रही। उसने फोन पर बेहद दर्दनाक गुहार लगाते हुए कहा कि वह जिंदा है और उसे बचा लिया जाए। परिवार



के लोग उसकी आवाज सुनकर परेशान हो उठे और जल्द से जल्द बचाव दल के पहुंचने का इंतजार करने लगे। गुलाफ्शां की आवाज ने परिवार में उम्मीद जगाई थी कि उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का काम शुरू किया, लेकिन भारी मलबे के कारण राहत और बचाव कार्य में समय लगा। जब तक बचावकर्मी गुलाफ्शां तक पहुंच सके, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।

सबसे दर्दनाक बात यह रही कि गुलाफ्शां अपनी मां से मिलने के लिए घर से निकली थी और यही मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात बन गई। वह अपने पीछे तीन वर्षीय बेटी और परिवार को छोड़ गई। जर्जर भवनों को लेकर यह हादसा एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े करता है।

महिला सुरक्षा पर सर्वोच्च अदालत सख्त अपराध के बाद नहीं पहले हो रोकथाम



एजेंसी, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि अपराध होने के बाद कार्रवाई करने से ज्यादा जरूरी है कि अपराध को पहले ही रोका जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था का उद्देश्य केवल अपराधियों को सजा देना नहीं, बल्कि ऐसा सुरक्षित माहौल बनाना भी है, जहां असामाजिक तत्व किसी गलत काम को अंजाम देने से पहले ही डरें।

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी राजधानी दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता के बीच सामने आई है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस और प्रशासन को केवल शिकायत या घटना के बाद सक्रिय होने की बजाय पहले से प्रभावी कदम उठाने चाहिए। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाना, सार्वजनिक स्थानों की निगरानी मजबूत करना, सीसीटीवी व्यवस्था को प्रभावी बनाना और महिलाओं की शिकायतों पर तत्काल प्रतिक्रिया देना जरूरी है। अदालत का संदेश साफ है कि महिला सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। इसके लिए प्रशासन, न्याय व्यवस्था, स्थानीय संस्थाओं और पूरे समाज को मिलकर काम करना होगा। महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ यह भरोसा भी कायम करना जरूरी है कि किसी भी अपराध की स्थिति में उन्हें तत्काल सहायता और न्याय मिलेगा।

नए वायुसेना प्रमुख आशुतोष दीक्षित का आगरा से खास नाता, सी-295 सिम्युलेटर से जुड़ी याद

आशुतोष दीक्षित के वायुसेना प्रमुख बनने से फिर चर्चा में आया आगरा कनेक्शन

एजेंसी, नई दिल्ली

भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख आशुतोष दीक्षित का आगरा से गहरा और खास जुड़ाव रहा है। करीब दो वर्ष पहले मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के पद पर रहते हुए उन्होंने आगरा स्थित वायुसेना स्टेशन में सी-295 विमान के फुल मोशन सिम्युलेटर का शुभारंभ किया था। यह देश का एकमात्र फुल मोशन सिम्युलेटर बताया जाता है, जिसे सी-295 विमान के पायलटों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण देने के लिए तैयार किया गया है। आशुतोष दीक्षित ने सिम्युलेटर के शुभारंभ के दौरान नए सी-295 विमान से जुड़ी तकनीकी और परिचालन क्षमताओं की विस्तृत जानकारी ली थी।

उन्होंने वायुसेना के जवानों और अधिकारियों का उत्साह भी बढ़ाया था। उस समय उन्होंने नए विमान की क्षमताओं, प्रशिक्षण व्यवस्था और इसके संचालन से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया



आगरा से वायुसेना प्रमुख तक आशुतोष दीक्षित

था। अब वायुसेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभालने के बाद आगरा से उनका यह पुराना जुड़ाव एक बार फिर चर्चा में है। आगरा का वायुसेना स्टेशन भारतीय वायुसेना के महत्वपूर्ण ठिकानों में शामिल है। यहां एएन-32, आईएल-78 और सी-130जे समेत कई महत्वपूर्ण मालवाहक और विशेष भूमिका वाले विमान तैनात रहे हैं। परिवहन और सामरिक अभियानों में आगरा की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। इसी वजह से यहां आधुनिक विमानों के प्रशिक्षण और संचालन के लिए सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है।

सी-295 भी भारतीय वायुसेना के परिवहन बेड़े में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला आधुनिक विमान है। यह विमान स्पेन से खरीदा गया है और इसे विशेष रूप से सैनिकों, उपकरणों तथा अन्य आवश्यक सामग्री के परिवहन के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसकी प्रमुख खूबियों में छोटे रनवे से संचालन की क्षमता भी शामिल है। विमान लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम है और कठिन परिस्थितियों में भी उपयोगी साबित हो सकता है।

अलीगढ़-आगरा के बीच दौड़ेगा विकास का एक्सप्रेसवे, एक घंटे में पूरी होगी दूरी

एजेंसी ,नई दिल्ली

अलीगढ़ से आगरा के बीच 65 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। करीब 3200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह चार लेन का एक्सप्रेसवे दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बनने के बाद अलीगढ़ से आगरा की दूरी तय करने में लगने वाला समय करीब ढाई घंटे से घटकर महज एक घंटा रह जाएगा। यह एक्सप्रेसवे अलीगढ़ जिले की सीमा में पड़ियावली और बढ़ौली फत्तेखां से शुरू होकर हाथरस जिले के सासनी कस्बे के बाहर से होते हुए आगरा के खंदौली तक बनाया जाएगा।

इसका निर्माण अलीगढ़-आगरा राजमार्ग और अलीगढ़-मथुरा राज्य राजमार्ग के बीच खेतों से होकर किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे खंदौली के पास यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जबकि अलीगढ़ में दिल्ली-कानपुर राजमार्ग से इसका संपर्क होगा। इससे यात्रियों को आगरा और अन्य प्रमुख शहरों तक तेज और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। यह अलीगढ़ जिले का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। मौजूदा अलीगढ़-आगरा मार्ग सासनी, हाथरस और सादाबाद होते हुए आगरा पहुंचता है। करीब 85 किलोमीटर लंबा यह मार्ग वर्तमान में दो लेन का है और इस पर टोल भी लिया जाता है।

लगातार बढ़ते यातायात दबाव के कारण लंबे समय से इसे चौड़ा करने की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसी को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नए फोरलेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की योजना पर काम शुरू किया है। इसके पूरा होने से अलीगढ़ और आगरा के बीच संपर्क बेहतर होगा, यात्रा समय घटेगा और क्षेत्र में व्यापार तथा आवागमन को भी गति मिलने की उम्मीद है।

न्यूज ब्रीफ

दिव्यांगजनों के लिए 9 व 16 को चिकित्सा शिविर

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला बिलासपुर में दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 9 और 16 अक्तूबर को क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में चिकित्सा परीक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. शशि दत्त शर्मा ने शिविर के लिए जिला मेडिकल डिसेबिलिटी बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड में शिशु रोग, ईएनटी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, नेत्र रोग, मनोचिकित्सा और मेडिसिन विशेषज्ञों सहित विभिन्न चिकित्सकों व अधिकारियों को शामिल किया गया है। शिविर दोनों दिन प्रातः 10 बजे से अंतिम लाभार्थी के परीक्षण तक नए ओपीडी परिसर में आयोजित होगा। सीएमओ ने संबंधित दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि और समय पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में पहुंचकर चिकित्सा परीक्षण करवाएं और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी करें।

रास्ता रोककर मारपीट के तीन मामले दर्ज

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला बिलासपुर के घुमारवीं और तलाई थाना क्षेत्रों में रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने के तीन मामले सामने आए हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घुमारवीं के छंजियार में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट को लेकर क्रॉस केस दर्ज हुए हैं। मनोहर लाल और रीता देवी ने एक-दूसरे पर रास्ता रोकने, गाली-गलौज और मारपीट के आरोप लगाए हैं। दोनों शिकायतों पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं, तलाई थाना क्षेत्र के भदोल गांव निवासी विजय कुमार ने ठाकुर दास पर रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में भी केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने मामलों की पुष्टि की है।

ओडिशा के छात्रों से मिले मंत्री राजेश धर्माणी



भारतेन्दु संवाददाता, मनाली। 'युवा संगम-7' कार्यक्रम के तहत ओडिशा के विभिन्न शिक्षण संस्थानों से हिमाचल भ्रमण पर आए 59 छात्र-छात्राओं ने मनाली के माल रोड पर हिमाचल की संस्कृति और स्थानीय जीवन को करीब से जाना। ओडिशा के 32 जिलों से आए विद्यार्थी 1 से 10 अक्तूबर तक आईआईटी हमीरपुर सहित निर्धारित शिक्षण संस्थानों में आयोजित कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। प्रदेश के तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण तथा नगर एवं ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्माणी ने माल रोड पर विद्यार्थियों से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों से हिमाचल की संस्कृति, पर्यटन स्थलों और स्थानीय परंपराओं के बारे में बातचीत कर उनके अनुभव जाने। मंत्री ने विद्यार्थियों को स्थानीय संस्कृति और खान-पान से भी परिचित करवाया तथा उनके साथ मोमो का आनंद लिया। विद्यार्थियों ने हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता और आतिथ्य की सराहना की। इस अवसर पर मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ भी मौजूद रहे। 'युवा संगम' शिक्षा मंत्रालय की पहल है, जो युवाओं को विभिन्न राज्यों की संस्कृति और जीवनशैली समझने का अवसर देती है।

कांगड़ा अस्पताल से इकलौती नेत्र रोग विशेषज्ञ का तबादला, मरीजों की बढ़ी चिंता

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। कांगड़ा सिविल अस्पताल में इकलौती नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. नेहा का तबादला डॉ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश 7 अक्तूबर 2026 को स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंघमार ने जारी किया, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। जानकारी के अनुसार कांगड़ा अस्पताल की नेत्र ओपीडी में रोजाना करीब 70 से 80 मरीज पहुंचते हैं। इनमें बुजुर्गों में मोतियाबिंद और नजर की कमजोरी के साथ बच्चों की आंखों से जुड़ी समस्याओं तथा संक्रमण के मरीज शामिल हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक के तबादले से नेत्र रोगियों की नियमित जांच और उपचार प्रभावित होने की आशंका है। स्थानीय लोगों के अनुसार कांगड़ा शहर के अलावा आसपास के कई गांवों के लोग भी इलाज के लिए इस अस्पताल पर निर्भर हैं। सरकारी अस्पताल में कम खर्च पर उपचार मिलने के कारण गरीब और बुजुर्ग मरीज यहां पहुंचते हैं। डॉक्टर के स्थानांतरण के बाद मरीजों को टांडा मेडिकल कॉलेज या निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ सकता है।

विद्यार्थियों ने गायन, नृत्य में दिखाई प्रतिभा



भारतेन्दु संवाददाता, इंदौरा। इंदौरा स्थित वैष्णो कॉलेज में टैलेंट हंट प्रतियोगिता का आयोजन उत्साह और उमंग के साथ किया गया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने गायन, नृत्य, अभिनय सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध अभिनेता अभय वर्मा और अभिषेक वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कॉलेज प्रबंधन और विद्यार्थियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कॉलेज के एमडी शिवम पठानिया और तमन्ना पठानिया ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों को प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास का अवसर देते हैं। मुख्यातिथियों ने प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए विद्यार्थियों को निरंतर मेहनत और हुनर निखारने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सफलता के लिए अनुशासन और सकारात्मक सोच को जरूरी बताया। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. सुरेखा पठानिया, शिक्षकगण, कॉलेज प्रबंधन और विद्यार्थी मौजूद रहे। अंत में प्राचार्य ने सभी का आभार व्यक्त किया।

वन्य जीव संरक्षण के प्रति किया जागरूक



भारतेन्दु संवाददाता, बीड़। वन्य जीव सप्ताह समारोह-2026 के उपलक्ष्य में बीड़ फॉरेस्ट रेंज में विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। 6 अक्तूबर को पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बीड़ के एनएसएस स्वयंसेवकों के लिए नेचर वॉक और बर्ड वॉचिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को वन्य जीवों और पक्षियों के बारे में जानकारी दी गई तथा उनके संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। वहीं, 8 अक्तूबर को वन विश्राम गृह से क्यूरी तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ वेस्ट वॉरियर्स के सदस्यों तथा महिला मंडल लोअर बीड़ की महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी की। प्रतिभागियों ने क्षेत्र में सफाई कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। वन विभाग ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों, विशेषकर युवाओं में वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है।

ओल्ड बस स्टैंड के सार्वजनिक शौचालय को शिफ्ट करने का किया विरोध

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। नगर पंचायत अर्की के वार्ड नंबर 6 स्थित ओल्ड बस स्टैंड के सार्वजनिक शौचालय को अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की चर्चा का स्थानीय व्यवसायियों ने विरोध किया है। इस संबंध में व्यवसायियों ने नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा शर्मा को ज्ञापन सौंपकर शौचालय को वर्तमान स्थान से न हटाने की मांग की। व्यवसायियों ने बताया कि ओल्ड बस स्टैंड मुख्य बाजार क्षेत्र में स्थित है, जहां तीन बैंक, एलआईसी कार्यालय और कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। यहां रोजाना बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों, व्यापारियों और ग्राहकों की आवाजाही रहती है। अर्की मेले के दौरान भी क्षेत्र में हजारों लोग पहुंचते हैं। व्यवसायियों का कहना है कि सार्वजनिक शौचालय महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों, दिव्यांगजनों, व्यापारियों और बाजार आने वाले लोगों के लिए आवश्यक है। इसे हटाने से असुविधा बढ़ सकती है। उन्होंने नगर पंचायत से जनहित को ध्यान में रखते हुए वर्तमान स्थान पर ही शौचालय रखने और अंतिम निर्णय से पहले स्थानीय लोगों से परामर्श करने की मांग की।

राजनीतिक सफर में पिता का योगदान अहम : आशीष बुटेल

पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशीष बुटेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास और नगर निगम पालमपुर में पिछले पांच साल में हुए विकास कार्यों को लेकर भारतेन्दु शिखर से खुलकर बात की। भारतेन्दु शिखर की एंकर **'रीत वशिष्ठ'** ने कई विषयों पर उनसे बातचीत की। पेश हैं इस बातचीत के मुख्य अंश :-

सवालः नगर निगम चुनाव में पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 सीटें जीतीं, जबकि प्रदेश के अन्य नगर निगमों में भाजपा का प्रदर्शन बेहतर रहा। इस जीत को आप किस तरह देखते हैं?

जवाबः मैं इस जीत को विकास की जीत मानता हूं। पिछले पांच वर्षों से पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस की सरकार रही और हमने पूरे क्षेत्र में बेहतर काम करने का प्रयास किया। उस समय के सभी पार्षदों ने अपने-अपने क्षेत्रों में जनता की समस्याओं को समझते हुए काम किया। इसका लाभ हमें चुनाव में मिला। हमने 15 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की है। मेरा मानना है कि यह जीत सिर्फ और सिर्फ विकास के कामों के आधार पर मिली है। लोगों की व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याओं का समाधान करने पर हमारा विशेष ध्यान रहा है।

मुलाकात जो बदले हालात

सवाल : विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि पालमपुर सीट आपके परिवार की राजनीतिक विरासत है। इस पर आपका क्या कहना है?

जवाबः मेरे पिता का मेरी राजनीतिक यात्रा और जीत में बहुत बड़ा योगदान है और मैं इसे कभी नकारता नहीं हूं। आखिर वह मेरे पिता हैं और उनका योगदान सबसे पहला है। वर्ष 2017 में जब मुझे पहली बार कांग्रेस से टिकट मिला, उस समय मेरे पिता विधानसभा अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने बेटे के लिए अपनी सीट छोड़ी और मुझे पालमपुर से चुनाव लड़ने का अवसर दिया। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। 2017 में भी, 2022 में भी और 2027 के चुनाव में भी उनका आशीर्वाद और योगदान मेरे लिए महत्वपूर्ण रहेगा।

सवालः वर्ष 2017 में आप पहली बार विधायक बने। उस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। पालमपुर के लिए किए गए कौन से काम आपको सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं?

जवाबः राजनीति में सबसे जरूरी बात यह है कि जनता की जरूरत के अनुसार काम किया जाए। मैं यह नहीं मानता कि घर बैठकर यह तय कर दिया जाए कि किसी गांव या क्षेत्र में कौन सा काम होना चाहिए और फिर उसे जनता पर थोप दिया जाए। हमारी कोशिश रहती है कि लोग जिस काम की मांग करें, उसे प्राथमिकता दी जाए। सरकारी धन का सही और उचित स्थान पर इस्तेमाल होना चाहिए। जनता की जरूरत के अनुसार विकास कार्य करना ही हमारी प्राथमिकता रही है।

सवालः वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। पालमपुर में आप फिर से जीत का दावा कर रहे हैं। जनता से इस बार क्या उम्मीद रखते हैं?

जवाबः पालमपुर की जनता ने मुझे, मेरे पिता और मेरे पूरे परिवार को हमेशा प्यार और आशीर्वाद दिया है। मैं 2027 में भी जनता से उसी प्यार और आशीर्वाद की उम्मीद करता हूं। चुनाव में अंतिम फैसला जनता का होता है और जनता जिसे चाहेगी, उसे अपना समर्थन देगी। मैं चाहता हूं कि पालमपुर की जनता का विश्वास आगे भी मेरे साथ बना रहे।

मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान आपका नाम भी चर्चा में था। अगर भविष्य में दोबारा आपका नाम मंत्रिमंडल के लिए आता है, तो आपकी क्या अपेक्षा होगी?



यह फैसला मुख्यमंत्री और पार्टी हाईकमान को करना है। मंत्रिमंडल में एक सीट होती है और दावेदार कई होते हैं। हर विधायक को अपना दावा रखने का अधिकार है और सभी अपनी बात पार्टी के सामने रखते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर किसी को हर जिम्मेदारी मिल जाए। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा चला हूं और आगे भी पार्टी के साथ ही रहूंगा। पार्टी मुझे कोई जिम्मेदारी देगी, तो उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा और अगर जिम्मेदारी नहीं भी मिलती है, तब भी कांग्रेस के साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहूंगा।

सवालः आपने इंदु गोस्वामी और त्रिलोक कपूर जैसे दिग्गज नेताओं को भी चुनाव में हराया है। 2027 में भाजपा के सामने संभावित चुनौती को आप किस तरह देखते हैं?

जवाबः चुनाव आमने-सामने की लड़ाई होती है। अभी यह तय नहीं है कि भाजपा की ओर से कौन प्रत्याशी होगा। इंदु लड़ेंगी, त्रिलोक लड़ेंगे या कोई नया उम्मीदवार आएगा, यह भविष्य की बात है। हमें इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। भाजपा की ओर से जो भी प्रत्याशी मैदान में आएगा, मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच होगा और हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे।

सवालः 2027 के चुनाव को लेकर आपका रोडमैप क्या रहेगा और पालमपुर की जनता के लिए आपका संदेश क्या है?

जवाबः हमारा फोकस जनता की जरूरतों और क्षेत्र के विकास पर रहेगा। हम वही काम करना चाहते हैं, जिसकी जरूरत लोगों को है। पालमपुर की जनता ने हमेशा हमारा साथ दिया है और आगे भी हम जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा जुड़ाव मजबूत है और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे।

राष्ट्रपति कुल्लू की पारंपरिक संस्कृति व स्वाद की यादें साथ ले गईं

धनेश गौतम, भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मनाली दौरा वीरवार सुबह सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। राष्ट्रपति सासे हेलिपैड से दिल्ली के लिए रवाना हुईं। उनके प्रस्थान के साथ ही पिछले दो दिनों से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में जुटे प्रशासन व पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए मनाली और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को विशेष रूप से मजबूत किया गया था। मनाली से अटल टनल और हिडिंबा मंदिर तक सुरक्षा के साथ यातायात प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

राष्ट्रपति अपने मनाली प्रवास के दौरान कई यादें साथ लेकर रवाना हुईं। इस दौरान उन्होंने कुल्लू की पारंपरिक खान-पान संस्कृति का स्वाद लिया। जिला प्रशासन की ओर से उनके भोजन में स्थानीय व पारंपरिक व्यंजनों को विशेष रूप से शामिल किया गया। भोजन में ऐसे पारंपरिक अनाजों और स्थानीय उत्पादों को भी प्राथमिकता दी गई, जिनका इस्तेमाल आधुनिक खान-पान के दौर में धीरे-धीरे कम होता जा रहा है।



◆ द्रौपदी मुर्मू का मनाली दौरा सफलतापूर्वक संपन्न, सासे हेलिपैड से दिल्ली के लिए हुईं रवाना

गुच्छी, लाल चावल व राजमाह का लिया स्वाद

राष्ट्रपति ने रात्रि भोजन में गुच्छी की सब्जी, लाल चावल और राजमाह का स्वाद लिया। बुधवार सुबह उनके लिए कुट्टू और काउनी के आटे के पराठे तथा बेसा का सूप तैयार किया गया। दोपहर के भोजन में बाथू की खीर, कच्चे पपीते व खुमानी का मीठा, तोरी और भिंडी की सब्जी, गुच्छी व रागी का सूप, कद्दू और आंबले की सब्जी तथा लाल चावल परोसे गए। स्थानीय व्यंजनों के माध्यम से राष्ट्रपति के सामने कुल्लू की पारंपरिक खाद्य संस्कृति की विविधता भी प्रस्तुत की गई। पारंपरिक अनाजों, जड़ी-बूटियों और स्थानीय उत्पादों से तैयार व्यंजनों को विशेष रूप से शामिल किया गया।

राष्ट्रपति की एक झलक पाने को उमड़ी भीड़

राष्ट्रपति के मॉल रोड पहुंचने की जानकारी मिलते ही उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने उत्साह के साथ राष्ट्रपति का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने भी वहां मौजूद लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। राष्ट्रपति के मनाली प्रवास के दौरान कुल्लू के पारंपरिक व्यंजनों, स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प को मिली विशेष पहचान ने क्षेत्र की समृद्ध खान-पान एवं सांस्कृतिक परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर सामने लाने का अवसर दिया। राष्ट्रपति का यह दौरा मनाली और कुल्लू की प्राकृतिक सुंदरता के साथ यहां की पारंपरिक जीवनशैली और स्थानीय उत्पादों की भी यादें छोड़ गया।

तिब्बत एम्पोरियम में की खरीदारी

स्थानीय व्यंजनों के साथ राष्ट्रपति ने मनाली की स्थानीय खरीदारी में भी रुचि दिखाई। मॉल रोड पर सैर के दौरान उन्होंने तिब्बत एम्पोरियम का दौरा किया और वहां से खरीदारी की। उन्होंने बच्चों के आकार की चार तिब्बती शर्ट, पर्वतीय बेरी सीबकथोर्न पल्प की चार बोतलें, जड़ी-बूटियों से निर्मित दर्द निवारक तेल की पांच छोटी शीशियां, मछली के आकार का एक फिश लॉक और अगरबत्ती रखने के लिए एक डिब्बी खरीदी।

स्पेयर पार्ट्स नहीं देने पर एलजी को उपभोक्ता आयोग की फटकार

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। करीब 10 साल पुरानी वॉशिंग मशीन की मरम्मत के लिए स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध न करवाने पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कोताही का दोषी ठहराया है।

आयोग ने कंपनी को 45 दिनों के भीतर मशीन में वास्तविक पीसीबी पार्ट लगाकर उसे पूरी तरह ठीक करने का आदेश दिया है। मामला पालमपुर निवासी अमिता शर्मा की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन से जुड़ा है। उनके पति ने वर्ष 2015 के अंत में करीब 60 हजार रुपए में मशीन खरीदी थी। नवंबर 2025 में मशीन खराब होने पर कंपनी के सर्विस इंजीनियर ने जांच की, लेकिन मेन पीसीबी उपलब्ध न होने की बात कहकर शिकायत बंद कर दी गई। इसके बाद महिला ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान कंपनी ने दावा किया कि मशीन की उम्र सात वर्ष है और संबंधित पार्ट्स का उत्पादन वर्ष 2022 में बंद हो चुका था।

◆ कहा- कंपनी 45 दिनों में मशीन की मरम्मत करे

आयोग अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की पीठ ने कंपनी के इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया। आयोग ने कहा कि खरीद के समय उपभोक्ता को मशीन की सीमित उपयोग अवधि की जानकारी नहीं दी गई थी। आयोग ने निर्देश दिया कि मरम्मत में विफल रहने पर कंपनी 15 हजार रुपए की बाय-बैक राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देगी। इसके अलावा मानसिक परेशानी और वित्तीय नुकसान के लिए 25 हजार रुपए तथा कानूनी खर्च के रूप में 10 हजार रुपए देने के आदेश दिए गए हैं।

टांडा अस्पताल में मरीजों के बैठने की जगह के सामने खुला मेन चैंबर

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज व अस्पताल टांडा में मरीजों व तीमारदारों की सुविधा के लिए कुर्सियां तो लगा दी गई हैं, लेकिन इन कुर्सियों के ठीक सामने फर्श में बना मेन चैंबर खुला पड़ा है। मरीज यहां बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, जबकि सामने खुला गहरा चैंबर हादसे को न्योता दे रहा है।



अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज और तीमारदार पहुंचते हैं। ऐसे में खुले चैंबर से किसी भी समय दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और चलने-फिरने में असमर्थ मरीजों के लिए यह स्थिति अधिक जोखिमपूर्ण हो सकती है। चैंबर के आसपास न तो बैरिकेडिंग की गई है और न ही लोगों को सावधान करने के लिए कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है। मरीजों का कहना है कि बैठने की व्यवस्था करना अच्छी पहल है, लेकिन उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है। अस्पताल प्रशासन से खुले चैंबर को जल्द सुरक्षित करने की मांग उठ रही है, ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इस संबंध में टांडा अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉ. विवेक बुनियाल ने कहा कि उन्हें खुले चैंबर की जानकारी नहीं है। उन्होंने संभावना जताई कि इसे सफाई के लिए खोला गया होगा। उन्होंने कहा कि चैंबर को जल्द ठीक करवाया जाएगा और वहां लगी बेंचों को हटाकर लोगों के आने-जाने के लिए रास्ता बनाया जाएगा।

पेंशनर्स की लंबित मांगों को लेकर फेडरेशन ने उठाई आवाज

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। हिमाचल पेंशनर्स फेडरेशन अर्की इकाई की बैठक अध्यक्ष मदन लाल गर्ग की अध्यक्षता में हुई। जिलाध्यक्ष जयनंद शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में इकाई सदस्य प्रकाश चंद गुप्ता के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बैठक में पेंशनरों की विभिन्न लंबित मांगों पर चर्चा करते हुए सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की गई। सदस्यों ने दीवाली से पहले लंबित महंगाई भत्ते (डीए) की किस्तें जारी करने, वित्तीय लाभों का भुगतान करने और चिकित्सा बिलों का जल्द निपटारा करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य खर्च को देखते हुए चिकित्सा बिलों का समय पर भुगतान जरूरी है। इस अवसर पर गोपाल गुप्ता, श्याम लाल पाल, रमेश कुमार सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

कांगड़ा में टीबी-मुक्त भारत अभियान के तहत 'जोश' टीमों का शुभारंभ

युवा शक्ति व जनभागीदारी से टीबी उन्मूलन पर जोर

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। जिला कांगड़ा में टीबी-मुक्त भारत अभियान के तहत 'जोश' संयुक्त स्वास्थ्य टीमों का जिला स्तरीय शुभारंभ सांसद कांगड़ा-चंबा डॉ. राजीव भारद्वाज ने किया।



इस पहल का उद्देश्य युवा शक्ति, सामुदायिक सहभागिता और जनभागीदारी के माध्यम से टीबी उन्मूलन के प्रयासों को गति देना है। कार्यक्रम के दौरान जिला टीबी-मुक्त भारत समिति की बैठक हुई और नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम में जिले ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। जोश टीमों का उन्मुखीकरण, टीबी जागरूकता गतिविधियां, सामूहिक शपथ तथा अभियान की प्रचार सामग्री का भी शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा एवं खेल, पंचायती राज, आयुष, एनसीसी, एनएसएस, माई भारत, आईएमए सहित विभिन्न विभागों और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में टीबी उन्मूलन में योगदान देने वाले निक्षय मित्रों, टीबी विजेताओं, माई भारत स्वयंसेवकों और युवा प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया।

गुंजन संस्था के संदीप और विजय को सामुदायिक सहयोग के लिए विशेष सम्मान मिला। वहीं, श्री सत्य साईं सेवा संगठन, रोटरी क्लब धर्मशाला, लायंस क्लब और इनर व्हील क्लब के प्रतिनिधियों को टीबी मरीजों के लिए पोषण सहयोग उपलब्ध कराने के लिए सम्मानित किया गया। कांगड़ा जिले की 287 ग्राम पंचायतों को टीबी-मुक्त ग्राम पंचायत के रूप में प्रमाणित किया गया है, जिनमें 37 स्वर्ण, 69 रजत और 181 कांस्य श्रेणी की पंचायतें शामिल हैं। जिले में टीबी की सक्रिय खोज, निवारक उपचार, पोषण सहयोग और जागरूकता गतिविधियां जारी हैं। सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने युवाओं, स्वास्थ्य कर्मियों, पंचायत प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से टीबी उन्मूलन को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने जोश टीमों से लोगों को लक्षणों, समय पर जांच और उपचार के प्रति जागरूक करने तथा टीबी से जुड़े भ्रम और भेदभाव को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में उपायुक्त हेमराज बैरवा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

विद्यालय विकास में एसएमसी की भूमिका पर हुई चर्चा

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। पीएम श्री राजकीय आदर्श माध्यमिक पाठशाला बंजार सीबीएसई में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) सदस्यों के लिए एकदिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालय विकास में एसएमसी की भूमिका को प्रभावी बनाना तथा विद्यार्थियों के शैक्षणिक और सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय, अभिभावकों व समुदाय के बीच समन्वय मजबूत करना रहा। प्रशिक्षण में एसएमसी की भूमिका, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, सीखने के परिणाम, अभिभावक सहभागिता, बाल अधिकार, विद्यार्थी कल्याण, समावेशी शिक्षा और सुरक्षित विद्यालय वातावरण जैसे विषयों पर चर्चा की गई। प्रधानाचार्य डॉ. धर्म पाल सहित शिक्षकों ने विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन दिया। समूह चर्चा, प्रश्नोत्तर और इंटरैक्टिव गतिविधियों के माध्यम से सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी की। समापन पर प्रधानाचार्य ने कहा कि विद्यालय का विकास सामूहिक सहभागिता से संभव है। उन्होंने एसएमसी सदस्यों से प्रशिक्षण में प्राप्त जानकारी को व्यवहार में लाने और विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया।

आखिरी सांस तक राजा वीरभद्र सिंह रहेंगे मेरे आदर्श : सुधीर शर्मा

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। धर्मशाला के विधायक व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर तीखे राजनीतिक हमले किए। उन्होंने अपने खिलाफ चल रही विजिलेंस जांच और वित्तीय लेन-देन से जुड़े आरोपों पर कहा कि उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेची है और उसकी राशि उनके खाते में ही आई है।

उन्होंने कहा कि लेन-देन बैंक के माध्यम से हुआ है और सरकार को जांच रिपोर्ट जल्द अदालत में पेश करनी चाहिए। सुधीर शर्मा ने सरकार द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों को ध्यान भटकाने वाला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी गारंटियां पूरी नहीं होने के कारण सरकार जनता का ध्यान दूसरे मुद्दों की ओर ले जा रही है। प्रदेश में दर्ज हो रही एफआईआर पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस को वास्तविक अपराध और नशे से जुड़े मामलों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। दलबदल और बिकाऊ होने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में मतदान से संबंधित नियमों का पालन किया गया था। उन्होंने दावा किया कि धर्मशाला की जनता ने उपचुनाव में उन्हें पहले से अधिक अंतर से जीत दिलाकर अपना समर्थन जताया। वीरभद्र सिंह के साथ अपने संबंधों पर सुधीर शर्मा ने कहा कि वे उन्हें अपना राजनीतिक गुरु और आदर्श मानते हैं। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह की तस्वीर आज भी उनके घर और कार्यालय में लगी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, लेकिन वीरभद्र सिंह को नहीं।



◆ कहा- चुनावी गारंटियां पूरी न होने के कारण सरकार जनता का ध्यान दूसरे मुद्दों की ओर ले जा रही

टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अर्की की 19 पंचायतें सम्मानित

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। सिविल अस्पताल अर्की में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में टीबी उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ब्लॉक अर्की की 19 ग्राम पंचायतों के प्रधान व उपप्रधानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीएमओ डॉ. मुक्ता रस्तोगी ने की, जबकि एसडीएम निशांत तोमर मुख्यातिथि और बीडीओ तन्मय कंवर विशेष रूप से मौजूद रहे। डुमैहर, मांगल और प्लानिया पंचायतों को गोल्ड मेडल, जबकि दानोघाट, खनलग और सहरोल को सिल्वर मेडल प्रदान किए गए। बखालग, बनोह-खरड़हट्टी, बरयाली, चईयांधार, चाखड़, दधोघी, कोटलु, रोहांज-जलाना, समोग, सानन, सरयांज और मटेरनी सहित अन्य पंचायतों को ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। एसडीएम ने टीबी के लक्षणों, समय पर जांच और उपचार के प्रति जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। बीएमओ ने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ पंचायतों और आम जनता की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम



भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। जिला रोलर स्केटिंग एसोसिएशन पठानकोट की ओर से 13वीं जिला रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप-2026 का आयोजन मिशन रोड स्थित रेहमा इंटरनेशनल स्कूल में किया गया। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न स्कूलों और स्केटिंग क्लबों से पहुंचे खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। खिलाड़ियों ने स्पीड इनलाइन, स्पीड क्वाड, रोलर हॉकी और इनलाइन हॉकी सहित विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी गति, कौशल और तकनीक का प्रदर्शन किया।

अंडर-8 इनलाइन में युवराज सिंह प्रथम, गोस्विक सलारिया द्वितीय और आन्या तृतीय रहे। क्वाड स्किड में जिया ने पहला, सहज ने दूसरा और जसप्रीत ने तीसरा स्थान हासिल किया। अंडर-10 क्वाड में प्रियांशु प्

न्यूज ब्रीफ

'वोट चोरी' के आरोपों के विरोध में कांग्रेस ने उदयपुर में मनाया काला दिवस



भारतेन्दु संवाददाता, केलांग। कथित 'वोट चोरी', चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी व विपक्षी सांसदों के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को उदयपुर ब्लॉक में काला दिवस मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन कर लोकतंत्र, मताधिकार की सुरक्षा और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उठाई प्रदर्शन में लाहौल-स्पीति की विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता अनुराधा राणा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष दोरजे लारजे, ब्लॉक अध्यक्ष अनिल ठाकुर सहित पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए निष्पक्षता और पारदर्शिता जरूरी है। विधायक अनुराधा राणा ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का वोट सर्वोच्च अधिकार है और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर उठने वाले सवालों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान की रक्षा से जुड़े मुद्दों को लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से उठाती रहेगी।

पशु चिकित्सा अधिकारियों की बैठक में एसीपीएस बहाल करने की मांग



भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा अधिकारी संघ की बैठक 7 अक्तूबर को देवसदन में आयोजित हुई। बैठक में जिला सचिव डॉ. रणधीर सिंह ने पशु चिकित्सकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस पर जागरूकता शिविरों के साथ कुत्तों का एंटी-रेबीज टीकाकरण किया गया। वहीं, 4 अक्तूबर को विश्व पशु दिवस पर जिले के चारों उपमंडलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। डॉ. रणधीर सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2022 लागू होने के साथ 3 जनवरी 2022 से सुनिश्चित करियर प्रगति योजना (एसीपीएस) समाप्त कर दी गई, जिससे पशु चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति और वेतन वृद्धि प्रभावित हुई है। संघ ने सरकार को ज्ञापन भेजकर एसीपीएस/टाइम स्केल पुनः बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सकों की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं, जबकि करियर प्रगति के अवसर सीमित हैं। एसीपीएस बहाली से लंबे समय से सेवाएं दे रहे अधिकारियों को उचित करियर और वेतन लाभ मिल सकेंगे।

आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों के लिए 31 अक्तूबर तक करें आवेदन

भारतेन्दु संवाददाता, घुमारवीं। बाल विकास परियोजना घुमारवीं के तहत आंगनबाड़ी केंद्र धारवाड़ा और पट्टा रणौता में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी रंजना शर्मा ने बताया कि पात्र महिला उम्मीदवार 31 अक्तूबर 2026 शाम 5 बजे तक सादे कागज पर आवेदन जमा कर सकती हैं। दस्तावेज सत्यापन, साक्षात्कार और चयन प्रक्रिया 4 नवंबर को सुबह 11 बजे एसडीएम कार्यालय घुमारवीं में होगी। उम्मीदवारों को मूल प्रमाण-पत्रों और सत्यापित प्रतियों सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। इसके लिए अलग से बुलावा पत्र जारी नहीं किया जाएगा। आवेदक की आयु 5 अक्तूबर 2026 को 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के फीडिंग एरिया की स्थायी निवासी हो और उसका नाम परिवार सर्वे रजिस्टर में दर्ज होना जरूरी है। न्यूनतम योग्यता 12वीं पास तथा पारिवारिक वार्षिक आय 50 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

जबली बिजली उपकेंद्र में मरम्मत कार्य के चलते कल बिजली आपूर्ति रहेगी बंद

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। 33 केवी विद्युत उपकेंद्र जबली में आवश्यक रखरखाव और मरम्मत कार्य के चलते 10 अक्तूबर को कई क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी। विद्युत उपमंडल तीन की सहायक अभियंता ई. जिज्ञासा नरयाल ने बताया कि उपकेंद्र के 33 केवी और 11 केवी यार्ड लाइनों का जरूरी रखरखाव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 10 अक्तूबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिलासपुर शहर, नम्होल, एम्स, जुरवाला और जबली सब स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी। इनमें छड़ोल, कोठीपुरा, ऋषिकेश सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। विभाग ने उपभोक्ताओं से निर्धारित अवधि के दौरान सहयोग बनाए रखने की अपील की है। सहायक अभियंता ने बताया कि प्रस्तावित विद्युत शटडाउन मौसम की स्थिति पर निर्भर रहेगा। मौसम अनुकूल नहीं होने की स्थिति में रखरखाव कार्य प्रभावित हो सकता है। उन्होंने उपभोक्ताओं से आवश्यक कार्य पहले ही निपटाने का आग्रह किया।

बाल रंगमंच महोत्सव में 'पिद्दू चिड़डू की कथा' का हुआ सफल मंचन



भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में आयोजित तीन दिवसीय बाल रंगमंच महोत्सव में कुल्लू से जुड़े लेखक किशन श्रीमान की कहानी 'पिद्दू चिड़डू की कथा' पर आधारित नाटक का सफल मंचन किया गया। किकली चैरिटेबल ट्रस्ट और भाषा एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित महोत्सव में संभोटा तिब्बतियन स्कूल, छोटा शिमला के विद्यार्थियों ने नाटक प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों के प्रभावशाली अभिनय, संवाद और मंचन को दर्शकों ने खूब सराहा। कहानीकार किशन श्रीमान ने इसे अपने लिए भावुक और अविस्मरणीय क्षण बताया। उन्होंने कहा कि जिस कहानी को उन्होंने कभी कागज पर शब्दों के माध्यम से रचा था, उसे जीवंत पात्रों और अभिनय के रूप में मंच पर देखना उनके लिए गौरव का विषय है। उन्होंने निर्देशक, कलाकारों, संगीत एवं तकनीकी टीम और आयोजन समिति का आभार जताते हुए कहा कि कहानी जब मंच पर आती है तो वह केवल लेखक की नहीं रहती, बल्कि कलाकारों और दर्शकों की भी हो जाती है।

पुराना कांगड़ा में कल से होगी रामलीला

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। पुराना कांगड़ा में नगरकोट युवा कला केंद्र की ओर से 10 अक्तूबर से रामलीला का मंचन किया जाएगा। करीब 12 दिनों तक चलने वाली रामलीला को लेकर आयोजकों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पिछले कई वर्षों से आयोजित हो रही रामलीला को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। रामलीला निर्देशक अजय बिजला, संजीव बत्रा और सुभाष काला ने बताया कि इस बार युवा कलाकारों में खासा उत्साह है और मंचन में नई तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। प्रभु श्रीराम की भूमिका विवेक कुमार, सीता की प्रणव, लक्ष्मण की पारस और हनुमान की सक्षम निभाएंगे। वहीं रावण की भूमिका अंकुश, मेघनाथ की आशीष बिजला, दशरथ की उमेश कला और अन्य प्रमुख पात्रों की भूमिकाएं भी कलाकार निभाएंगे। आयोजकों ने बताया कि रामलीला के दौरान प्रतिदिन चार प्रश्न पूछे जाएंगे और सही उत्तर देने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। इस आयोजन में स्थानीय लोगों का हर वर्ष भरपूर सहयोग मिलता है।

कंट्रोवर्सी खत्म करवा दो, इस एक लाईन ने और खड़ी कर दी भाजपा में कंट्रोवर्सी

भाजपा प्रभारी के निर्देश पर जब एक लाईन में जबाव दिया भाजपा पदाधिकारी ने तो रह गए सारे सन्न

सुरेंद्र कटोच, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हाल ही में भाजपा प्रभारी श्रीकांत ने हमीरपुर में पुराने कार्यकर्ताओं व पूर्व पदाधिकारियों की बैठक ली, बैठक में कुछ वर्तमान पदाधिकारी भी पहुंच गए।

इस दौरान सभी को अपनी - अपनी बात रखने का हक दिया गया। इस दौरान एक वर्तमान पदाधिकारी ने अपनी बात रखनी चाही, तो प्रभारी ने उन्हें केवल एक लाईन में अपनी बात रखने को कह दिया। उस दौरान उस पदाधिकारी ने जो कहा उसके बाद अब जिला भाजपा में क्रंट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़ती दिखने लगी है। उसने एक लाईन में कहा कि जनाब जिला भाजपा की कंट्रोवर्सी खत्म कर दो। मिली जानकारी के अनुसार उनकी एक लाईन के जबाव में कई सारे प्रश्न उभरते दिखे, लेकिन अब कंट्रोवर्सी सरेआम भी आती दिख रही है। काबिलेगौर है

जिन लोगों के खिलाफ बोलना था उनकी मौजूदगी से घुटे कई भाजपाई

सूत्रों से ये भी पता चला कि बैठक में जिन भाजपाईयों के खिलाफ बोलने का जनून था वह भी वहां मौजूद रहे। इस वजह से कई भाजपाई बैठक के बाहर आकर आपस में ही अपना सियासी खुमार निकालते रहे। उनका कहना था कि होना तो ये चाहिए था कि प्रभारी एक-एक से अकेले बात करते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और कंट्रोवर्सी घटने के बजाय और बढ़ती गई।

आप सुजानपुर में राणा का काम करो या फिर नाहन आ जाओ

इस बैठक के बाद एक ऐसा भी विषय रहा, जो खासा चर्चा में आ गया है। सुजानपुर से एक भाजपा नेता पिछले अर्से से स्वयं को भाजपा के टिकट की दावेदारी करता नजर आ रहा है। उसकी सूचना मिलने पर भाजपा टॉप लीडर ने उसे ये हिदायत दे डाली कि वे टिकट की आस भूलकर या तो पूर्व विधायक राजेंद्र राणा के पक्ष में काम कर लो या फिर वह नाहन में आकर काम करें।

◆हाल ही में भाजपा प्रभारी ने हमीरपुर में पुराने भाजपा कार्यकत्ताओं व पूर्व पदाधिकारियों की ली थी बैठक

कि भाजपा ने अपने प्रदेश के प्रभारियों को पुराने उन कार्यकर्त्ताओं को भी सक्रिय करने की हिदायत दी है। इसी कड़ी में हमीरपुर जिले की बैठक के बाद ये भी निष्कर्ष निकलता दिखा कि जो कंट्रोवर्सी है, अब वो कई गुटों तक एक ऐसे भी हैं, जो समीरपुर छोड़ विजयपुर जा चुके हैं। यही नहीं इनमें एक ऐसा चर्चित कैंप भी है, जो सीधे कथित अमित शाह को रिपोर्ट करता है, अब आगामी विधानसभा चुनावों के मध्यनजर ये कैंप एक दूसरे के लिए आ चुकी है। बतातें चलें कि इन दिनों खासतौर पर जिला भाजपा में ऐसे लोग भी हैं, जो अभी भी समीरपुर कैंप के गिने जाते है। इन्हीं में से खासे सक्रिय माने जा रहे है। इनमें दो कैंप ऐसे हैं, जो समीरपुर को अपनी ओर से सियासी तौर पर काटा मार चुके हैं। वहीं, दूसरे कैंप इस बार समीरपुर लैस भाजपा की जिले की पांचों सीटें जीतने का दावा करता चर्चा में चल रहा है। अब देखना ये है आने वाले विधान सभा चुनावों या फिर संभावित दिसंबर में होने वाले नगर निगम के चुनावों में ये कैंप किस तरह के सियासी गुल खिलाते हैं।

फोरलेन पर 151 .33 ग्राम चिट्टे के साथ पंजाब के तीन तस्कर काबू



अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम (एसडीटी) ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फोरलेन पर 151.33 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने मामले में पंजाब के अमृतसर निवासी तीन युवकों को गिरफ्तार कर तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार भी कब्जे में ली है। जानकारी के अनुसार, एसडीटी बिलासपुर की टीम धराड़सानी फोरलेन पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी।

इसी दौरान पंजाब नंबर की कार को संदेह के आधार पर रोका गया। तलाशी लेने पर कार से 151.33 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जितेंद्र सिंह (40), जोवन जीत सिंह (25) और गुरचंट सिंह (32) के रूप में हुई है। तीनों अमृतसर जिले के न्यू कृपा नगर, नारायणगढ़, स्याटा के निवासी बताए गए हैं। मामले में थाना झंडूता में मुकदमा संख्या 86/2026 दर्ज कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस अब बरामद नशे की खेप के स्रोत और संभावित सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि चिट्टा कहां से लाया गया था और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। बिलासपुर पुलिस ने कहा कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और तस्करी नेटवर्क पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत शिकंजा कसा जाएगा।

नवरात्र पर 11 अक्तूबर को खुला रहेगा कांगड़ा का सराफा बाजार

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। शरदकालीन नवरात्र के अवसर पर ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कांगड़ा का सराफा बाजार रविवार, 11 अक्तूबर को खुला रहेगा। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष लकी मल्होत्रा ने बताया कि नवरात्र के दौरान शुभ मुहूर्त में सोने-चांदी के आभूषणों सहित अन्य वस्तुओं की खरीदारी को लेकर लोगों में विशेष उत्साह रहता है। इसी को देखते हुए रविवार को बाजार खोलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि नवरात्र के शुभ अवसर पर कई लोग नई वस्तुओं और आभूषणों की खरीदारी करते हैं। बाजार खुला रहने से स्थानीय ग्राहकों के साथ आसपास के क्षेत्रों से आने वाले लोगों को भी खरीदारी की सुविधा मिलेगी। सराफा एसोसिएशन ने ग्राहकों से बाजार में खरीदारी के दौरान आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है।

कांग्रेस में अनगिनत गुट, मुख्यमंत्री भाजपा के गुट गिनाते हैं : जयराम



भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू अक्सर भाजपा के अंदर गुट गिनाते रहते हैं, लेकिन खुद अपने भीतर झांककर देख लें कि कांग्रेस में एक नहीं बल्कि अनगिनत गुट पैदा हो चुके हैं। जयराम ने वीरवार को मंडी के इंदिरा मार्केट पार्क में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित सेवा के रंग, राष्ट्र के संग रंगोली कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया। इसके उपरांत भाजपा महिला मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक में भी शिरकत की।

कार्यक्रम के पश्चात मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल और समर्पित सेवाकाल के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस प्रकार के विशेष व प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आज संपूर्ण देशवासी यही हृदय से चाहते हैं कि आगामी 25 वर्षों तक भी नरेंद्र मोदी ही देश का कुशल नेतृत्व करते रहें। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर करारा हमला बोला और कहा कि मुख्यमंत्री को शायद ऐसा लगता है कि वे हॉलीलॉज को डिसलॉज करने में पूरी तरह सफल रहे हैं, लेकिन उनकी यह सोच बिल्कुल सही नहीं है। जिस नेता का हिमाचल प्रदेश के समग्र विकास में विशेष योगदान रहा हो, उन्हें इस प्रकार से भुला देना और उनका निरंतर निरादर करना केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की ही संकीर्ण संस्कृति हो सकती है।

हिमाचल में 14 अक्तूबर तक मौसम खराब



अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 9 से 14 अक्टूबर तक राज्य के कई हिस्सों में मौसम खराब रह सकता है। इस दौरान उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी होने के आसार हैं। इससे पहाड़ों में तापमान और नीचे जाने के साथ ठंड बढ़ेगी। हालांकि राहत की बात यह है कि इस अवधि में कहीं भी भारी बारिश या भारी बर्फबारी की आशंका नहीं है।

मौसम विभाग ने इस अवधि के लिए कोई भारी बारिश या भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी नहीं किया है। वीरवार को शिमला सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिनभर धूप-छांव का दौर जारी रहा। कुछ स्थानों पर हल्की धूप भी खिली। मौसम में आए इस बदलाव का असर खासकर पर्वतीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में महसूस किया जा रहा है। अगले दिनों में ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। इससे राज्य के पर्वतीय इलाकों में ठंड बढ़ेगी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्दी का असर तेज होगा। मौसम विभाग के अनुसार 9 से 13 अक्टूबर के दौरान राज्य में अलग-अलग स्थानों पर बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। 14 अक्टूबर तक भी मौसम पूरी तरह साफ होने के बजाय कुछ हिस्सों में बदलाव बना रह सकता है। मौजूदा पूर्वानुमान में भारी बारिश या भारी बर्फबारी जैसी स्थिति नहीं है। इससे पहले पिछले 24 घंटों के दौरान भी राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। बिलासपुर के मलरान और आरएल बीबीएमबी में सबसे अधिक 30-30 मिलीमीटर बारिश हुई। शिमला जिले के सराहन में 20 मिलीमीटर, सिरमौर के पांवटा साहिब में 10 मिलीमीटर और शिमला के साथ चंबा जिले के सलूणी में 10-10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इन इलाकों में हुई बारिश ने मौसम में ठंडक बढ़ाने का काम किया है।

वीरवार को छह शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के औसत न्यूनतम तापमान में भी 1.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। लाहौल-स्पीति का कुकुमसेरी 2.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ राज्य में सबसे ठंडा रहा।

खेल केवल खिलाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी : डॉ. सुजाता

◆कुल्लू कॉलेज में इंटर कॉलेज बैडमिंटन व शूटिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ

◆दरंग, हरिपुर व कुकुमसेरी कॉलेज ने पिस्टल और राइफल से निशाना लगाया

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में वीरवार को इंटर कॉलेज बैडमिंटन एवं शूटिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में सैंज महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सुजाता ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।

उन्होंने कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि स्वस्थ जीवन और व्यक्तित्व विकास के लिए भी बेहद जरूरी हैं। बैडमिंटन और शूटिंग जैसे खेल एकाग्रता, धैर्य और आत्मविश्वास की सीख देते हैं। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी की स्पोर्ट्स एंड को-करिकुलर एक्टिविटीज काउंसिल के लिए इंटर कॉलेज प्रतियोगिताओं का आयोजन बड़ी जिम्मेदारी है। सीमित संसाधनों के बावजूद सामूहिक प्रयासों से प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया जा रहा है। प्राचार्य डॉ. राकेश राणा ने मुख्यातिथि और प्रतिभागी खिलाड़ियों का कुल्लवी परंपरा के अनुसार स्वागत किया। आयोजन सचिव डॉ. ओम प्रकाश ने बताया कि बैडमिंटन छात्रा वर्ग का पहला मुकाबला कुल्लू और करसोग कॉलेज के बीच हुआ, जिसमें कुल्लू कॉलेज ने जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मंडी कॉलेज और एमएलएसएम सुंदरनगर की टीमों ने भी अपने मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।

वहीं, 10 मीटर पिस्टल और राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में दरंग, हरिपुर और कुकुमसेरी कॉलेज के प्रतिभागियों ने निशानेबाजी में दमखम दिखाया। प्रतियोगिता के दौरान महाविद्यालय के प्राध्यापक, कर्मचारी और आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे।

किसानों-पशुपालकों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता : चंद्र कुमार

दूध के बढ़े दाम से पशुपालकों को मिलेगा आर्थिक लाभ



भारतेन्दु संवाददाता, ज्वाली। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने वीरवार को लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह ज्वाली में लोगों की जनसमस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का प्राथमिकता और समयबद्ध तरीके से समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों, पशुपालकों और गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि किसानों और पशुपालकों के हाथ में पैसा पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ गेहूं, मक्का, जौ और कच्ची हल्दी की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए गाय के दूध का खरीद मूल्य 61 रुपये और भैंस के दूध का 71 रुपये प्रति लीटर किया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के कल्याण के लिए भी कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। 'अपना परिवार सुखी परिवार योजना' के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। पात्र परिवारों को 300 यूनिट बिजली उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के विकास पर उन्होंने कहा कि सड़क, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार करोड़ों रुपये के विकास कार्य करवा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। एसआईआर के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि किसी के मताधिकार का हनन न हो और निर्वाचन प्रक्रिया में लोगों का विश्वास कायम रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसमस्याओं पर समयबद्ध कार्रवाई हो तथा विकास कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरे किए जाएं।

बासा व जोगिंद्रनगर ने जीते खो-खो के खिताब

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। राजकीय महाविद्यालय सराज लंबाथाच में आयोजित एसपीयू इंटर-कॉलेज खो-खो चैंपियनशिप-2026 का तीन दिवसीय आयोजन संपन्न हुआ। समापन समारोह में मुख्यातिथि चेत राम ने विजेता टीमों को ट्रॉफियां और पुरस्कार प्रदान किए। पुरुष वर्ग में राजकीय महाविद्यालय बासा ने प्रथम, वीजीसी मंडी ने द्वितीय तथा राजकीय महाविद्यालय कुल्लू ने तृतीय स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय जोगिंदरनगर प्रथम, एमएलएसएम सुंदरनगर द्वितीय और राजकीय महाविद्यालय कुल्लू तृतीय रहा। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व और टीम भावना विकसित करते हैं। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया। प्राचार्या प्रो. जया कुमारी ने आयोजन की सफलता के लिए सभी सहयोगियों का आभार जताया।

वल्लभ कॉलेज मंडी में मनाया भारतीय वायु सेना दिवस, कैडेट्स ने लिया राष्ट्रसेवा का संकल्प



भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी की एनसीसी वायु सेना विंग की ओर से भारतीय वायु सेना दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य कैडेट्स को वायु सेना के गौरवशाली इतिहास, शौर्य, अनुशासन और राष्ट्रसेवा की परंपरा से परिचित करवाना रहा।

कार्यक्रम के प्रथम सत्र की अध्यक्षता फ्लाइट कमांडर एवं एसोसिएट एनसीसी अधिकारी फ्लाइंग ऑफिसर डॉ. चमन ने की। उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना ने युद्ध के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं, राहत-बचाव और मानवीय सहायता अभियानों में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने वायु सेना के आदर्श वाक्य 'नभः स्पृशं दीप्तम' का उल्लेख करते हुए कैडेट्स से ऊंचे लक्ष्य निर्धारित कर कठिन परिश्रम करने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं को अनुशासन, फिटनेस, सकारात्मक सोच और राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संदेश दिया। दूसरे सत्र की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार ने की। उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ आपदा राहत और मानवीय सहायता में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय के कई एनसीसी कैडेट्स राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस शिविरों तथा अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं। कैडेट्स ने 18,370 फीट ऊंची परांगला सहित विभिन्न चोटियों पर तिरंगा और एनसीसी ध्वज फहराकर महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। सहायक प्रोफेसर योगराज ने नेतृत्व क्षमता के महत्व पर प्रकाश डाला, जबकि गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर धृति शर्मा ने एनसीसी प्रशिक्षण के साथ शैक्षणिक उत्कृष्टता पर जोर दिया। इस अवसर पर भाषण प्रतियोगिता में लीडिंग फ्लाइट कैडेट काजल प्रथम, कैडेट कविता द्वितीय और कैडेट खुशबू जामवाल तृतीय रहीं। चित्र लेखन में लीडिंग फ्लाइट कैडेट आयुषी प्रथम, खुशबू ठाकुर द्वितीय और भावना तृतीय रहीं। कार्यक्रम में एनसीसी एयर विंग व आर्मी विंग के 53 कैडेट्स ने भाग लिया और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा का संकल्प लिया।

नयना देवी में आश्विन नवरात्र मेले को लेकर विभिन्न धाराओं के तहन निषेधाज्ञा आदेश जारी

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। श्री नयना देवी जी में आश्विन नवरात्र मेले के दौरान कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार ने 11 से 20 अक्तूबर तक विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। मेले के दौरान मंदिर परिसर में लाउडस्पीकर, ढोल-नगाड़े, बैंड-बाजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक सार्वजनिक घोषणाएं केवल कंट्रोल रूम के माध्यम से की जाएंगी। मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के प्रसाद के प्रयोग पर भी रोक रहेगी। पुलिस थाना कोट कहलूर के क्षेत्र में अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद और तेजधार हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस बल इस आदेश से बाहर रहेगा। यातायात व्यवस्था के तहत टोबा से श्री नैना देवी मंदिर मार्ग पर केवल बसों और टैक्सियों को आवाजाही की अनुमति होगी। ट्रक, कैंटर, ट्रैक्टर और अन्य भारी वाहनों पर रोक रहेगी। गड़ामोड़ और ग्वालथाई से आगे ऐसे वाहनों में सवार यात्रियों को मंदिर की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने की अपील की है।

मांडी-नंदोल में गैस सिलेंडर की समस्या नियमित सप्लाई वाहन लगाने की मांग



भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। अर्की विधानसभा क्षेत्र के सूरजपुर वार्ड से जिला परिषद सदस्य शशिकांत शर्मा ने ग्राम पंचायत घणागुघाट के मांडी-नंदोल गांवों में लंबे समय से चली आ रही रसोई गैस सिलेंडर की समस्या को लेकर उपमंडलाधिकारी अर्की निशांत तोमर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समाजसेवी डी.डी. शर्मा और दूनी चंद भी मौजूद रहे।

शशिकांत शर्मा ने एसडीएम को बताया कि मांडी और नंदोल गांवों में गैस सिलेंडर पहुंचाने के लिए नियमित वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके चलते ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों को सिलेंडर लेने के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार उन्हें सिलेंडर सिर पर उठाकर लाने-ले जाने पड़ते हैं या वाहन की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त किराया देना पड़ता है। इससे ग्रामीणों का समय और धन दोनों खर्च होते हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि दोनों गांवों में नियमित रूप से रसोई गैस सिलेंडर की गाड़ी भेजने की व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को गांव में ही गैस उपलब्ध हो सके और उन्हें अनावश्यक परेशानी से राहत मिले। इस दौरान शशिकांत शर्मा ने सड़क से संबंधित औपचारिकताएं पूरी होने का प्रमाण देते हुए लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी रोड फिटनेस सर्टिफिकेट भी एसडीएम को सौंपा। एसडीएम निशांत तोमर ने ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उचित समाधान का आश्वासन दिया।

खूबसूरत अंदाज में जेस मार्टिन

जेस मार्टिन एक प्रतिभाशाली खेल महिला हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण से पहचान बनाई है। उनके संघर्ष और उपलब्धियां युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक हैं। खेल के मैदान पर उनका आत्मविश्वास और निरंतर बेहतर प्रदर्शन उन्हें खास बनाता है।



स्पोर्ट्स विंडो

चीन में क्रिकेट को बढ़ावा देगा आईसीसी

एजेंसी, नई दिल्ली। ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किए जाने के बाद चीन की क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) इस देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करेगा। आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता ने कहा कि विश्व संस्था चीन में जल्द ही टियर 2 प्रतियोगिता के आयोजन के लिए राष्ट्रीय संघ का साथ देगा और साथ ही देश में उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस) स्थापित करने में भी मदद करेगा। गुप्ता ने पीटीआई से कहा कि चीन में क्रिकेट को अधिक सुलभ बनाना और महिला क्रिकेट को बढ़ावा देना भी उसकी योजनाओं का हिस्सा है। अगर आईसीसी चीन में अपनी मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब हो जाती है, तो वहां क्रिकेट के लिए अपार संभावनाएं हैं।

टेबल टेनिस : मानुष शाह और मानव ठक्कर चीन स्मैश के सेमीफाइनल में

एजेंसी, बीजिंग। भारत के मानुष शाह और मानव ठक्कर ने गुरुवार को डब्ल्यूटीटी चीन स्मैश 2026 के पुरुष युगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में चीन के लियांग जिंगकुन और शियांग पेंग को सीधे गेमों में 3-0 से हराया। दूसरी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने 19 मिनट तक चले मुकाबले में 11-9, 11-5, 11-4 से जीत दर्ज की। मानुष और मानव ने मुकाबले के आगे बढ़ने के साथ अपना दबदबा बढ़ाया और लगातार तीन गेम जीतकर अंतिम चार में जगह बनाई। अब सेमीफाइनल में उनका सामना स्वीडन के एंटोन कालबर्ग और क्रिस्टियन कार्लसन तथा दक्षिण कोरिया के लिम जोंगहून और ओ जुनसोंग की जोड़ी के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा। मानुष शाह वीरवार को मिश्रित युगल सेमीफाइनल में भी उतरेंगे। वह दिया चिताले के साथ मिलकर चीनी ताइपे की लिन युन-जू और चेंग आई-चिंग की जोड़ी का सामना करेंगे।

धनंजय डिसिल्वा ने तुरंत प्रभाव से छोड़ी श्रीलंका टेस्ट टीम की कप्तानी

एजेंसी, कोलंबो। श्रीलंका के टेस्ट कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने तुरंत प्रभाव से कप्तानी से इस्तीफा देते हुए कहा है कि अब अगली पीढ़ी को बागडोर सौंपने का समय आ गया है। अपने कैरियर में 69 टेस्ट खेलकर 13 शतक समेत 4400 से अधिक रन बनाने वाले 35 वर्ष के धनंजय बतौर खिलाड़ी चयन के लिये उपलब्ध रहेंगे। जनवरी 2024 में टेस्ट कप्तान बने डिसिल्वा ने श्रीलंका क्रिकेट चयन समिति को अपने फैसले से अवगत करा दिया है। उन्होंने चयन समिति को लिखे पत्र में कहा , 'मेरा मानना है कि अब बागडोर अगली पीढी को सौंपी जानी चाहिए।' श्रीलंका क्रिकेट के सीईओ एशले डिसिल्वा ने क्रिकेट के पारंपरिक प्रारूप में योगदान के लिये धनंजय को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा , 'श्रीलंका क्रिकेट उन्हें भविष्य के लिये शुभकामना देता है और बतौर कप्तान योगदान के लिये धन्यवाद भी।'



जोबर्ग सुपर किंग्स ने जेसन रोल्स सहित छह खिलाड़ियों को खरीदा

एजेंसी, जोहानिसबर्ग। जोबर्ग सुपर किंग्स ने एसए20 कि अगले साल होने वाले टूर्नामेंट के लिए नीलामी में दक्षिण अफ्रीका के युवा ऑलराउंडर जेसन रोल्स सहित छह खिलाड़ियों को अपनी टीम से जोड़ा। इस फ्रेंचाइजी ने रोल्स को 29 लाख रैंड (1.69 करोड़ रुपये) में खरीदा।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज

संजू सैमसन के खेलने पर संशय, सूर्यवंशी को मिल सकता है मौका

एजेंसी, रांची

संजू सैमसन को छोड़कर भारत के सभी बल्लेबाज फॉर्म में हैं और इसलिए टीम प्रबंधन शुक्रवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ को यहां होने वाले दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज करने के लिए भेज सकता है। भारतीय टीम यहां जीत हासिल करने पर पांच मैचों की शृंखला में 2-0 की बढ़त बना लेगी, लेकिन उसके लिए सैमसन का खराब प्रदर्शन चिंता का विषय बना हुआ है।

सैमसन पिछली चार पारियों में केवल 29 रन बना पाए हैं जिनमें उनका उच्चतम स्कोर 11 है। उनकी असफलता के कारण भारत को इन मैच में अच्छी शुरुआत नहीं मिल पाई। लेकिन पिछले मैच में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला शतक लगाने



वाले कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में मध्य क्रम ने सैमसन की असफलता का टीम पर खास असर नहीं पड़ने दिया। अय्यर ने अपने करियर के 68वें मैच में अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा।

ऐसे में सूर्यवंशी को एक और मौका मिल सकता है जिन्होंने अब तक मिले अवसरों पर यह साबित कर दिया कि वह खेल के छोटे प्रारूप के लिए उपयुक्त बल्लेबाज हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज के पास कई तरह के शॉट हैं और वह अपने आक्रामक अंदाज से विपक्षी टीम को शुरू में ही दबाव में ला सकते हैं। भारतीय टीम प्रबंधन ने हालांकि इस 15 वर्षीय बल्लेबाज को मौका देने के बजाय अब तक अभिषेक और सैमसन की स्थापित सलामी जोड़ी का ही समर्थन किया है। जापान में एशियाई खेलों में सूर्यवंशी और अभिषेक ने ही पारी का आगाज किया था और सैमसन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे।

संभावित टीमें

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, ईशान किशन, नमन धीर, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, मयंक यादव।

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेज़, मैथ्यू फोर्ड, शिमरोन हेटमायर, अकील हुसैन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोटी, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर।

पैरा एशियाई खेलों की चयन प्रक्रिया में शूटरों ने भ्रष्टाचार का लगाया आरोप

एजेंसी, नई दिल्ली

पैरा एशियाई खेलों के लिए चयन प्रक्रिया में कथित वित्तीय भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और हेरफेर के आरोपों के बीच पैरा-शूटरों ने तत्काल स्वतंत्र जांच की मांग की है। वहीं, भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि टीम का चयन पूरी तरह योग्यता के आधार पर किया गया।

भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के महानिदेशक को बुधवार को सौंपे गए एक पत्र में निशानेबाजों ने आरोप लगाया कि 18 से 24 अक्टूबर तक होने वाले आइची-नागोया पैरा एशियाई खेलों के लिए चयन में भारतीय पैरालंपिक समिति के अधिकारियों और उसकी शूटिंग टेक्निकल कमेटी (एसटीसी) ने 'अवैध तरीके से धन की वसूली', 'खुलेआम भ्रष्टाचार' और खेल मंत्रालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।

◆ भारतीय पैरालंपिक समिति ने आरोपों को किया खारिज

पत्र में आरोप लगाया गया कि खिलाड़ियों पर चयन की शर्त के तौर पर सरकार से मिलने वाली नकद पुरस्कार राशि में से 20 प्रतिशत कमीशन देने का दबाव बनाया जा रहा था। इसमें अधिकारियों पर कुछ निशानेबाजों को फायदा पहुंचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय कोटा और क्वालीफाइंग स्कोर में हेरफेर करने का भी आरोप लगाया गया है। एशिया में तीसरे नंबर के पी4 50मीटर फ्री पिस्टल एसएच1 शूटर संदीप कुमार ने चयन प्रक्रिया में भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि एशिया में 14वें नंबर पर मौजूद रुद्राक्ष खंडेलवाल को एशियाई नंबर 1 आकाश और खुद उनसे पहले चुना गया। पीसीआई अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी है और पूरी तरह निर्धारित मानदंडों के आधार पर की गई है।

दो बार पैरालंपिक खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीत चुके झाझरिया ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, 'चयन निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। चयन 100 प्रतिशत निष्पक्ष है और खेल मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।' खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा कि पैरा-शूटरों की वास्तविक शिकायतों का समाधान किया जाएगा, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि पैरा एशियाई खेलों के लिए टीम के चयन को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है और इस समय इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता।

इस बीच, निशानेबाजों ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपों का समाधान नहीं किया गया तो वे न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत परमादेश जारी करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय का रुख करने पर विचार करेंगे।

आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स के दो कोच ने पद से दिया इस्तीफा

एजेंसी, नई दिल्ली

आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स के फील्डिंग कोच ब्रैड हैडिन और तेज गेंदबाजी कोच जेम्स होप्स ने टीम छोड़ दी है। दोनों ने हाल ही में फ्रेंचाइजी को इसकी जानकारी दी। हैडिन और होप्स के बिग बैश लीग (बीबीएल) से जुड़ सकते हैं। अब आईपीएल 2027 से पहले टीम को 3 कोच की जरूरत है। क्योंकि, साईराज बहुतुले ने पहले ही टीम छोड़ दी है। वे टीम इंडिया के स्पिन बॉलिंग कोच बने हैं। पंजाब की टीम पिछले आईपीएल में 5वें स्थान पर रही थी। उसने लखनऊ के खिलाफ अपना आखिरी मैच जीता। लेकिन, यह जीत प्लेऑफ में पहुंचने के लिए काफी नहीं थी। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर ब्रैड हैडिन पंजाब किंग्स के फील्डिंग कोच थे। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेम्स होप्स पोंटिंग के कार्यकाल में टीम के बॉलिंग कोच बने थे।



◆ फील्डिंग कोच हैडिन और तेज बॉलिंग कोच होप्स ने छोड़ी टीम

रिकी पोंटिंग चुनेंगे नया कोचिंग स्टाफ

क्रिकबज के अनुसार पंजाब किंग्स मैनेजमेंट नए कोचों की तलाश शुरू कर चुका है। नए स्टाफ पर फैसला रिकी पोंटिंग करेंगे। मैनेजमेंट कुछ नाम सुझा सकता है। उम्मीदवारों से बातचीत और इंटरव्यू पोंटिंग के उनसे बात करने के बाद होंगे। एक सूत्र ने कहा, 'हेड कोच ही फैसला करेंगे।' पोंटिंग ने इस बारे में पूछे गए सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया।

मोनांक के शतक से अमेरिका ने आईसीसी लीग का खिताब जीता

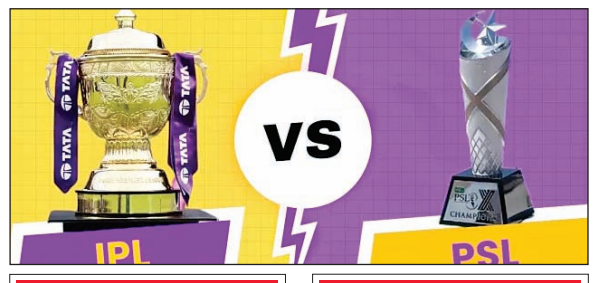
एजेंसी, डलास। कप्तान मोनांक पटेल के शानदार शतक की मदद से अमेरिका ने नामीबिया को चार विकेट से हराकर आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का खिताब जीता। ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम में मोनांक पटेल ने 108 रन बनाए जिससे अमेरिका ने नामीबिया के नौ विकेट पर 298 रन के बड़े स्कोर को बौना साबित करते हुए सात गेंद शेष रहते जीत हासिल की। मोनांक पटेल के अलावा स्मित पटेल ने तेज 50 रन और शेहान जयसूर्या ने 74 रन का योगदान दिया। नामीबिया की तरफ से कप्तान गेरहार्ड इरास्मस (76) ने सर्वाधिक रन बनाए। अमेरिका ने इस जीत से दो और अंक हासिल किए जिससे उसकी शीर्ष पर जगह पक्की हो गई। अमेरिका ने वनडे विश्व कप क्वालीफायर में अपनी जगह पहले ही पक्की कर ली है, जहां वह अगले साल दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले विश्व कप में जगह बनाने की कोशिश करेगा।

आईपीएल से फिर टकरा सकती है पीएसएल

18 मार्च से 2 मई तक होगी पाकिस्तानी लीग, 8 टीमें लेंगी भाग

एजेंसी, नई दिल्ली

भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट लीग की डेट एक बार फिर टकरा सकती हैं। पीसीएल ने वीरवार को अपनी लीग पीसीएल-12 का शेड्यूल जारी किया। पाकिस्तान क्रिकेट लीग की शुरुआत 18 मार्च से होगी। जबकि, फाइनल मैच 2 मई को खेला जाएगा। इसी बीच इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) भी शुरू हो सकता है। हालांकि, बीसीसीआई ने अब तक इसका शेड्यूल जारी नहीं किया है। एक सितंबर को लंदन में पीएसएल संचालन परिषद की बैठक में कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें सभी आठ फ्रेंचाइजी के मालिकों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पीएसएल के 11वें सीजन में पहली बार 8 टीमों का फॉर्मेट लागू किया गया था। इसी सीजन में खिलाड़ियों के चयन के लिए ड्राफ्ट सिस्टम की जगह पहली बार प्लेयर ऑक्शन कराया गया। पीएसएल11 के फाइनल में पेशावर जल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को हराकर 9



आईपीएल से क्यों हो सकता है टकराव?

पीएसएल की विंडो मार्च से मई के बीच है, जबकि आईपीएल भी आमतौर पर इसी अवधि में खेला जाता है। 2026 में भारतीय लीग 28 मार्च से शुरू होकर 31 मई तक चली थी। पीएसएल12 की 18 मार्च से 2 मई की विंडो आईपीएल के शुरुआती और लीग स्टेज के हिस्से से टकरा सकती है।

पीएसएल का स्तर ऊंचा करेंगे : मोहसिन नकवी

चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि पीएसएल-11 ने दिखाया कि यह लीग क्या करने में सक्षम है। उन्होंने रोमांचक मुकाबलों, रिकॉर्ड दर्शकों और रिकॉर्ड प्रसारण आंकड़ों का जिक्र किया। नकवी ने कहा- पीएसएल 12 में लीग का स्तर और ऊंचा किया जाएगा। बोर्ड एक और शानदार सीजन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी फ्रेंचाइजियों को एक बार फिर खिताब के लिए कॉम्पीट करते देखने का इंतजार है।

8 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर भारत

जीएसटी, आईबीसी और डिजिटलीकरण से बदली भारत की आर्थिक तस्वीर

एजेंसी, मुंबई

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक निवेशकों का भरोसा लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। वैश्विक निवेश फर्म केकेआर की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था अगले एक दशक में दोगुनी होकर 8 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान किए गए संरचनात्मक सुधार, बुनियादी ढांचे में लगातार बढ़ता निवेश और अर्थव्यवस्था का तेजी से औपचारिककरण विकास की क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ ही भारत वैश्विक निवेशकों के लिए एक बड़े और आकर्षक बाजार के रूप में उभर रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत पहले ही करीब 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का आकार हासिल कर चुका है और मौजूदा आर्थिक गति बनी रही तो अगले 10 वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था का आकार फिर से दोगुना करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है।

केकेआर ने अपनी रिपोर्ट में भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल बताया है, जहां लंबे समय तक लगातार लागू किए गए आर्थिक सुधारों का प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। रिपोर्ट का आकलन है कि किसी अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव केवल कुछ तिमाहियों में नहीं आते, बल्कि लगातार कई वर्षों तक किए गए नीतिगत और संरचनात्मक प्रयासों का परिणाम होते हैं।

दोगुनी होगी अर्थव्यवस्था

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत पहले ही करीब 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का आकार हासिल कर चुका है और मौजूदा आर्थिक गति बनी रही तो अगले 10 वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था का आकार फिर से दोगुना करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है।



बुनियादी सुविधाओं से विकास को रफ्तार

बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली और डिजिटल संपर्क जैसी सुविधाओं पर लगातार निवेश किया जा रहा है। बेहतर आधारभूत ढांचा उत्पादन, परिवहन और व्यापार की लागत कम करने के साथ आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत जैसे बड़े देश में इसका प्रभाव रोजगार, उद्योग, सेवा क्षेत्र और घरेलू मांग पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि वैश्विक निवेशक भारत की दीर्घकालिक विकास क्षमता को लेकर उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 8 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान कई आर्थिक और वैश्विक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

जीएसटी ने आसान किया कर ढांचा

भारत के मामले में भी यही देखने को मिल रहा है। वर्ष 2014 के बाद लागू किए गए कई प्रमुख आर्थिक सुधारों ने अर्थव्यवस्था की बुनियाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें वस्तु एवं सेवा कर, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, श्रम बाजार का औपचारिकीकरण, डिजिटल व्यवस्था का विस्तार और बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश प्रमुख हैं। जीएसटी ने देश में अलग-अलग अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थाओं को एक साझा ढांचे में लाने का काम किया।

एयर इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए पेश किया 'ईजीरोम' सिम

एजेंसी, मुंबई

एयर इंडिया और टाटा कम्युनिकेशंस ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की मोबाइल कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए एयर इंडिया ब्रांडेड ट्रैवल सिम 'ईजीरोम' पेश किया है। यह सेवा यात्रियों को विदेश यात्रा के दौरान वॉयस और डेटा सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। ग्राहक इसे एयर इंडिया के विशेष वेबपेज से भौतिक सिम और ई-सिम, दोनों रूपों में खरीद सकते हैं। शुरुआती चरण में सिम नि:शुल्क दिया जा रहा है, जबकि रोमिंग पैक के लिए शुल्क देना होगा। ये पैक उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, एशिया प्रशांत और पश्चिम एशिया के 30 देशों में उपलब्ध हैं और इनकी शुरुआती कीमत 241 रुपये, कर अलग से, रखी गई है। यात्रियों को अपनी जरूरत के अनुसार केवल डेटा अथवा वॉयस और डेटा दोनों वाले प्लान चुनने की सुविधा मिलेगी। डेटा प्लान लेने वाले ग्राहकों को एक जीबी तक अतिरिक्त मुफ्त डेटा भी दिया जाएगा। कंपनी ने भविष्य में इसकी पहुंच 190 देशों तक बढ़ाने की योजना बनाई है।



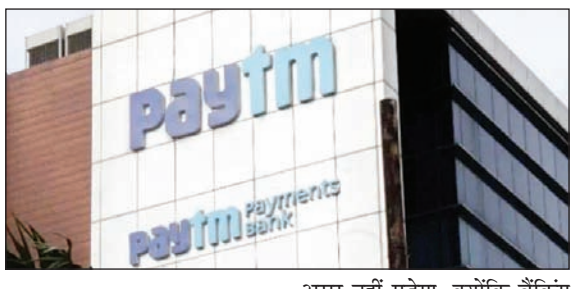
एयर इंडिया और टाटा कम्युनिकेशंस के अनुसार, यात्री यात्रा शुरू होने से पहले ही अपना मोबाइल प्लान चुनकर सक्रिय कर सकेंगे और विदेश पहुंचते ही इंटरनेट से जुड़ सकेंगे। टाटा कम्युनिकेशंस की 600 से अधिक मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों के साथ साझेदारी से बेहतर अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का दावा किया गया है।

आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंकों की सूची से हटाया

एजेंसी, नई दिल्ली

भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ एक और सख्त प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उसे आधिकारिक तौर पर 'शेड्यूल बैंक' यानी अनुसूचित बैंक की सूची से बाहर कर दिया है। केंद्रीय बैंक की अधिसूचना के अनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 'भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934' की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है। यह कार्रवाई बैंक के खिलाफ चल रही व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है।

आरबीआई के अनुसार, बैंक का संचालन उसके जमाकर्ताओं और वित्तीय संस्थान के हितों के खिलाफ पाया गया था। इसी के चलते मार्च 2022 में नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद 2024 की शुरुआत में



◆ लाइसेंस रद्द होने के बाद बाहर हुआ पेटीएम बैंक

खातों, वॉलेट और फास्टैग में नए डिपॉजिट तथा टॉप-अप पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था।

लगातार नियमों के उल्लंघन और चेतावनियों के बावजूद सुधार न होने पर आरबीआई ने यह कठोर कदम उठाया। नए आदेश से आम ग्राहकों की दैनिक वित्तीय गतिविधियों पर कोई अतिरिक्त असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंकिंग सेवाओं पर पहले ही प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। पुराने खातों और वॉलेट में मौजूद राशि को निर्धारित नियमों के तहत निकाला जा सकता है, लेकिन अब नई राशि जमा या ट्रांसफर नहीं की जा सकती। विजय शेखर शर्मा द्वारा प्रमोटेड इस संस्थान का अनुसूचित बैंक की सूची से बाहर होना उसकी पैतृक कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है।

सरकार ने खारिज किए मस्क के आरोप

एजेंसी, नई दिल्ली। भारत सरकार ने एलन मस्क के उन आरोपों को खारिज कर दिया है, जिनमें उन्होंने दावा किया था कि कुछ भारतीय उद्योगपति अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए स्टारलिंक को भारत में आने से रोक रहे हैं। सरकार ने 8 अक्टूबर को कहा कि देश में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं के लिए निर्धारित नियम सभी कंपनियों के लिए समान हैं। नियम किसी कंपनी के साथ भेदभाव करने के उद्देश्य से लागू नहीं किए जा रहे हैं। इससे पहले बुधवार को एलन मस्क ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया था कि भारत के कुछ बड़े कारोबारी नहीं चाहते कि स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देश में आए, ताकि उनका एकछत्र राज बना रहे। मस्क ने किसी कंपनी या उद्योगपति का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान के बाद भारतीय दूरसंचार कंपनियों के बीच बहस तेज हो गई।

शेयर मार्केट बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल की तेजी ने बढ़ाई चिंता, लगातार नौवें हफ्ते बाजार लाल

सेंसेक्स 1045 अंक टूटा, निफ्टी भी 371 अंक गिरा

एजेंसी, मुंबई

शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला लगातार नौवें हफ्ते भी जारी रहा। 8 अक्टूबर को सेंसेक्स 1,045 अंक टूटकर 71,593 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 371 अंक की गिरावट दर्ज की गई और यह 22,232 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में मेटल, ऑटो और रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। विशेषज्ञों के अनुसार कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और वैश्विक बाजारों में बढ़ते दबाव का भारतीय शेयर बाजार पर नकारात्मक असर पड़ा है।

बाजार में गिरावट की एक बड़ी वजह रिजर्व बैंक की ब्याज दरों को लेकर बदलती नीति भी मानी जा रही है। करीब चार साल में पहली बार दरों में बढ़ोतरी के साथ आरबीआई ने अपना रुख 'न्यूट्रल' से बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' कर दिया है। इससे आने वाले महीनों में ब्याज दरों में एक प्रतिशत तक बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। ब्याज दरें बढ़ने की संभावना से निवेशकों की चिंता बढ़ी है।



वैश्विक स्तर पर बॉन्ड यील्ड में तेज बढ़ोतरी भी शेयर बाजार पर दबाव बना रही है। अमेरिका की 30 साल की बॉन्ड यील्ड 5.71 प्रतिशत के पार पहुंच गई है, जबकि 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी 5.3 प्रतिशत से ऊपर चली गई है। बॉन्ड यील्ड बढ़ने पर निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर डेट मार्केट की ओर रुख करते हैं।

मध्य पूर्व में तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर बढ़ते हमलों के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमत 2 प्रतिशत बढ़कर 102 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। सप्लाई बाधित होने की आशंका और क्रूड इन्वेंट्री में 32 लाख बैरल की कमी से भी कीमतों को समर्थन मिला है। महंगा कच्चा तेल भारत जैसे बड़े आयातक देश के लिए चिंता बढ़ाता है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने भी बाजार की मुश्किलें बढ़ाई हैं।

निवेशकों की चिंता बढ़ी

बुधवार को विदेशी निवेशकों ने 6,121 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। पिछले नौ कारोबारी सत्रों में उनकी बिकवाली करीब 57,000 करोड़ रुपये रही है। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी के जरिए बाजार को संभालने की कोशिश की। बीते सात दिनों में डीआईआई ने 14,867 करोड़ रुपये की खरीदारी की, जबकि एफआईआई ने 13,782 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। तकनीकी स्तर पर भी बाजार को झटका लगा है। निफ्टी ने 22,500 के प्रमुख सपोर्ट स्तर को तोड़ दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार अब 22,300 और फिर 52 सप्ताह के निचले स्तर 22,180 तक जाने की आशंका बनी हुई है।